चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

www.chauthiduniya.com

भूमिहीन ग़रीबों का सत्याग्रह

सियासी दुनिया पेज 3

नोएडा: बिखर गया आईटी हब बनने का सपना

सियासी दुनिया पेज 5

माओवादियों का एक मोहरा भर है छत्रधर

अपनी दुनिया पेज 7

पाकिस्तान में कौन सुरक्षित है?

बाक़ी दुनिया पेज 11

मूल्य 5 रुपये

दिल्ली, 19–25 अक्टूबर 2009

श्री कृष्ण के नाम पर धोखाधड़ी

फोटो– *पीटीआई*

इस्कॉन की राष्ट्र–विरोधी हरकत

सोचिए ज़रा. देश में फैली ग़रीबी के नाम पर इस्कॉन ने कितना शर्मनाक जाल विदेशों में फैला रखा है. विश्व के सभी विकसित देशों, ख़ासकर अमेरिका में इस्कॉन बेंगलुरू ने अपनी संस्था अक्षय पात्र की ओर से बड़े– बड़े होर्डिंग और बैनर लगा रखे हैं. जिन पर भारतीय बच्चों की बेहद फटेहाल और भूख से बेहाल तस्वीरें लगाई गई हैं. तस्वीर में बच्चों के गंदे शरीर पर मक्खियां भिनभिना रही हैं. वे नंगे हैं. रो रहे हैं. गंदगी और कूड़े के बीच बैठे हैं.

ग़रीबों की तस्वीर दिखा जुटा रहे हैं धन

रूबी अरुण

इस्कॉन बेंगलुरू के अध्यक्ष मधु पंडित दास को किसका संरक्षण प्राप्त है? आख़िर कौन–सी वो राजनीतिक हस्तियां हैं जिनकी शह पर मधु पंडित दास का साम्राज्य न सिर्फ़ कर्नाटक और देश के दूसरे हिस्सों में बल्कि विदेशों में भी फल–फूल रहा है. ख़ासकर उन प्रदेशों में जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन था, या है. भाजपा के कद्दावर नेता अनंत कुमार से उनके मधुर रिश्ते तो जगज़ाहिर हैं ही, पर उनके अलावा कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा, मधु पंडित दास पर इतने मेहरबान क्यों हैं? क्यों कर्नाटक की सरकार विपक्षी कांग्रेस के विरोध और आरोप–प्रत्यारोप के बावजूद बेशक़ीमती सरकारी ज़मीन इस्कॉन बेंगलुरू को औने–पौने दामों में दे देती है, वह भी व्यवसायिक इस्तेमाल के लिए? इस्कॉन बेंगलुरू के तमाम संशयात्मक कामों के बाद भी मुख्यमंत्री येदियुरप्पा क्यों नहीं करा रहे हैं उस पर लगे इल्ज़ामों की छानबीन? मधु पंडित दास पर राष्ट्र की गरिमा से खिलवाड़ करने के गंभीर आरोप हैं फिर भी प्रदेश की भाजपा सरकार इस्कॉन बेंगलुरू के कारनामों से नज़र फिराए बैठी है. जबकि भाजपा हमेशा राष्ट्रीयता का ही राग आलापती है. भाजपा सरकार की यह कैसी देशभक्ति है कि भूख और ग़रीबी के नाम पर व्यापार करने वाली संस्था की ग़ैर–वाजिब हरकतों को तो नज़रअंदाज़ कर ही दिया जाता है, बल्कि उसके धार्मिक समारोहों में मुख्यमंत्री येदियुरप्पा अपनी पूरी कैबिनेट के साथ बड़ी शान के साथ शामिल होते हैं. मुख्य अतिथि के पद को सुशोभित करते हैं और संस्था का मान बढ़ाते हैं. वैसे दलील ये भी दी जा सकती है कि शायद मुख्यमंत्री ने यह काम उड़िया समाज के मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए किया हो. पर तथ्य यह नहीं है. बेंगलुरू की कुल आबादी का महज़ 2 प्रतिशत अंश ही उड़िया समाज के ज़िम्मे जाता है. तो ज़ाहिर है मुख्यमंत्री की ये शिरकत मतदाताओं को लुभाने की बजाय आपसी घनिष्ठ संबंधों के लिहाज़ से ही थी. पिछले साल जब मुख्यमंत्री येदियुरप्पा बेंगलुरू में मधु पंडित दास द्वारा आयोजित जगन्नाथ रथ यात्रा में अपने दल–बल के साथ शामिल हुए थे, तब मधु पंडित दास ने एक प्रेस नोट जारी कर इस बात की मुनादी की थी कि उनके मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज़ नेताओं से बेहद सौहार्दपूर्ण रिश्ते हैं और इसी कारण मुख्यमंत्री की उन पर कृपा है.

सोचिए ज़रा. देश में फैली ग़रीबी के नाम पर इस्कॉन ने कितना शर्मनाक जाल विदेशों में फैला रखा है. विश्व के सभी विकसित देशों, ख़ासकर अमेरिका में इस्कॉन बेंगलुरू ने अपनी संस्था अक्षय पात्र की ओर से बड़े– बड़े होर्डिंग और बैनर लगा रखे हैं, जिन पर भारतीय बच्चों की बेहद फटेहाल और भूख से बेहाल तस्वीरें लगाई गई हैं. तस्वीर में बच्चों के गंदे शरीर पर मक्खियां भिनभिना रही हैं. वे नंगे हैं. रो रहे हैं. गंदगी और कूड़े के बीच बैठे हैं. कुल मिला कर ये तस्वीरें देखने वालों के मन पर बड़ा ही मार्मिक असर छोड़ती हैं. विदेशी इन तस्वीरों को देखते हैं और भारतीयों की ज़लालत भरी ज़िंदगी पर लानतें भेजते हैं, तरस खाते हैं. नतीज़ा होता है कि अक्षय पात्र के एजेंट बड़ी आसानी से इन तस्वीरों के ज़रिए विदेशियों की जेब से भारी–भरकम रक़म निकलवाने में कामयाब हो जाते हैं. सबसे बड़ी बात ये कि संस्था के प्रतिनिधि इस बात का ज़िक्र तक नहीं करते कि भारत सरकार इन बच्चों का पेट भरने के नाम पर कितना कुछ कर रही है. मिड डे मील के नाम पर कितनी बड़ी सरकारी मदद दी जाती है. संस्था को भी इस काम के लिए भारी–भरकम अनुदान दिया जाता है. और ज़ाहिर ये किया जाता है कि सरकार निकम्मी और लाचार है जो कुछ कर ही नहीं सकती. प्रदेश सरकार को विपक्षी पार्टियों ने इन सभी बातों का प्रमाण तक सौंप रखा है. उसे सारी बातों की ख़बर है. पर सरकार चुप है. ऐसे शर्मनाक कामों के बाद भी राज्य सरकार ने अक्षय पात्र को मिड डे मील के नाम पर दिया जाने वाला सरकारी अनुदान रोका नहीं है. उसे जारी रखा है. प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डी के शिव कुमार कहते हैं कि प्रदेश भाजपा सरकार की नीयत में ही खोट है. वह चाहती ही नहीं कि मधु पंडित दास के कारनामों का ख़ुलासा हो. चूंकि भाजपा की राजनीति धर्म की ठेकेदारी पर ही टिकी है. इसलिए वह इस्कॉन के ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई कर ही नहीं सकती. क्योंकि उसे अपने वोट बैंक के खिसकने का डर है. यही वजह है कि प्रदेश भाजपा नेताओं के साथ–साथ भाजपा के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के संबंध भी मधु पंडित दास के साथ इतने ही प्रगाढ़ हैं. लिहाज़ा भगवान कृष्ण के नाम पर धड़ल्ले से मुनाफ़ाखोरी और धोखाधड़ी जारी है.

पर सवाल यह भी है कि इतने गंभीर मसले पर अगर राज्य कुछ नहीं कर रही तो केंद्र सरकार ने चुप्पी क्यों लगा रखी है? ज़िम्मेदारी तो भारत सरकार की भी बनती है? क्योंकि इस्कॉन से कांग्रेस के बड़े–बड़े नेताओं के ख़ास रिश्ते हैं. इस्कॉन का हमेशा से ये दावा रहा है कि कांग्रेस से जुड़े पूंजीपतियों का उसे हमेशा साथ मिला है.

वैसे इस मामले में प्रदेश कांग्रेस ने कर्नाटक विधान सभा में ख़ूब बावेला ज़रूर मचाया. तब कर्नाटक के क़ानून मंत्री एस सुरेश कुमार ने यह आश्वासन दिया कि इस्कॉन बेंगलुरू द्वारा विदेशों में भारत का ग़रीब राष्ट्र के रूप में चित्रण

(शेष पृष्ठ 2 पर)

चौथी दुनिया के पास जो तथ्य मौजूद हैं उनसे यह बात साफ़ है कि बेंगलुरू इस्कॉन धर्म के नाम पर , भगवान कृष्ण के नाम पर या समाजसेवा के नाम पर जो कुछ भी कर रहा है वह बेदाग़ नहीं हैं. प्रमाण इस बात के भी हैं कि मधु पंडित दास को जो ज़मीन राज्य सरकार ने धर्मार्थ मुहैया कराई है उसके पीछे किन दिग्गज़ों का हाथ है. क्योंकि कनकपुरा रोड पर जो 650 फ्लैट और दुकानें बनाई और बेची जा रही हैं उनमें राजनीतिक हस्तियों के रिश्तेदारों की भी हिस्सेदारी है.

इस्पात और खान मंत्रालय के बाबू अपने स्वार्थों को लेकर अड़े हुए हैं. जिससे माइन्स एक्ट में संशोधन का महत्वपूर्ण भी मामला अटका हुआ है.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

बाबूगिरी से बढ़ी मुश्किलें

पिछले कुछ समय से इस्पात और खान मंत्रालय में छत्तीस का आंकड़ा बना हुआ है. वजह है, माइन्स एंड मिनरल्स सांइटिफिक डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट में संशोधन. जबकि इसके पूर्ववर्ती अधिकारी खदानों से निकासी संबंधी अधिकार ख़ुद रखना चाहते हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि खान मंत्रालय ने इस्पात संयंत्रों को स्थापित करने में अपना काफी हिस्सा निवेश किया है. खान मंत्रालय के बाबुओं का मानना है कि देश में खनिज पदार्थों के इतने अधिक स्रोत हैं कि आम लोगों के उपयोग से किसी तरह की समस्या नहीं आने वाली है.

इसी मसले से जुड़ी दूसरी सबसे बड़ी बात है, लौह अयस्कों के नीलामी की. जिस पर इस्पात और खान मंत्रालय में आपसी सहमति नहीं बन पा रही है. इस्पात मंत्रालय नीलामी से संबंधित नीतियों पर रोक चाहता है, साथ ही इसने यह भी सुझाव दिया है कि दूसरी औद्योगिक इकाइयों की जगह घरेलू औद्योगिक इकाइयों को अधिक प्राथमिकता दिया जाना चाहिए. लेकिन, सूत्रों की मानें तो खान मंत्रालय के बाबुओं को यह विचार कतई पसंद नहीं है. खान मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव एस विजय कुमार इस बात पर ज़ोर देते हैं कि उनका मंत्रालय ग़ैर–कोयला और ग़ैर–आण्विक खनिजों के बीच अपने किरदार को लेकर एक दूरी बनाकर रखना चाहेगा. सूत्र कहते हैं कि इन विस्तृत रिपोर्ट के अलावा, दरअसल, दोनों मंत्रालय के बाबू, राज्यों द्वारा संचालित कंपनियों के हितों की रक्षा में लगे हुए हैं. हालांकि, दोनों मंत्रालयों में समझौते की कोशिशें चल रही हैं, लेकिन यह जितना लंबा खिंचेगा, उतना ही माइन्स ऐक्ट में किसी भी तरह के संशोधन दूर की कौड़ी ही साबित होगा.

मोदी रहेंगे बाख़बर

मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यालय अब सिर्फ़ गुजरात के मौसम की ही ख़बर नहीं रखेगा. गुजरात सरकार के बाबू इस बात से बेहद चिंतित हैं कि मुख्यमंत्री जी अब उनके काम का निरीक्षण ऑनलाइन करेंगे. फ़िलहाल, मुख्यमंत्री कार्यालय राज्य के सभी ज़िलों के डिस्ट्रिक्ट–इंचार्ज, सुपर–इंचार्ज और दूसरे बाबुओं की निगरानी प्रत्यक्ष तौर पर करता है. ताकि सभी बाबू अपनी ज़िम्मेदारियों को बख़ूबी निभाएं.

सूत्रों के मुताबिक़, कुछ महीने पहले सरकार द्वारा लिए गए संकल्पों का ही नतीजा है, ऑनलाइन निगरानी. जिसके तहत इस संगठित कार्य और डॉक्यूमेंट प्रबंधन प्रणाली (आईडब्ल्यूडीएमएस) के लिए पूरे राज्य में सरकार इंट्रानेट लगाने जा रही है. उस वक़्त मुख्यमंत्री मोदी ने सभी ज़िला अधिकारियों को यह निर्देश दिया था कि वे विभिन्न विभागों को यह सूची जारी कर दें, ताकि संबंधित विभागीय सचिवालय अपने नोडल अधिकारी को यह आदेश दे सके और यह योजना लागू हो सके.

ज़ाहिर है, इस नए प्रावधान की वजह से राज्य के बाबू ख़ुश कम ही होंगे. वजह साफ़ है, बाबुओं को अब यह चिंता सता रही है कि यदि वे अपनी ज़िम्मेदारियों को सही से नही निभा पाए तो उन्हें मोदी के ख़ौफ़ का सामना करना पड़ेगा.

साथ ही मुख्यमंत्री कार्यालय ऑनलाइन ही उनकी विकास रिपोर्ट तैयार करगा और बाबू प्रत्यक्ष तौर पर उनसे सवाल–जवाब बहुत ही कम कर सकते हैं. स्वाभाविक है कि इस योजना से गुजरात के बाबुओं के दिल में डर समा गया है.

श्री कृष्ण के नाम पर धोखाधड़ी

पृष्ठ 1 का शेष

कर भोजन योजना के नाम पर चंदा एकत्र करने के आरोपों की सरकार जांच करेगी. और पारदर्शिता क़ायम रहे इसकी ख़ातिर इस जांच रिपोर्ट को सदन के पटल पर भी रखा जाएगा. पर यहां भी प्रदेश सरकार का विरोधाभासी रवैया सामने आ रहा है. एक तरफ़ क़ानून मंत्री जांच का भरोसा देते हैं तो दूसरी तरफ़ राज्य के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री विशेश्वर हेगड़े संस्था के पक्ष में दलील देते ज़रा भी नहीं हिचकते. वे साफ़ तौर पर कहते हैं कि मिड डे मील को संचालित करने वाली इस्कॉन की संस्था अक्षय पात्र प्रभावी तरीक़े से अपना काम कर रही है. अब किसकी बात पर यक़ीन किया जाए?

हालांकि इस्कॉन बेंगलुरू के प्रतिनिधियों के अपने अलग ही तर्क हैं. मधु पंडित दास कहते हैं कि सभी आरोप बेबुनियाद हैं. वे ऐसा कोई काम नहीं कर रहे जिसे अनैतिक करार दिया जा सके. विदेशों से जो चंदा आता है वह धर्मार्थ गतिविधियों में इस्तेमाल होता है. अमेरिका जैसे देशों में उनकी संस्था को क़ानूनी मान्यता भी मिली हुई है. जिससे अगर कोई उन्हें दान देता है तो वह करमुक्त होता है. उनकी संस्था सभी काम वैधानिक तरीक़े से करती है. पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डी के शिव कुमार का दावा है कि उनके पास इस्कॉन के घोटाले के पक्के प्रमाण हैं. जिसे उन्होंने सदन के पटल पर भी रखा है. इनकी ज़ुबान पर भले ही हरे रामा–हरे कृष्णा का नाम है पर इनका काम धर्म–नैतिकता से परे है. देश के ग़रीब और भूखे बच्चों का पेट भरने के नाम पर इस्कॉन देश के सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रहा है. समाजसेवा के नाम पर इस्कॉन विदेशों में भारत की अस्मिता बेच रहा है. देश की सरकार और यहां के लोकतंत्र पर शर्मनाक धब्बा लगा रहा है. क्यों इस्कॉन बेंगलुरू विदेशों में ख़ुद को चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में पेश करता है? जब भारत सरकार पूरी सहायता राशि और अनाज़ मुहैया करा रही है फिर भी भोजन योजना के नाम पर सहायता राशि की अपील क्यों की जा रही है? क्यों संस्था सरकार से और अनाज़ की मांग करती है? यह कहते हुए कि सरकार द्वारा दी जा रही सहायता राशि अपर्याप्त है. जबकि मिड डे मील के नाम पर मिल रहे सरकारी अनाज़ को यही संस्था काले बाज़ार में बेच देती है. ऐसा करते हुए संस्था के ट्रक को रंगे हाथ पकड़ा भी जा चुका है.

सचमुच यह बात हैरान कर देने वाली है कि इस्कॉन बेंगलुरू, भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना सर्वशिक्षा अभियान से जुड़ी योजना मिड डे मील के नाम पर इस्कॉन विश्व के बाज़ार में भारत की ग़रीबी और भूख का इश्तहार लगा कर मदद के नाम पर चंदा वसूली कर रहा है. एक आम आदमी से लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा तक से भारतीय बच्चों की भूख मिटाने के नाम पर वसूली कर चुकी है ये संस्था. विदेशों में इस संस्था ने बाक़ायदा व्यवसायिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति कर रखी है. प्रोफेशनल वेबसाइट के ज़रिए भी दान मांगने का काम चालू है. फिर भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है. क्या एक संस्था, संस्था का अध्यक्ष या फिर उसके राजनीतिक संबंध इतने अहम हैं कि वह राष्ट्र हित से ऊपर हो जाते हैं? ख़ासकर एक ऐसा व्यक्ति जो पहले से ही विवादित रहा हो. जिसके ऊपर अदालत में फ़र्ज़ीवाड़े का मुक़दमा चल रहा हो.

मज़ेदार तथ्य यह भी है कि बेंगलुरू इस्कॉन और मुंबई इस्कॉन के बीच ख़ुद को असल इस्कॉन साबित करने की होड़ लगी है और यह मसला अदालत तक पहुंच गया है. सन 2001 से यह मामला अदालत में है. इस विवाद में एक जज का नाम भी घसीटा जा चुका है. मुंबई इस्कॉन का आरोप है कि बेंगलुरू इस्कॉन के चीफ मधु पंडित दास एक षड्यंत्रकारी किस्म के व्यक्ति रहे हैं. उनकी बेजा हरकतों के मद्देनज़र ही उन्हें मुख्य इस्कॉन से 2001 में ही निकाला जा चुका है. उसके बाद मधु पंडित दास ने फ़र्ज़ीवाड़ा करते हुए बेंगलुरू में नक़ली इस्कॉन और हरे कृष्ण आंदोलन की स्थापना की. इतना ही नहीं, मधु पंडित दास ने कर्नाटक सरकार से 200 करोड़ रुपये की ज़मीन भी हथिया ली. साथ ही मिड डे मील के नाम पर देश और विदेशों में मधु पंडित दास ने कई चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना कर डॉलर के रूप में चंदा इकठ्ठा करना शुरू कर दिया. प्रदेश कांग्रेस के नेता बताते हैं कि भोजन योजना के रूप में एकत्रित राशि को मधु पंडित दास अपने परिवार के रियल स्टेट बिज़नेस में लगाते हैं न कि भारत के ग़रीब बच्चों की भूख मिटाते हैं. यही वजह है कि कुछ ही सालों में मधु पंडित दास और उनके परिवार के लोग अचानक ही बेंगलुरू के सबसे बड़े रियल स्टेट परियोजना डेवलपर्स में से एक हो गए हैं. इस बात की जांच होनी चाहिए कि एक ऐसा शख़्स जिसे धोखाधड़ी के मामले में उसकी पुरानी संस्था निकाल देती है वह आख़िरकार कैसे इतनी बड़ी हस्ती बन जाता है. प्रदेश कांग्रेस तो अब यह मांग करने लगी है कि मधु पंडित दास के संपर्कों और उनके धन के स्रोतों की सीबीआई जांच होनी चाहिए.

चौथी दुनिया के पास जो तथ्य मौजूद हैं उनसे यह बात साफ़ है कि बेंगलुरू इस्कॉन धर्म के नाम पर, भगवान कृष्ण के नाम पर या समाजसेवा के नाम पर जो कुछ भी कर रहा है वह बेदाग़ नहीं हैं. प्रमाण इस बात के भी हैं कि मधु पंडित दास को जो ज़मीन राज्य सरकार ने धर्मार्थ मुहैया कराई है उसके पीछे किन दिग्गज़ों के हाथ हैं. क्योंकि कनकपुरा रोड पर जो 650 फ्लैट और दुकानें बनाई और बेची जा रही हैं उनमें राजनीतिक हस्तियों के रिश्तेदारों की भी हिस्सेदारी है. इसके अलावा एक विशाल फाइव स्टार होटल, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, शॉपिंग मॉल भी निर्माणाधीन है. देवेनाहाली हवाई अड्डे के पास एक लक्ज़री टाउनशिप पर भी काम चल रहा है. अपने ऊंचे राजनीतिक संपर्कों की बदौलत मधु पंडित दास और उनके दो सगे भाई जयपुर, वृंदावन और मथुरा में भी टाउनशिप परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं. त्रिवेंद्रम में कोवलम तट पर स्वास्थ्य रिसॉर्ट बनाया जा रहा है. एक साधु जो आज से साढ़े आठ साल पहले ख़ाली हाथ था, आज वह एक हज़ार करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति का मालिक बन बैठा है. यह बात हर किसी के लिए अचरज भरी है. संपत्ति के जो भी आंकड़े हैं वे पूरी तरह प्रमाणिक हैं, क्योंकि इसे मधु पंडित दास द्वारा ही कर्नाटक विधान सभा की पटल पर तब रखा गया, जब विपक्षियों के हमले से घबरा कर कर्नाटक सरकार ने मधु पंडित से 13 अप्रैल को जवाब तलब किया. पर उसके बाद महीनों बीत गए. कर्नाटक सरकार ने फिर चुप्पी साध रखी है. मुंबई इस्कॉन के प्रतिनिधि का आरोप है कि मधु पंडित दास हमारे नाम पर भी धोखाधड़ी कर रहे हैं. मुंबई इस्कॉन ने इस बाबत कर्नाटक के मुख्यमंत्री से मिल कर अपनी शिकायत भी दर्ज़ कराई पर उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है. हम अपना मसला कोर्ट की मार्फ़त ही सुलझाएंगे.

वैसे देखा जाए तो इस्कॉन की ये पुरानी रवायत है. इस्कॉन पहले भी संदेह के दायरे में रहा है. उस पर अमेरिकी ख़ुफ़िया एजेंसी सीआईए का एजेंट होने का आरोप भी लग चुका है. यह अलग बात है कि यह संदेह कभी साबित नहीं हो सका. धर्म की आड़ में अपनी जेब भरने की ख़ातिर यहां ख़ूब तथाकथित हरकतें की जाती हैं. कुछ वक़्त–वक़्त पर सामने भी आई हैं, पर बहुतेरी भगवा चादर तले दबा दी जाती हैं. मुंबई इस्कॉन भी कोई दूध का धुला नहीं है.

पर इस्कॉन बेंगलुरू अभी जो कुछ भी कर रहा है वह राष्ट्रविरोधी ज़रूर है. और इस काम में उसके संरक्षक बने लोग भी देश हित के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं.

कितनी तक़लीफ़ की बात है जब भारत एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है और दुनिया भी भारत की बढ़ती हैसियत को खुले मन से स्वीकार कर रही है. ऐसे में विश्व के सामने भारत की भूखी नंगी तस्वीर पेश कर अपनी जेब भरने के लिए चंदा जुटाया जा रहा है. शर्मसार कर देने वाली ऐसी नापाक़ हरकत पर राज्य सरकार के साथ–साथ भारत सरकार भी अंधी–बहरी बनी बैठी ही है. क्या वाक़ई सभी राजनीतिक दल एक ही थैली के चट्टे–बट्टे हैं? क्या महज़ लफ्फ़ाज़ियां करने और एक–दूसरे पर कीचड़ उछालने भर से ही इनका राष्ट्र के प्रति कर्तव्य पूरा हो जाता है? क्या मौजूदा प्रकरण तो यही तस्वीर पेश नहीं करता? तो क्या ये समझा जाए कि देश के सम्मान और स्वाभिमान की चिंता किसी भी राजनीतिक दल को नहीं? अगर फ़िक्र होती तो मधु पंडित दास सरीख़े तथाकथित धर्म के ठेकेदारों की इतनी जुर्रत नहीं होती कि वो भारत के वजूद को विश्व भर में ज़लील करने की सोच भी पाते.

ruby@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
देश का पहला साप्ताहिक अखबार

वर्ष 1 अंक 32, 19 अक्टूबर–25 अक्टूबर 2009

संपादक
संतोष भारतीय

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63, नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के– 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनाट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के–2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग
कनाट प्लेस, नई दिल्ली 110001

फोन न.
संपादकीय 011–47149999
विज्ञापन + 0120–4783999
प्रसार + 91 9810017924
फैक्स न. 0120–4783950

पृष्ठ–16 (+4 बिहार व झारखंड)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुनः प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

घोषणा के दो साल बीत जाने के बाद भी केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रीय भूमि सुधार नीति घोषित नहीं की गई. प्रधानमंत्री ने वादा करके भुला दिया.

केंद्र सरकार को चेतावनी

भूमिहीन ग़रीबों का सत्याग्रह

मनीष कुमार

दिल्ली में फिर से एक जनसैलाब आने वाला है. गांधीजी की राह पर भूमिहीन किसान फिर से चलने को तैयार हैं. भूमिहीन ग़रीब सत्याग्रह करने वाले हैं. इस सत्याग्रह का आग़ाज़ एकता परिषद और साथी संगठनों के जनादेश दिवस 29 अक्टूबर को होगा. 29 अक्टूबर से 2 नवंबर के दौरान देश भर से आए तीन हज़ार भूमिहीन ग़रीब दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करेंगे. सरकार के सामने यह मांग रखेंगे कि देश के भूमिहीन ग़रीबों को ज़मीन का मालिकाना हक़ मिले. सरकार पहले भी कई बार भूमि सुधार की बात कर चुकी है, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ है. अब इन भूमिहीन ग़रीबों का एक ही सवाल है कि सरकार केवल घोषणाएं ही करेंगी या काम भी. देश भर से आए तीन हज़ार लोग पूरे देश के ग़रीबों की आवाज़ बनकर आए हैं. ये उन मुद्दों पर सरकार को आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं, जो देश में हर भूमिहीन किसान और मज़दूर के लिए ज़रूरी हैं. 29 अक्टूबर से शुरू होने वाला सत्याग्रह चेतावनी मात्र है. एकता परिषद का कहना है कि अगर इस सत्याग्रह को सरकार ने नज़रअंदाज़ किया तो अक्टूबर 2011 में एक लाख लोगों का दिल्ली में प्रदर्शन होगा.

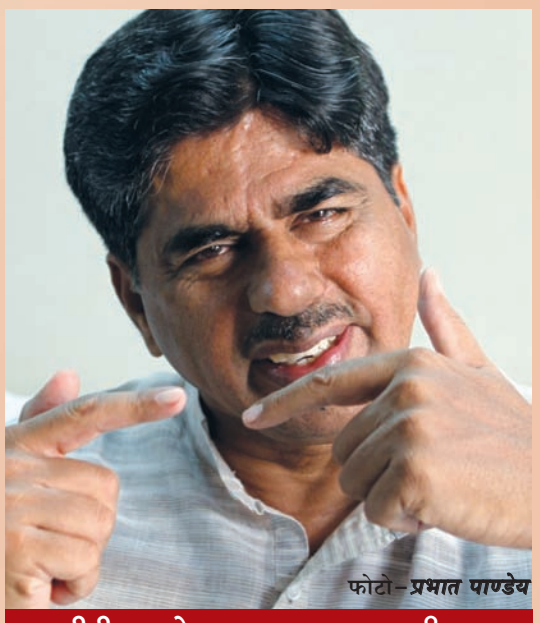

फोटो- *प्रभात पाण्डेय*

पीवी राजगोपाल, अध्यक्ष, एकता परिषद

भारत में प्रजातंत्र का कैसा रूप है, जहां कुछ लोगों की मांगें तो बंद कमरों में चुपचाप मान ली जाती हैं, वहीं कुछ लोग अपनी जायज़ मांगों को लेकर चीखते-चिल्लाते और धरना- प्रदर्शन करते रह जाते हैं, लेकिन सरकार की कान पर जूं तक नहीं रेंगती. उनकी मांगें सुनकर भी अनसुनी कर दी जाती हैं. देश में एक ख़तरनाक स्थिति पैदा हो गई है. शक्तिशाली और अमीर लोग सरकार की मदद से ज़मीन की लूटखसोट में लगे हैं. औद्योगीकरण, वैश्वीकरण, बाज़ारवाद और पर्यटन को बढ़ावा देने के नाम पर ग़रीबों की ज़मीन छीनी जा रही है. लाखों लोगों को एक व्यवस्थित और बर्बर ढंग से उनकी भूमि से बेदख़ल किया जा रहा है. ये ग़रीब जनता बहुमत में हैं. हमें यह याद रखना चाहिए कि उस प्रजातंत्र का अस्तित्व ख़तरे में होता है, जहां का बहुमत हाशिए पर आ जाता है. फ़िलहाल भारत सरकार तो सिर्फ़ इस बात से परेशान है कि नक्सलियों से कैसे मुक़ाबला किया जाए. सरकार की बेरुख़ी की वजह से, जिस दिन ये ग़रीब भूमिहीन बहुमत बंदूक़ उठा लेगी, उस स्थिति से निपटने के लिए न तो सरकार के पास कोई साधन होगा और न ही देश में प्रजातंत्र बचेगा. प्रधानमंत्री जी से यह उम्मीद है कि वह इस चेतावनी रैली को बड़े ध्यान से सुनेंगे.

इतिहास गवाह है कि जन आंदोलनों ने बिना किसी हिंसा के कई ताक़तवर हुकूमतों को मिट्टी में मिला दिया. यह भारत है. यहां गांधी को प्यार करने वाले लोग रहते हैं. जीवन की समस्याओं से जूझने वाले ग़रीबों और भूमिहीनों ने गांधीजी के तरीक़ों को अपनाया है. वे सत्याग्रह करने वाले हैं. एकता परिषद के संस्थापक और अध्यक्ष पी वी राजगोपाल कहते हैं कि अगर वंचितों के इस अहिंसक संघर्ष को केंद्र सरकार नज़रअंदाज़ करेगी तो यही लोग कल को आत्महत्या करेंगे या किसी की हत्या करने को मजबूर होंगे. हम गांधी के बताए रास्ते पर चलकर संघर्ष इसलिए कर रहे हैं, ताकि देश और दुनिया को बताया जा सके कि गांधी का तरीक़ा कारगर तरीक़ा है. एकता परिषद का कहना है कि अगर 29 तारीख़ से होने वाले धरना पर सरकार ने ग़ौर नहीं किया तो वह देशव्यापी आंदोलन छेड़ेगी और 2011 में दिल्ली में देश भर से एक लाख भूमिहीन सत्याग्रह करने पहुंचेंगे. यह जनसैलाब इस बात का भी गवाह बनेगा कि बाज़ारवाद के इस दौर में किस तरह प्रजातंत्र शक्तिशाली और अमीरों के हाथों की कठपुतली बन गया है.

जल, जंगल, ज़मीन और ग़रीब की बात करने वाले देश में सैकड़ों संस्थाएं हैं, लेकिन वे सेमिनार तक ही सीमित हैं. एकता परिषद ने इसे ज़मीन पर उतार कर दिखाया है. एकता परिषद ने 2007 के ऐतिहासिक सत्याग्रह को दोहराने की ठान ली है, लेकिन इस बार का जनादेश पहले वाले सत्याग्रह से ज़्यादा विशाल और सशक्त होगा. 29 अक्टूबर के सत्याग्रह का मतलब क्या है, यह समझने के लिए यह जानना ज़रूरी है कि 2007 में क्या हुआ था.

पूरे देश से 25000 भूमिहीन ग़रीब ग्वालियर से दिल्ली तक की पदयात्रा करते हुए 29 अक्टूबर 2007 को दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंचे. 2007 की पदयात्रा में वही आदिवासी और दलित शामिल हुए, जो अपनी ज़मीन खो चुके थे. किसी की ज़मीन पर सामंतों ने अवैध ढंग से क़ब्ज़ा कर रखा था, तो किसी की ज़मीन भू-माफ़ियाओं ने हड़प ली थी. कोई सरकार की परियोजनाओं में अपनी ज़मीन खो बैठा तो कोई औद्योगिक विकास की चपेट में आ गया. ग़रीब की जब ज़मीन ही चली जाए तो वह क्या करेगा, यह किसी ने नहीं सोचा.

2007 के सत्याग्रह से एक साल पहले चार सौ साथियों के साथ चेतावनी यात्रा की गई थी. प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि एक साल के भीतर सरकार उनकी मांगों पर कार्रवाई करे. अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो 25000 सत्याग्रही ग्वालियर से दिल्ली मार्च करेंगे. देखते ही देखते पूरा साल बीत गया, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया. सरकार के रवैए को देखते हुए एकता परिषद के कार्यकर्ता प्रदर्शन की तैयारी में फिर से जुट गए.

हज़ारों पदयात्रियों के लिए खाना, पानी, दवा और उनके लिए सारे बंदोबस्त को सफलता के साथ अंजाम दिया गया. यात्रा के पहले दिन जब सत्याग्रही ढोल-नगाड़े बजाते, नाचते-गाते और नारे लगाते कतारबद्ध होकर सड़कों पर उतरे तो उनका यह जुलूस दस किलोमीटर लंबा हो गया. यात्रा को देखने वालों की आंखें थक जातीं, पर यात्रा का दृश्य उनकी आंखों से ओझल नहीं होता. तीन दिनों की पदयात्रा के रास्ते अनेक सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक नेता-कार्यकर्ता दलगत सीमाओं से ऊपर उठकर हर पड़ाव पर मदद के लिए आगे आए. पदयात्रियों को दिल्ली पहुंचने तक आम लोगों का भरपूर समर्थन मिला, लेकिन सरकार की ओर से निराशा ही हाथ लगी. प्रधानमंत्री के विशेष दूत बनकर आए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने यह घोषणा की थी कि प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए भूमि सुधार कमेटी का एक महीने के अंदर गठन करने का निर्देश दिया है और प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद का गठन किया जाएगा, जो राष्ट्रीय भूमि सुधार नीति को मंजूरी प्रदान करेगी. मगर, इस घोषणा के दो साल बीत जाने के बाद भी केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रीय भूमि सुधार नीति घोषित नहीं की गई. प्रधानमंत्री ने वादा करके भुला दिया. भूमिहीनों को भूमि का मालिकाना हक़ देने, किसानों को ज़मीन का उचित मुआवज़ा दिलाने और न्यायालय में लंबित मामलों का निस्तारण करने जैसी कई अन्य भूमि संबंधी समस्याओं का समाधान भूमि सुधार नीति को लागू करने से हो सकता है.

ये मामले सिर्फ़ तीन हज़ार भूमिहीन किसानों के नहीं हैं. यह आवाज़ पूरे देश के ग़रीबों की आवाज़ है. भूख और लाचारी का रंग एक ही है, चाहे वह भूमिहीन मज़दूर उड़ीसा का हो या फिर बिहार का. उनकी परेशानियां एक जैसी हैं. उनके दुख एक हैं. एकता परिषद के नेतृत्व में ज़मीन से जुड़े किसान और मज़दूर राष्ट्रीय भूमि सुधार नीति की घोषणा की मांग करने, प्रधानमंत्री को उनका वादा याद दिलाने दिल्ली आ रहे हैं.

देश में भूमिहीनों, वंचितों को भूमि का मालिकाना हक़ नहीं मिल रहा है और बड़े पैमाने पर किसानों और आदिवासियों से भूमि अधिग्रहित करने का काम चलाया जा रहा है. वनाधिकार क़ानून भी लागू किया गया, इस क़ानून को सही तरीक़े से लागू करने के लिए कोई ठोस क़दम नहीं उठाए गए, इसलिए ज़मीनी स्तर पर इस क़ानून का कोई ख़ास असर नहीं दिखा. अदिवासियों को उनकी ज़मीन का मालिकाना हक़ नहीं मिला. भूमिहीन मजदूरों की हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है. छोटे किसान आत्महत्या कर रहे हैं. लगता है कि देश चलाने वालों की आंखों पर पट्टी बंधी है या फिर सरकार को यह लगता है कि जिनके पास उत्पादन के साधन नहीं हैं, जो उपभोक्ता नहीं हैं, जो बाज़ार से सामान नहीं ख़रीद सकते, जिनके पास जमा करने के लिए धन नहीं है, वे भूमिहीन और ग़रीब नष्ट करने योग्य हैं.

manish@chauthiduniya.com

गांधी शांति प्रतिष्ठान की अध्यक्ष राधा भट्ट हिमालय के बिगड़ते पर्यावरण से बेहद दुखी हैं. उन्हें भावी पीढ़ी को होने वाली परेशानी की चिंता सताती है, तो सरकार की उदासीनता भी उन्हें सालती है. लेकिन वह नाउम्मीद नहीं हैं, इसलिए पदयात्रा के ज़रिए लगातार जागरूकता अभियान चला रही हैं.

अभी और जंग लड़नी है : राधा भट्ट

फोटो–प्रभात पाण्डेय

सरकारों की शोषक प्रवृत्ति नदियों के विनाश का कारण बन रही है. अगर हिमालय की नदियां सूख जाएंगी तो उत्तरी भारत तबाह हो जाएगा. बांग्लादेश और पाकिस्तान तक पानी की घोर कमी हो जाएगी. मानव आबादी ख़त्म होने लगेगी. सरकार कंपनियों का साथ दे रही है. उसे अपनी जनता की कोई चिंता नहीं है. सरकार यह सोचने तक को तैयार नहीं कि अगर प्राकृतिक स्रोत ख़त्म हो गए तो पीढ़ियां बरबाद हो जाएंगी.

हिमालय को बचाना है. नदियों, पर्वतों और जंगलों को पैसों के लालची व्यापारियों की भेंट नहीं चढ़ने देना है. चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े. गांधी शांति प्रतिष्ठान की अध्यक्ष राधा भट्ट के दिन रात आजकल इसी जद्दोज़हद में कट रहे हैं. वे लड़ रही हैं. उत्तराखंड की महिलाओं के साथ आंदोलन कर रही हैं. पर्वतों, नदियों, जंगलों और घाटियों की पद यात्रा करते हुए सरकार के ख़िलाफ़, व्यापारियों और बिल्डरों के ख़िलाफ़ विरोध के स्वर पूरी मज़बूती से दर्ज़ करा रही हैं. रचना और संघर्ष के साझी पहल की अनूठी मिसाल पेश कर रही हैं.

लगभग 76 वर्ष की उम्र में भी राधा भट्ट की दुबली–पतली काया में कुछ कर गुज़रने की आग धधक रही है. उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले के धुरका गांव में पैदा हुईं राधा भट्ट ने उत्तराखंड के वजूद को मूल स्वरूप में क़ायम रखने की ख़ातिर पूरी ज़िंदगी लड़ाई लड़ी है. आज भी ये जन जीवन और पर्यावरण पर आए संकट के लिए संघर्ष कर रही हैं. उत्तराखंड की नदियों के तेज़ी से घटते जा रहे प्रवाह और जलस्तर, कंपनियों की मनमानी व लूट, प्रशासन द्वारा जवाबदेही के कर्तव्य की उपेक्षा के विरूद्ध राधा भट्ट ने गांधीवादी तरीक़े से मोर्चा खोल दिया है. अपनी पूरी ज़िंदगी राधा भट्ट ने समाज के उत्थान के लिए क़ुर्बान कर दी, पर आज भी इनकी अदम्य जिजीविषा क़ायम है.

सरकार के कामकाज के तरीक़े से ये बेहद ख़फ़ा हैं. कहती हैं कि सरकार प्रगति के नाम पर उत्तराखंड के अस्तित्व को संकट में डाल रही है. सेब के बगीचों को बिल्डरों के हाथों बेच दिया जा रहा है. जहां वे नाजायज़ तरीक़ों से काटेजेज़ का निर्माण कर रहे हैं. गांववालों के पीने के पानी का अवैध तरीक़े से दोहन कर रहे हैं. राधा भट्ट ने कादीर राणा और कंपनी नामक उस बिल्डर के विरोध में भी पदयात्रा निकाली है. वे लोगों को उसके ग़लत कामों के विरोध में जागरूक कर रही हैं ताकि वह आइंदा भोले–भाले ग्रामीणों का बेज़ा फ़ायदा न उठा सके. इसके अलावा उन्होंने 5000 आम लोगों के साथ उत्तराखंड नदी बचाओ अभियान के तहत 15 नदी घाटियों में 2000 किलोमीटर की पदयात्रा भी की, जिसमें उन्होंने पाया कि अगर सरकार लगातार अंधाधुंध हिमानी नदियों पर बांध बनाती रही तो आने वाले बीस वर्षों में उत्तराखंड में पानी के लिए त्राहि–त्राहि मच जाएगी. यहां के संवेदनशील पर्वतों और जंगलों का जीवन संकट में पड़ जाएगा.

राधा भट्ट कहती हैं कि सरकार बिना सोचे–समझे यहां 330 बड़े और मध्यम सुरंग और बांध बनाने की योजना को अमली जामा पहना रही है. जिनसे वह 30 हज़ार मेगावाट बिजली उत्पादन कर उत्तराखंड के लोगों को ऊर्जा प्रदेश बनाने का सपना दिखा रही है. पर इन टनल्स को बनाने के क्रम में पहाड़ हिल जाते हैं. जिससे भूस्खलन का ख़तरा बढ़ जाता है. उत्तराखंड वैसे भी भूकंप के लिहाज़ से बेहद संवेदनशील क्षेत्र है. सुरंगों को बनाने के लिए जो विस्फोट किए जाते हैं, उनकी वजह से जोशीमठ, ज़िला चमोली आदि जगहों पर रहने वाले लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं. रूद्रप्रयाग के चमोली गांव की धरती हर धमाके में थर्रा जाती है. ये यक़ीनन मानव के जीवित रहने के अधिकार का हनन है.

राधा भट्ट कहती हैं कि सरकारों की ये शोषक प्रवृत्ति नदियों के विनाश का कारण बन रही है. अगर हिमालय की नदियां सूख जाएंगी तो उत्तरी भारत तबाह हो जाएगा. बांग्लादेश और पाकिस्तान तक पानी की घोर कमी हो जाएगी. मानव आबादी ख़त्म होने लगेगी. सरकार कंपनियों का साथ दे रही है. उसे अपनी जनता की कोई चिंता नहीं है. सरकार यह सोचने तक को तैयार नहीं है कि अगर प्राकृतिक स्रोत ख़त्म हो गए तो पीढ़ियां बरबाद हो जाएंगी.

सरकार की उदासीनता से नाराज़ राधा भट्ट अब यह मानने लगी हैं कि जनता को अपने हक़ की ख़ातिर अब समानांतर सरकारों का गठन करना चाहिए, जिस तरीक़े से महाराष्ट्र के हिवड़े बाज़ार के निवासियों ने किया. अब ज़रूरत है कि जनता सभी को नेपथ्य में डाल कर ख़ुद सामने आकर ख़म ठोके.

राधा भट्ट का नाम गांधी–विनोबा युग के बचे हुए थोड़े से गांधीवादियों में प्रमुखता से शुमार किया जाता है. वे आज देश–दुनिया के शीर्षस्थ गांधीवादी संस्थाओं और संगठनों में अहम पदों पर हैं. पिछले पचास वर्षों से महात्मा गांधी के विचारों को अपने जीवन में चरितार्थ करते हुए राधा भट्ट ने जिस दृढ़ता से उन विचारों को समाज निर्माण की दिशा में लागू करने की अथक साधना की है वह बेमिसाल है. विनोबा भावे के भूदान आंदोलन, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन, शराबबंदी, खनन और नदी बचाओ जैसे आंदोलनों ने राधा भट्ट के व्यक्तित्व का निर्माण किया है.

राधा भट्ट, अपने चाहने वालों के बीच राधा दीदी के नाम से जानी जाती हैं. इनका मानना है कि जीवन तो समाज के लिए कुछ सार्थक कर गुज़रने का नाम है. सरकार की उदासीनता के बावजूद राधा भट्ट की हिम्मत नहीं टूटी है. राधा भट्ट कहती हैं कि वह उस गिलहरी की तरह अपना काम करना जानती हैं जो भगवान राम के श्रीलंका जाने के लिए सेतुबंध बनाने की ख़ातिर बहुत अल्प ही सही लेकिन निरंतर सहयोग देती रही. किसी भी काम का नतीजा तुरंत मिले, ऐसी कल्पना भी नहीं करनी चाहिए. बस आपके विचार और आपकी दिशा सही होनी चाहिए. राधा भट्ट के साथ पूरा कारवां है जो उनके विचारों के मुताबिक़ आंदोलन को गति दे रहा है. उत्तराखंड की महिलाओं का बड़ा समूह राधा भट्ट की अगुआई में अपनी नदियों को बचाने के लिए कृतसंकल्प है. कुल 12 नदियां कौसानी से निकलती हैं और उन सबके पानी पर सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं ने संकट पैदा कर रखा है. हर हाल में उन नदियों को बचाने की कशमकश जारी है. राधा भट्ट बताती हैं कि पहाड़ की महिलाएं अपनी प्राकृतिक संपदाओं के संरक्षण के लिए इतनी जागरूक हो चुकी हैं कि वे वन विभाग से तालमेल कर गांव–गांव में छोटे–छोटे तालाब बना रही हैं, वर्षा के जल को एकत्र कर रही हैं और भू–स्खलन के ख़तरों को रोकने के उपाय कर रही हैं.

हालांकि राधा भट्ट ने इस बाबत समिति की ओर से सरकार को दिक़्क़तों और उपायों का मसौदा बना कर भी दिया है. प्रधानमंत्री ने उन्हें आश्वासन भी दिया है कि उनके सुझावों पर अमल किया जाएगा. पर अभी तक कोई सरकारी पहल शुरू नहीं की गई है.

रूबी अरुण
ruby@chauthiduniya.com

नोएडा में देश का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी पार्क बनाने का सपना आख़िर क्यों नहीं पूरा हो पाया? क्या प्रदेश की बेलगाम नौकरशाही और नोएडा प्राधिकरण इसकी कसूरवार नहीं है?

नोएडा : बिखर गया आईटी हब बनने का सपना

सपना था एक बेहतर कल के निर्माण का. लेकिन, अफसरशाही के आगे भला किसकी चली है? नोएडा को देश का सबसे बड़ा आईटी हब बनाने का सपना भी अफसरों की मनमानी का शिकार हो गया. कैसे? पढ़िए इस रिपोर्ट में.

फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

शशि शेखर

नोएडा के सेक्टर 29 में है गंगा शॉपिंग कांप्लेक्स. वर्ष 1996 में यहीं से शुरू किया गया था एक सपने को साकार करने का सरकारी प्रयास. सपना था नोएडा को देश का सबसे बड़ा आईटी हब बनाना और सबसे बड़े सॉफ्टवेयर आयात केंद्र की स्थापना करना. लेकिन यह सपना हक़ीक़त बनने से पहले ही टूट गया. जहां देशी–विदेशी सॉफ्टवेयर कंपनियों के दफ़्तर खुलने थे, वहां आज एक भी सॉफ्टवेयर कंपनी खोजने से भी नहीं मिलती. हां, शेयर का धंधा करने वाली कंपनियां ज़रूर चलती हैं. सरकारी दफ़्तरों के बाबू फाइलों में उलझे नज़र आते हैं. सॉफ्टवेयर कंपनियों के लिए बनाए गए केबिनों की फर्श पर जहां धूल पसरी हुई है, वहीं छतों से लटकते मकड़ियों के जाले उस सरकारी सपने को मुंह चिढ़ा रहे हैं, जिसने देश को सबसे बड़ा आईटी हब देने का वायदा किया था.

दरअसल, यह पूरी कहानी शुरू होती है नब्बे के शुरुआती दौर से. तब सॉफ्टवेयर, सूचना तकनीक और सिलिकॉन वैली जैसे शब्द आम हिंदुस्तानियों के दिल में रोमांच पैदा कर देते थे. अमेरिका से चले ये सारे हाई प्रोफाइल शब्द देश के राजनीतिक गलियारों के लिए मानो विकास का मूलमंत्र बन गए थे. सरकार ने लोगों को सपना दिखाया कि हम भी अमेरिका की तरह अपने देश में एक नहीं, कई सिलिकॉन वैली बना सकते हैं. इसी मक़सद से भारत सरकार ने वर्ष 1991 में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क नाम से एक संस्था बनाई. दक्षिण भारत के बेंगलुरू और हैदराबाद जैसे शहरों को इस दौड़ में आगे देख उत्तर भारत ने भी इसमें शामिल होने का निर्णय लिया. इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य को आईटी हब बनाने का फ़ैसला किया. 1996 में दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 29 स्थित गंगा शॉपिंग कांप्लेक्स में नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की गई. कहा गया कि यह देश का सबसे बड़ा आईटी हब बनेगा, साथ ही सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर निर्यात केंद्र भी. टेक्नोलॉजी पार्क की देखरेख की ज़िम्मेदारी सौंपी गई नोएडा विकास प्राधिकरण को.

शुरुआती दौर में कई सॉफ्टवेयर कंपनियों ने इस टेक्नोलॉजी पार्क में रुचि दिखाई और यहां से अपना कारोबार शुरू करने के लिए आवेदन किया. प्राधिकरण ने लीज होल्ड और रेंटल बेसिस पर कंपनियों को केबिन आवांटित कर दिए. लीज होल्ड और रेंटल बेसिस पर केबिन आवंटन पहले पांच सालों के लिए किए गए. हालांकि लीज डीड में इस बात का भी उल्लेख था कि पांच साल की समय सीमा को और आगे भी बढ़ाया जा सकता है.

2003–04 तक यह टेक्नोलॉजी पार्क सचमुच देश का दूसरा सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी पार्क बन गया. हज़ारों करोड़ रुपये का कारोबार होने लगा. नोएडा अचानक ही बेंगलुरू और हैदराबाद से होड़ लेने लगा. लेकिन, इसके बाद अचानक इस टेक्नोलॉजी पार्क को किसी की बुरी नज़र लग गई. सॉफ्टवेयर कंपनियों के शटर गिरने लगे. आवंटित किए गए केबिन एक के बाद एक करके ख़ाली होते चले गए. वजह एक नहीं, कई थीं. कुछ कंपनियां तो घाटे की वजह से बंद हुईं और उनके केबिन ख़ाली हो गए. लेकिन उन कंपनियों के दफ़्तर भी सील कर दिए गए, जो पांच साल की समय सीमा बीतने के बाद भी अपना काम जारी रखना चाहती थीं और उनका काम अच्छा ख़ासा चल रहा था. यहीं से नोएडा विकास प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश सरकार की भूमिका सवालों के घेरे में आनी लगी. प्राधिकरण के अधिकारियों की मनमानी और सरकार की बेरुखी दिखनी शुरू हो गई. इसी का नतीजा था कि जब कुछ कंपनियों के रेंटल लीज की समय सीमा ख़त्म हो गई तो प्राधिकरण के अधिकारियों ने उस समय सीमा को नहीं बढ़ाया. इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? जब इस टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना ही सॉफ्टवेयर विकास और सॉफ्टवेयर कंपनियों के लिए की गई थी तो प्राधिकरण को समय सीमा बढ़ाने में क्या परेशानी थी? ऐसी ही एक कंपनी एक्लिप्स सिस्टम के मालिक हैं एम.के. सिंघल, जिन्हें 15 अक्टूबर 2001 को केबिन संख्या 206, 207 और 208 आवंटित किए गए थे. पांच साल पूरे होने पर जब सिंघल ने लीज की समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया तो प्राधिकरण ने ऐसा करने से इंकार कर दिया. ज़िला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक ने भी मामले में हस्तक्षेप करते हुए प्राधिकरण को लिखा कि एक्लिप्स सिस्टम आईटी क्षेत्र की कंपनी है और इसे हटाए जाने से सॉफ्टवेयर उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए संबंधित मामले पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाए. लेकिन, प्राधिकरण पर इसका कोई प्रभाव नही पड़ा. अधिकारियों की तानाशाही और मनमौजी रवैए के चलते बिना कोई कारण बताए 24 नवंबर 2006 को सिंघल की कंपनी सील कर दी गई. बकौल सिंघल, कुछ अधिकारियों ने मुझसे अपने रिश्तेदारों के लिए नौकरी की मांग की थी. चूंकि मेरी कंपनी छोटी थी और उसमें ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं थी, इसीलिए मैंने उन्हें मना कर दिया था. हो सकता है कि उक्त मांग पूरी न हो पाने के कारण ही सिंघल पर गाज गिरी हो. इसके बाद सिंघल ने सूचना का अधिकार क़ानून के तहत प्राधिकरण से अपनी कंपनी सील किए जाने की वजह पूछी. इस पर सीधे सीधे कुछ न बताकर कहा गया कि समय सीमा बढ़ाने के आपके आवेदन को स्वीकार नहीं किया गया. इसके अलावा अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी का आदेश है कि वाणिज्यिक कार्यों के लिए इन परिसंपत्तियों को टेंडर के आधार पर निस्तारित किया जाए. हालांकि प्राधिकरण या उसके अधिकारी यह तय नहीं कर सकते थे कि टेक्नोलॉजी पार्क के केबिनों की व्यापारिक संपत्ति के तौर पर नीलामी की जाए अथवा नहीं, क्योंकि इस टेक्नालॉजी पार्क की स्थापना सॉफ्टवेयर उद्योग के विकास के लिए की गई थी. प्राधिकरण द्वारा बनाई गई लीज डीड के मुताबिक़ भी इस पार्क में सिर्फ़ सॉफ्टवेयर या उस पर आधारित कंपनी ही चलाई जा सकती है.

निश्चित तौर पर नोविप्रा का यह आदेश तुगलकी फ़रमान था. साफ़ पता चलता है कि प्राधिकरण प्रशासन की दिलचस्पी सॉफ्टवेयर विकास या आईटी हब से ज़्यादा अपनी मर्ज़ी चलाने में है. कहानी का दिलचस्प पहलू यह है कि इतना कुछ होने के बाद भी राज्य सरकार ने इस प्रकरण में दख़ल देना ज़रूरी नहीं समझा. समझे भी क्यों? जब सत्ता अंबेडकर पार्क, उत्तम प्रदेश और राम मंदिर बना देने के वायदे भर से ही मिल जाती हो तो आख़िर कहीं और मेहनत करने की ज़हमत भला कोई क्यों उठाएगा?

ज़ाहिर है, उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे सच का सामना करना ही नहीं चाहती, जो उसे उसकी असली तस्वीर दिखाता हो. एक कड़वा सच. यह सच है राज्य से पलायन करते मजदूरों का, यह सच है आत्महत्या करते किसानों का, यह सच है बंद होते कल–कारखानों का. इन हालात में नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क उम्मीद की किरण बनकर आया था, जो भ्रष्टाचार, नौकरशाही और व्यवस्था की बेरुख़ी का शिकार बन गया.

feedback@chauthiduniya.com

सिलिकॉन वैली बनाम टेक्नोलॉजी पार्क

सिलिकॉन वैली शब्द का इस्तेमाल अमेरिका के कैलीफोर्निया शहर के लिए किया जाता है. वजह, इस शहर में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर और इंटरनेट कंपनियां उत्पादन कार्य में लगी हुई हैं. कंप्यूटर में जिस चिप का इस्तेमाल किया जाता है, उसे सिलिकॉन नाम के सेमीकंडक्टर से बनाया जाता है. सिलिकॉन के अत्यधिक उपयोग की वजह से ही आज यह शहर सिलिकॉन वैली के उपनाम से प्रसिद्ध है. आज सिलिकॉन वैली महज़ एक शब्द नहीं, बल्कि ख़ुद में विकास और समृद्धि का नया नाम बन चुका है. 1991 में भारत सरकार ने भी सिलिकॉन वैली की तर्ज पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की. सॉफ्टवेयर आयात को बढ़ावा देना इस परियोजना का मक़सद था. अब तक पूरे देश में 41 टेक्नोलॉजी पार्क बनाए जा चुके हैं. नोएडा का टेक्नोलॉजी पार्क उन्हीं में से एक है.

ख़ाली केबिनों से हो रहा है करोड़ों का नुक़सान

सूचना क़ानून (आरटीआई) के तहत मिली जानकारी के मुताबिक़, आईटी कंपनियों को रेंट लीज पर पांच साल के लिए केबिन आवंटित किए गए थे. रेंट लीज की समय सीमा भी बढ़ाई गई थी लेकिन, आरटीआई के तहत दिए गए जवाब में नोविप्रा का कहना है कि उसके पास यह जानकारी उपलब्ध नहीं है कि इन कंपनियों ने अपने केबिन क्यों वापस लौटाए या किसी अन्य कंपनी को सब लीज पर दे दिए. लीज होल्ड बेसिस पर आवंटित किए गए सभी केबिनों में भी सन्नाटा पसरा हुआ है. आर. सिस्टम नामक एक कंपनी ने अपना केबिन संख्या 212 शेयर का धंधा करने वाली एक कंपनी को सब लीज पर दे दिया है. जबकि नोविप्रा के लीज डीड नियमों के मुताबिक़ कोई सॉफ्टवेयर कंपनी सिर्फ़ ऐसी कंपनी को ही अपने केबिन सब लीज पर दे सकती है जो सॉफ्टवेयर उद्योग से जुड़ी हो. उधर केबिनों के ख़ाली पड़े होने से प्राधिकरण को करोड़ों रुपये का नुक़सान भी हो रहा है.

कंपनी का नाम	केबिन संख्या	क्षेत्रफल	आवंटन वर्ष	केबिन ख़ाली/ सील होने का वर्ष	मासिक किराया	अब तक हुआ नुक़सान (नवंबर 2000-अक्टूबर 2008 तक)
एल.के सॉफ्टवेयर	395-405, 417-422	650 वर्ग मी.	नवंबर, 94	नवंबर 2001	143000 रु.	11869000 रु.
(395-405 में उत्तर प्रदेश बिक्रीकर विभाग का दफ़्तर चल रहा है. बाक़ी केबिन ख़ाली.)						
डेलसॉफ्ट	301,302,427,428,432	309.54 वर्ग मी.	1995	अक्टूबर 2001	68098.80 रु.	5720299.20 रु.
बिरला सॉफ्ट	423-26,433,435-39, 449-52,456-466, ए1 -ए10, ए12, बी1-बी17	4906.42 वर्ग मी.	1995	2007	1079412.40 रु.	2407072.80 रु.
यूकिया सॉफ्टवेयर	309	51.16 वर्ग मी.	1995	दिसंबर 03	11255.20 रु.	641546.40 रु.
एक्लिप्स सिस्टम	206,207,208	160.7 वर्ग मी.	2001	नवंबर 06	35215.40 रु.	809954.20 रु.
पिपल.कॉम	201,202,209-211,213	----	जुलाई 1998	सभी केबिन ख़ाली	----	----
					कुल नुक़सान	21447872.60 रु.

उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 12 सीटों के साथ, अखिलेश यादव के इस्तीफ़ा देने से ख़ाली हुई फिरोज़ाबाद लोकसभा सीट के लिए भी उपचुनाव हो रहा है. इस सीट पर सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव की पुत्रवधू डिंपल यादव के प्रत्याशी होने से टक्कर ज़ोरदार होने की संभावना है.

मुख्यमंत्री निशंक पर भारी मंत्री कण्डारी

कहते हैं, भ्रष्टाचार की गंगोत्री में एक बार जो नहा ले, उसे कहीं और किसी भी हाल में चैन नहीं आता. अफ़सर तो दाग़ी था ही, मंत्री उससे भी दो हाथ आगे. अब शासन की क्या बिसात कि वह दाग़ियों यानी चोरों, रिश्वतखोरों और सरकारी धन की बंदरबांट करने वालों पर हाथ डाल सके? यही चल रहा है इन दिनों उत्तराखंड में. पेश है एक रिपोर्ट.

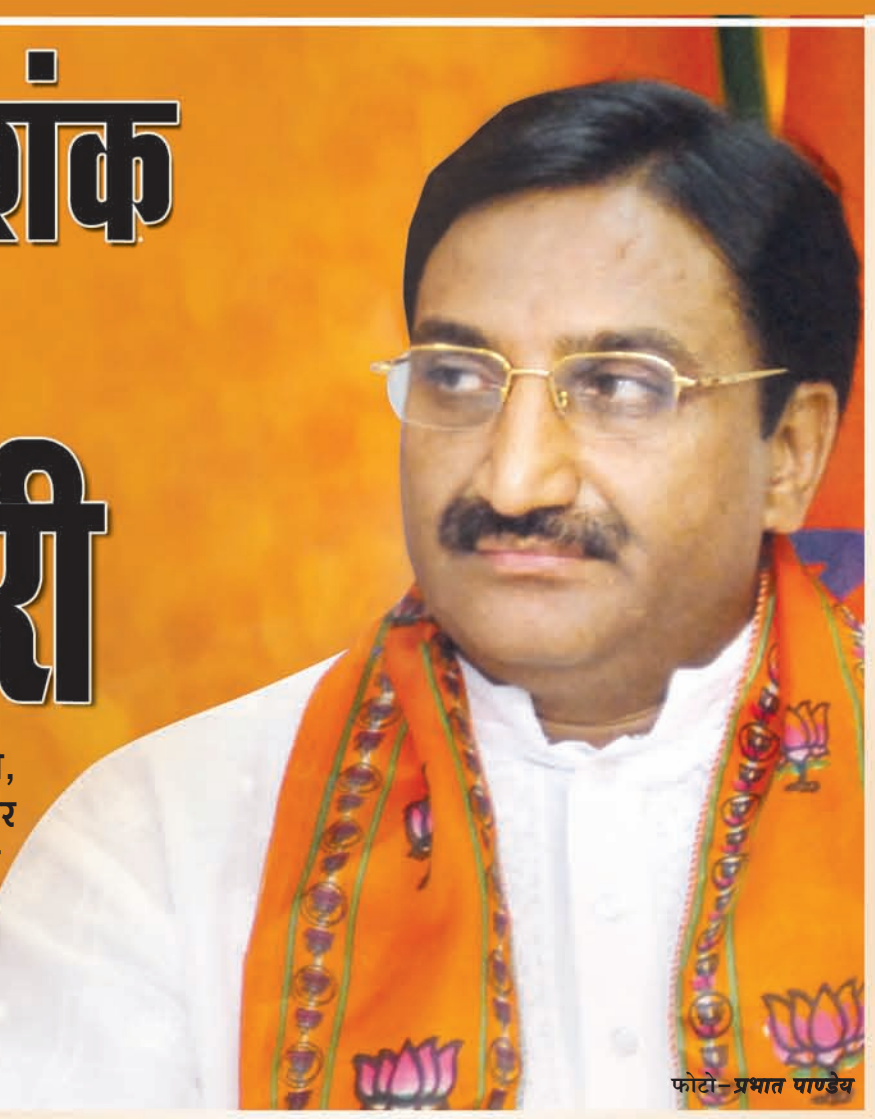

फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

राजकुमार शर्मा

सूबे के मुख्यमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने कभी सपने में भी न सोचा होगा कि उनके कैबिनेट का एक मंत्री ही भ्रष्टाचार विरोधी उनके अभियान के सामने दीवार बनकर आ जाएगा. दशहरे की पूर्व संध्या पर निशंक के इशारे पर सरकार के सचिव द्वारा एक भ्रष्ट अधिकारी के ख़िलाफ़ उठाए गए क़दम मंत्री मातवर सिंह कण्डारी को इतने अखरे कि वह अपनी ही सरकार के विरोध में उतर आए हैं. राजधानी देहरादून में इन दिनों यह प्रकरण ज़ोरों से चर्चा में है.

मालूम हो कि खण्डूरी की विदाई के बाद सत्तासीन हुए निशंक ने शासन को चाकचौबंद करने, जनसामान्य का विश्वास मज़बूत करने, पुलिस को मित्र पुलिस बनाने और निरंकुश नौकरशाही की लगाम कसने के लिए एक अभियान चला रखा है. कुछ भ्रष्ट अधिकारी व दाग़ी मंत्री उनके इस अभियान के निशाने पर हैं. मुख्यमंत्री निशंक अपने विश्वासपात्र चुनिंदा अफ़सरों के साथ अभियान में ज़ोर-शोर से जुटे हुए हैं. मुख्यमंत्री की निगाहें इन दिनों अपनी कार्यशैली के लिए बदनाम लघु सिंचाई विभाग पर हैं, जिसके मुखिया एस ए असगर हैं, जो अक्सर अपने कारनामों के लिए चर्चा में रहते हैं.

एस ए असगर वर्ष 2005 में लघु सिंचाई विभाग के अध्यक्ष रह चुके हैं. उस दौरान भी यहां ख़ाली पदों के सापेक्ष ज़्यादा अभ्यर्थियों का चयन कर करोड़ों रुपये की अवैध कमाई की गई थी. चतुर्थ श्रेणी के आधा दर्ज़न पदों के सापेक्ष 22, आशुलिपिक ग्रेड-2 के पांच पदों के सापेक्ष आठ, कनिष्ठ सहायक के नौ पदों के स्थान पर 18, सहायक बोरिंग टेक्निशियन के 13 पदों के सापेक्ष 32 और चालकों के पांच पदों के सापेक्ष 11 लोग भर्ती किए गए थे. इसके अलावा कनिष्ठ सहायक पद के लिए प्राप्त 1333, आशुलिपिक पद के 303, सहायक बोरिंग टेक्निशियन पद के 417 आवेदनपत्रों को बिना कोई कारण बताए निरस्त कर दिया गया था. इन भर्तियों में उस शासनादेश को भी अनदेखा किया गया, जिसमें आंदोलनकारियों के परिवारजनों को नौकरियों में वरीयता देने की बात कही गई थी. इस मामले को राज्य आंदोलनकारी सम्मान परिषद की सुशीला बलूनी ने सरकार के समक्ष उठाया था.

असग़र कई अन्य मामलों में भी दाग़ी रहे हैं. इन्होंने एचओडी पद पर अपनी डीपीसी कराकर स्थाई तैनाती के लिए तदर्थ सेवा के पांच साल भी जोड़ लिए थे, जबकि पदोन्नति के लिए तदर्थ सेवा का कार्यकाल नहीं जोड़ा जा सकता. एचओडी के लिए कम से कम पच्चीस वर्ष की रेगुलर सेवा ज़रूरी है, लेकिन इस दाग़ी अधिकारी की सेवा मात्र 21 वर्ष है. बतौर ई ई एक्ज़ीक्यूटिव इस पर सोनला हाईड्रम मशीन घोटाले के आरोप साबित हो चुके हैं. उक्त हाईड्रम मशीनें पानी के भीतर लगाई गई थीं, जिसमें लाखों रुपये की हेराफेरी सामने आई थी. इसी तरह इसने रुद्र प्रयाग में भी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए एक्सटेंशन व ट्रेनिंग योजना के तहत वर्ष 2003-04 में तीस की जगह मात्र बीस हाईड्रम मशीनें ही लगाई थीं, जिसकी जांच पूरी हो चुकी है, लेकिन कार्यवाही के लिए मामला शासन स्तर पर अभी तक विचाराधीन है.

इस अधिकारी को राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री मातवर सिंह कण्डारी का खुला संरक्षण प्राप्त है. कण्डारी की गिनती दाग़ी मंत्रियों में होती है. उन पर पटवारी कांड के कथित दोषियों को संरक्षण देने और सरकारी वाहन के दुरुपयोग सहित कई आरोप हैं. मुख्यमंत्री निशंक के इशारे पर ही सिंचाई सचिव विनोद फोनिया ने एस ए असग़र के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू की. फोनिया ने 26 सितंबर की शाम अनु सचिव संजय टोलिया और अधिकारी सत्य प्रकाश को नियुक्ति घोटाले से संबंधित फाइल लेने के लिए एचओडी कार्यालय भेजा. उस समय एचओडी असग़र कार्यालय में अभियंताओं की बैठक ले रहे थे. उन्होंने सचिव के दूतों को पूरी तरह से नकार दिया. यह सूचना पाकर फोनिया स्वयं वहां के लिए रवाना हुए. उनके आने की ख़बर लीक हो जाने से असग़र अफ़रातफरी में कार्यालय का पंखा बंद किए बिना ही रफूचक्कर हो गए. इस तरह की बैठक करने से नाराज़ सचिव ने रात में ही उनके कार्यालय को सील कर दिया. जब पुलिस भेजकर असग़र को बुलवाया गया तो वह अपना घर छोड़ चलते बने.

लघु सिंचाई कार्यालय पर सील लगने की जानकारी होते ही मंत्री मातवर सिंह कण्डारी खुलकर एचओडी के बचाव में उतर आए. उन्होंने मुख्य सचिव को बुलाकर सचिव फोनिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का निर्देश देने के साथ ही विभागीय अधिकारियों को क्लीन चिट भी दे दी. इस बीच मुख्य सचिव के कहने पर विभागाध्यक्ष कार्यालय की सील खोल दी गई है. लेकिन, सचिव विनोद फोनिया और मंत्री मातवर सिंह की लड़ाई अब चरम सीमा पर पहुंच चुकी है. सचिव के सिर पर मुख्यमंत्री का हाथ है. इस संदर्भ में मुख्यमंत्री का कहना है कि ईमानदार को छेड़ेंगे नहीं और भ्रष्टाचारी को छोड़ेंगे नहीं. यह कहकर उन्होंने साफ़ संकेत दे दिया है कि कण्डारी ने अगर समय रहते ख़ुद को नहीं सुधारा तो उन पर किसी भी पल गाज गिर सकती है.

उधर कण्डारी के ख़िलाफ़ विपक्ष ने भी मोर्चा खोल दिया है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष यशपाल आर्य कहते हैं कि कण्डारी द्वारा भ्रष्ट अफ़सर को बचाना यह साबित करता है कि सरकार के हाथ भी भ्रष्टाचार में सने हुए हैं. जब शासन एक भ्रष्ट अधिकारी को दंडित करने का प्रयास कर रहा है तो इसमें किसी मंत्री को कोई दिक़्क़त क्यों हो रही है? मुख्यमंत्री को इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए. समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विनोद बड़थ्वाल का मानना है कि सिंचाई मंत्री को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए. यह कैसी सरकार है जिसमें एक कैबिनेट मंत्री ही दोषी अफ़सर को बचाने में लगा हुआ है और काम करने वाले अधिकारियों को धमकाया जा रहा है. आख़िर निर्धारित पदों से ज़्यादा नियुक्तियां कैसे कर दी गईं? सोनला हाईड्रम पर करोड़ों रुपये कैसे ख़र्च कर दिए गए? कांग्रेस के विधायक दिनेश अग्रवाल का मानना है कि मंत्री और नौकरशाही के बीच टकराव की यह स्थिति राज्य के लिए ठीक नहीं है.

दरअसल, अपने सिर पर मुख्यमंत्री का हाथ होने के चलते ही सचिव फोनिया ने इस मामले में ख़ुद को राम भक्त हनुमान की तरह पेश कर डाला. एक विभागाध्यक्ष की ताक़त जानते हुए भी फोनिया अपने जोश पर क़ाबू न रख सके. मंत्री तक को चेतावनी भरा पत्र लिखने का हौसला रखने वाले फोनिया को ठेंगा दिखाकर एचओडी पहले घर भाग निकला, फिर वहां से कहीं और चला गया. मानो वह कहना चाहता हो कि बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे सचिव.

उधर मुख्यमंत्री ने भी सचिव फोनिया को हनुमान के रूप में पेश कर पहले तो अपनी राम वाली छवि बनानी चाही, किन्तु बाद में दाग़ियों को सबल देखकर उन्होंने हथियार डालना ही उचित समझा. नतीजतन एक दागी मंत्री अपने मुख्यमंत्री पर भारी साबित हो रहा है. सच तो यह है कि दाग़ी मंत्री हो या संतरी, सबने यहां एक ऐसा गठजोड़ बना लिया है जिसके सामने किसी का भी टिक पाना बहुत मुश्किल दिख रहा है.

feedback@chauthiduniya.com

बहुत कठिन है उपचुनाव की डगर

सुरेंद्र अग्निहोत्री

उत्तर प्रदेश में आगामी नवंबर माह में होने वाले उपचुनाव के लिए सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं. इसके तहत विधानसभा की 12 और लोकसभा की एक सीट के लिए मतदान होगा. फिरोज़ाबाद संसदीय सीट समाजवादी पार्टी के अखिलेश सिंह यादव द्वारा त्यागपत्र देने से ख़ाली हुई है. यहां से अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव पहली बार मैदान में उतर कर अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर रही हैं. सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने कल्याण सिंह की मौजूदगी में डिंपल यादव को फिरोज़ाबाद के सियासी दंगल में उतारा है. मुलायम सिंह ने कहा कि कभी हमारे समर्थन से लड़ने वाले लोग डिंपल को हराने के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं. उनका इशारा कांग्रेस प्रत्याशी राजबब्बर की ओर था, जो फिरोज़ाबाद में फ़िलहाल सबसे आगे दिख रहे हैं. सपा को उसके गढ़ में उसी के पूर्व साथियों को लेकर कांग्रेस और बसपा पहली बार खुली चुनौती दे रही हैं.

फोटो–*पीटीआई*

उपचुनाव में मुख्य लड़ाई बसपा, कांग्रेस और सपा के बीच मानी जा रही है. कांग्रेस का उद्देश्य झांसी और देवरिया की अपनी रिक्त हुई सीटों पर फिर से विजय हासिल करने के साथ-साथ 2012 में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले अपनी ताक़त का आकलन करना है. सपा को अपने हुए बेगाने के चलते रिक्त हुई सीटें जीतनी ज़रूरी हैं.

सबकी नज़रें लोकसभा से अधिक 12 विधानसभाई सीटों के उपचुनाव पर लगी हैं. भाजपा हाईकमान द्वारा लखनऊ पश्चिम विधानसभा सीट के लिए अमित पुरी को प्रत्याशी घोषित करते ही शहर में भाजपा के दो गुट बन गए थे, तमाम विरोध के बावजूद जब नेतृत्व ने प्रत्याशी नहीं बदला तो कार्यकर्ता चुपचाप चुनाव की तैयारियों में जुट गए. महानगर भाजपा अध्यक्ष प्रदीप भार्गव की अध्यक्षता में रणनीति तय की गई. संगठन महामंत्री नागेंद्र नाथ ने कहा कि पार्टी का निर्णय हमारे लिए सर्वमान्य है. ग़ौरतलब है कि लखनऊ की यह सीट लालजी टंडन के सांसद बनने से ख़ाली हुई थी.

उपचुनाव में मुख्य लड़ाई बसपा, कांग्रेस और सपा के बीच मानी जा रही है. कांग्रेस का उद्देश्य झांसी और देवरिया की अपनी रिक्त हुई सीटों पर फिर से विजय हासिल करने के साथ-साथ 2012 में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले अपनी ताक़त का आकलन करना है. सपा को अपने हुए बेगाने के चलते रिक्त हुई सीटें जीतनी ज़रूरी हैं. इन सीटों को हारने का मतलब उसका हाशिए पर जाना समझा जाएगा. उधर बसपा हर हाल में 12 में से 10 सीटें जीतना चाहती है. वह इसके लिए हर टोना-टोटका आज़मा रही है. उसने लखनऊ और कोसला विधानसभा उपचुनाव के लिए पूर्व में घोषित अपने प्रत्याशी बदल दिए हैं. झांसी में भी प्रत्याशी बदलने की चर्चा ज़ोरों पर है. कांग्रेस नौ प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, लेकिन तीन सीटों पर अभी तक वह अपने प्रत्याशी तय नहीं कर पाई है. भाजपा की हालत विचित्र है. उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वह किस ओर जाए.

प्रदेश में विकास की गति रुक गई है. सचिवालय में सन्नाटा पसरा हुआ है. मुख्यमंत्री मायावती का सारा ध्यान हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव पर है. सूबे के मंत्री अपनी पार्टी को जिताने के लिए कमर कस चुके हैं. इस बार अनेक बसपा नेता अपने प्रतिद्वंद्वियों के साथ-साथ दोस्तों से भी लोहा ले रहे हैं, क्योंकि अंतिम समय में बसपा सुप्रीमो द्वारा प्रत्याशी बदल देने से कई अपने ही दुश्मन बन बैठे हैं. इसलिए इस बार बुंदेलखंड के उपचुनाव बहुत कठिन है डगर पनघट की, वाले हो गए हैं. एक कहावत है – *झांसी गले की फांसी, दतिया गले का हार. ललितपुर न छोड़िए, जब तक मिले उधार.* लेकिन, उधार के लोगों को अभी तक अपना भाग्य विधाता बनाती रही ललितपुर की जनता ने आगामी विधानसभा उपचुनाव में इस बार यहीं के मूल निवासी को ही बतौर प्रतिनिधि भेजने के पोस्टर लगाकर सबको सकते में डाल दिया है. बुंदेलखंड की झांसी और ललितपुर सदर विधानसभा सीट जीतने के लिए सत्तारूढ़ बसपा ने पूरी ताक़त झोंक दी है. लगभग एक दर्ज़न मंत्री झांसी और ललितपुर में लगे हुए हैं. ललितपुर विधानसभा सीट बसपा विधायक नाथूराम कुशवाहा के निधन से ख़ाली हुई थी. इसे हर हाल में जीतने का लक्ष्य रखा गया है. वहीं दूसरी ओर तीन दशक से ललितपुर की राजनीति में सिरमौर रहे बुंदेला परिवार की दूसरी पीढ़ी के चंद्रभूषण सिंह बुंदेला यहां से अपनी राजनीतिक पारी सपा उम्मीदवार के रूप में शुरू कर रहे हैं. लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को ललितपुर विधानसभा में मिली बढ़त के बाद त्रिकोणीय संघर्ष होना तय है.

झांसी में कांग्रेस के लिए प्रदीप जैन आदित्य के सांसद बनने से ख़ाली हुई सीट पर अपना क़ब्ज़ा बरकरार रखने की चुनौती है. यहां सपा का प्रत्याशी कमज़ोर होने के कारण कांग्रेस और बसपा में ही सीधी टक्कर होने की संभावना है. बसपा विद्रोही ब्रजेंद्र व्यास के निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में आने से भाजपा भी मज़बूती के साथ उतर रही है. बुंदेलखंड के विकास के लिए राहुल गांधी की पहल पर बनने वाले प्राधिकरण के विरोध का ख़ामियाज़ा भी इस चुनाव में बसपा को यहां भुगतना पड़ सकता है. सूखे की मार से जूझ रहे बुंदेलखंड में भूख से मौत जैसे कई मुद्दे सुर्ख़ियों में हैं. केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य के लिए यह उपचुनाव अग्निपरीक्षा के समान है. बुंदेलखंड में भारतीय जनता पार्टी के सामने भी कम चुनौतियां नहीं हैं. बसपा ने काबीना मंत्री दद्दू प्रसाद को ललितपुर और नसीमुद्दीन सिद्दीकी को झांसी की कमान सौंपी है. झांसी से कैलाश साहू और ललितपुर से दिवंगत बसपा विधायक की पत्नी सुमन कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया गया है. जखौरा की लीलादेवी कहती हैं, *अगर थोरो भौत पड़सा अपन के गांव में आतौ तो सड़कन को उद्धार हुइयै, कुछ कराऔ नईयां नेतन ने. चुनाव जी लऔ फिर दिखवो नसीब नइयां.*

feedback@chauthiduniya.com

26 सितंबर को लालगढ़ के पास से पत्रकार के वेश में छत्रधर की गिरफ़्तारी ने एक नई बहस छेड़ दी है. कोलकाता प्रेस क्लब ने मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृहमंत्री को पत्र लिखकर अपना विरोध जताया है.

माओवादियों का एक मोहरा भर है छत्रधर

बिमल राय

पुलिस कुछ न करे तो मुश्किल, कर गुज़रे तो और ज़्यादा मुश्किल! माओवादियों के मोहरे छत्रधर की गिरफ़्तारी इसका जीता जागता प्रमाण है. यह दोहरापन आख़िर हमें कहां ले जाएगा?

हाल ही में लालू प्रसाद यादव जब कोलकाता आए और उन्होंने पश्चिम बंगाल को नक्सलवाद की जननी बताया तो इसमें रहस्योद्घाटन जैसा कुछ भी नहीं था. सब जानते हैं कि सिद्धार्थ शंकर राय की कांग्रेसी हुकूमत में ही इस विषधर ने फन फैलाया था और आज एक-एक कर छह राज्यों में इसकी जड़ें फैल चुकी हैं. यह भी एक संयोग है कि आज केंद्र में कांग्रेस की ही सरकार है, जिसने माओवाद, लिबरेशन और दूसरे नामों से लगातार मज़बूत हो रहे इस अतिवाद को कुचलने के लिए कड़े क़दम उठाने को हाल ही में मंजूरी दी है. इन कड़े क़दमों की कामयाबी को हमें देखना है, पर जहां तक बंगाल का सवाल है, इसमें पेंच ही पेंच नज़र आ रहे हैं. क्योंकि, यहां एक तरफ़ आदिवासियों का हित देखने वाले अतिसक्रिय बुद्धिजीवी व मानवाधिकारवादी हैं तो दूसरी तरफ़ तृणमूल कांग्रेस जैसी पार्टी, जो 2011 में राज्य की सत्ता पर क़ाबिज़ होने की धुन में छत्रधर महतो जैसे लोगों को आदिवासियों का प्रतिनिधि मानकर इस राष्ट्रीय त्रासदी पर ढुलमुल रवैया अपनाने पर मजबूर हुई है.

26 सितंबर को लालगढ़ के पास से छत्रधर की गिरफ़्तारी के बाद पूर्वी इलाक़ा एक बार फिर अशांत हुआ. माओवादियों ने दो अक्टूबर को 24 घंटे के भारत बंद का आह्वान किया. झारखंड के सिंहभूम और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में रेल पटरियां उड़ाने जैसी हिंसक वारदातें भी हुईं. हालांकि बंगाल से ज़्यादा असर झारखंड में हुआ. माओवादियों ने दो पुलिसकर्मियों को बंधक बना लिया. पश्चिम मिदनापुर और पुरुलिया ज़िलों में ज़मीनी स्तर पर कोई आंदोलन न दिखने पर राज्य सरकार छत्रधर को काग़ज़ी नेता मानकर ख़ुश है. इधर, माओवादी जिस तरह छत्रधर का बचाव कर रहे हैं, उससे दोनों के बीच के रिश्तों में संदेह नहीं रह गया है. हक़ीक़त तो यह है कि यह आदिवासी नेता पूरी तरह माओवादियों के निर्देश पर ही चल रहा था. अवैध गतिविधियां निरोधक अधिनियम के तहत हुई गिरफ़्तारी के बाद छत्रधर ने सीआईडी के सामने कथित तौर पर जो ख़ुलासे किए हैं, उससे भी काफी कुछ पता चला है.

छत्रधर महतो को गिरफ़्तार कर ले जाती पुलिस.

छत्रधर के मुताबिक़, लालगढ़ के 400 युवकों को माओवादियों ने प्रशिक्षण दिया है. 14 से 25 साल के इन युवकों को पिंगबनी, कादासोल और झिटका के जंगलों में प्रशिक्षण दिया जाता था. महतो ने यह भी माना कि वह पहले माओवादियों का प्रवक्ता था. यह भी पता चला है कि छत्रधर माओवादी नेता शशधर का भाई है, जो पिछले साल नवंबर में मुख्यमंत्री के क़ाफ़िले पर हमले से पहले लालगढ़ आता भी था. विस्फोट के बाद जब पुलिस ने दो स्कूली बच्चों को गिरफ़्तार किया तो इससे उपजे आक्रोश को भुनाने के लिए उसने पुलिस अत्याचार के ख़िलाफ़ जन संघर्ष समिति बनाने का फ़ैसला किया. महतो ने यह भी बताया कि माओवादियों के बड़े नेता किशन जी और विकास किन-किन गांवों में ठहरे. हालांकि, उसने उन गांव वालों के नाम नहीं बताए हैं. ये ख़ुलासे काफी नहीं हैं, क्योंकि विकास और किशन जी अभी भी पकड़ से बाहर हैं. सीआईडी के सामने सबसे बड़ी बाधा यही है कि छत्रधर के ख़िलाफ़ उसे गवाह नहीं मिल रहे हैं. बताया जाता है कि माओवादियों के भय से छत्रधर ने सिर्फ़ छिटपुट जानकारियां दी हैं और आगे कुछ भी बताने से इनकार कर दिया है.

पत्रकार के वेश में छत्रधर की गिरफ़्तारी को लेकर राज्य में ही नहीं, पूरे देश में एक नई बहस शुरू हो गई है. नंदीग्राम से लालगढ़ तक सरकार की रणनीति की लगातार आलोचना करने वाले घटक दलों ने भी पुलिस के तरीक़े का बचाव किया है. माकपा नेता रबिन देव ने तो साफ़ कहा कि इसमें बुराई क्या है? सवाल यह उठता है कि जिस आदमी को पकड़ने के लिए सुरक्षा बल महीनों से लगे हुए थे, उससे कई पत्रकार निर्भय होकर कैसे इंटरव्यू ले रहे थे? पुलिस द्वारा सिंगापुर से आए पत्रकारों का वेश धरने पर प्रेस बिरादरी भी भड़की. कोलकाता प्रेस क्लब ने केंद्रीय गृहमंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर अपना विरोध जताया. उसका कहना था कि इससे पत्रकारों में असुरक्षा की भावना तो पैदा हुई ही है, उनके पेशे की भी बदनामी हुई है. पुलिस ने एक स्थानीय पत्रकार को विश्वास में लेकर अपने ऑपरेशन को अंजाम दिया. आरएसपी नेता क्षिति गोस्वामी का कहना था कि लक्ष्य को देखते हुए उसे हासिल करने के तरीक़े को अनुचित नहीं ठहराया जा सकता. पुलिस हमेशा से छद्म वेश में अपराधियों को पकड़ती रही है.

सच कहें तो पुलिस के पास कोई और चारा नहीं था. हमारी राजनीतिक-सामाजिक व्यवस्था के तीन स्तंभों नेता, पुलिस और पत्रकार में से पहले के दो महारथी फेल हो गए थे. तीन-चार महीने के लालगढ़ अभियान के बाद भी राज्य सरकार यह कहने की हालत में नहीं आई कि हालात क़ाबू में हैं. लगातार माकपा काडरों की हत्याएं होती रहीं. विकास का काम ठप रहा. सुरक्षाबलों को निराशा घेरने लगी. इन हालात में पुलिस ने छत्रधर को पकड़ कर माओवादियों के एक मोहरे को कमज़ोर कर दिया है. छत्रधर की गिरफ़्तारी के बाद माओवादी नेता किशन जी की प्रतिक्रिया थी कि सरकार लालगढ़ में हुई ज़्यादतियों को ढंकने के लिए उस पर यह आरोप लगा रही है. उन्होंने इस दावे का भी खंडन किया कि छत्रधर के पास एक करोड़ रुपये की जीवन बीमा पॉलिसी, भारी भरकम बैंक बैलेंस और अकूत संपत्ति है. उन्होंने ललकारा भी कि अगर ऐसा है तो पुलिस संपत्ति को जब्त करे और उसके काग़ज़ात सार्वजनिक करे. मुख्य सचिव अशोक मोहन चक्रवर्ती ने अप्रत्यक्ष रूप से उन कलाकारों एवं बुद्धिजीवियों को धमकाया है, जो हाल ही में छत्रधर से मिलने लालगढ़ गए थे. उनका बयान है कि प्रतिबंधित संगठन से किसी भी तरह का संबंध रखने और उसे मदद पहुंचाने वाले लोगों के ख़िलाफ़ अवैध गतिविधि अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी. हालांकि, इस बयान के बाद तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी ने कलाकारों एवं बुद्धिजीवियों का बचाव करते हुए सरकार को आग से न खेलने की सलाह दी है. कलाकारों एवं बुद्धिजीवियों ने भी धमकी की परवाह न करते हुए कोलकाता में एक रैली निकाली और महतो की गिरफ़्तारी का पुरजोर विरोध किया.

छत्रधर के पकड़ में आने के बाद देश में नक्सली हिंसा की दो बड़ी वारदातें हुई हैं. पहली वारदात बिहार के खगड़िया में और दूसरी वारदात महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में हुई, जिसमें 17 पुलिसकर्मियों की जान गई. इन हत्याओं के बाद आम आदमी में भी माओवादियों के ख़िलाफ़ गुस्सा और भड़का है तथा छत्रधर जैसे मोहरों पर भी. माओवादियों के ख़ात्मे के लिए केंद्र का हालिया बना एक्शन प्लान क्या माओवाद की राजनीतिक जड़ों को काट पाएगा, जिसके बूते छत्रधर जैसे लोग रातोंरात हीरो बना दिए जाते हैं?

feedback@chauthiduniya.com

spice
www.spice-mobile.com
अब सब खल्लास!
मल्टी-सिम M-4580 की आकर्षक कीमत और भरपूर खूबियाँ करे सबको खल्लास।

M-4580
किलर खूबी: बड़ी बैट्री
25 दिनों का स्टैंड-बाइ टाइम और 10 घंटों का टॉकटाइम
मल्टी-सिम (GSM/GSM)
MP3 प्लेयर और FM रिकार्ड
वन-टच टॉर्च और करैन्सी चेकर
4 GB तक एक्सपैन्डेबल मैमोरी
BEST BUY PRICE: Rs. 2149

M-5252
10 दिनों का स्टैंड-बाइ टाइम और 4 घंटों का टॉकटाइम
मल्टी-सिम (GSM/GSM)
डिजिटल कैमेरा
बिल्ट-इन FM एंटेना
ड्यूअल LED टॉर्च
8 GB तक एक्सपैन्डेबल मैमोरी
BEST BUY PRICE: Rs. 3049

C-5300
सभी CDMA कनेक्शन के साथ चले
बड़ी स्क्रीन
डिजिटल कैमेरा
MP3 प्लेयर और FM रिकार्ड
एक्सपैन्डेबल मैमोरी
वन-टच टॉर्च
BEST BUY PRICE: Rs. 2999
बड़ी स्क्रीन | बड़ी मैमोरी | बड़ा साउण्ड | बड़ी बैट्री
big series
Spice Mobiles come loaded with:
emergic email2sms Mail on Mobile | Shuffle Ring tone | mGurujee | ibibo i build · i bond | REUTERS | Mobile Tracker
Registered Office: Spice Mobiles Ltd., D-1, Sector-3, Noida 201301, Uttar Pradesh, India. Fax: +91-120-4363845. E-mail: contactus@spicemobile.in. Spice Mobile Phones are available at all leading telecom outlets. *Conditions apply. Price features and specifications are subject to change without prior notice. Some of the listed capacity is used for phone functions and thus available capacity could be less than the quoted figure. Battery operation time may vary depending on network usage, environment, music and video formats.
www.itsaugust.com

डॉक्टर भी हमारी और आपकी तरह एक इंसान हैं. जब हम सबसे कहीं न कहीं भूल हो जाती है तो उनसे ऐसा क्यों नहीं हो सकता? और, फिर क्यों हम विभिन्न मंचों पर उनके ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं?

नस्लवाद हमेशा से एक बहुत बड़ी समस्या रहा है. इससे बचाव के लिए जरूरी है कि समाज का हर सदस्य हर समय अपनी आंखें चौकन्ना रखे.

एम जे अकबर

हक़ीक़त हैं, जिन्ना में जादू था

यह बेहद दिलचस्प है कि 1947 के छह दशक बाद भी दिल्ली और मुंबई में जिन्ना पर यदि बहस हो तो पूरा हॉल भर सकता है, जबकि गांधी पर किसी तरह की चर्चा हो तो सबसे अगली पंक्ति भरने में भी संदेह है. क्या ऐसा सिर्फ़ इसलिए कि जिन्ना मुक़दमों की सुनवाई के दौरान अभियोजन या बचाव पक्ष के वकील के तौर पर वक्ता के रूप में नाटकीयता पेश करते हैं और श्रोता चुपचाप सुनते रहते हैं. लेकिन, आख़िरकार निर्णायक तो जूरी ही होता है? जिन्ना अपने समय के एक महान बैरिस्टर थे और उन्हें उपर्युक्त बातें बेहद ही पसंद आई होंगी.

क्या गांधी हमारे अवचेतन में एक चिड़चिड़े स्वभाव, हमारी अंतरात्मा के दर्पण में एक अपराध बन गए हैं? भला यह कौन चाहता होगा कि उसकी तुलना संत के मानदंडों से की जाए, वह भी तब, जबकि उसने अपनी आत्मकथा में बड़ी ढिठाईपूर्वक ईमानदारी से अपने अपराधों को क़बूला हो? वहीं दूसरी तरफ़ जिन्ना निजता पसंद शख्स थे. यहां तक कि वह अपनी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को छुपाकर रखना पसंद करते थे. उनकी किसी भी हक़ीक़त को जानने के लिए असंख्य पोस्टमॉर्टम की ज़रूरत पड़ती. गांधी बहुत ही जल्द एक आदर्श बन गए. हम जिन्ना की स्मृतियों को तो परेशान कर सकते हैं, लेकिन गांधी की स्मृतियां हमें परेशान करती हैं.

> यदि गांधी अभी जीवित होते तो 2 अक्टूबर 2009 को अपने 140वें जन्मदिन पर कहां होते? बेशक, वह महाराष्ट्र में अनशन कर रहे होते. आख़िर क्यों? यदि आंकड़ों के मुताबिक़ देखें तो राज्य पुलिस का आम नागरिक जीवन में दख़ल पहले की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ा है, जो बेहद ही आक्रोशित करने वाला है.

यदि गांधी अभी जीवित होते तो 2 अक्टूबर 2009 को अपने 140 वें जन्मदिन पर कहां होते? बेशक़, वह महाराष्ट्र में अनशन कर रहे होते. आख़िर क्यों? यदि आंकड़ों के मुताबिक़ देखें तो राज्य पुलिस का आम नागरिक जीवन में दख़ल पहले की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ा है. जो बेहद ही आक्रोशित करने वाला है. महाराष्ट्र में पिछले पांच वर्षों में औसतन हर बीस दिन में दंगे होते रहे हैं. प्रिंट मीडिया ने इस ख़बर को बस दो पैराग्राफ़ में ही निपटा दिया. टेलीविज़न ख़ास हस्तियों के साथ चर्चे में ही मशगूल रहा और इस तरह उसने अहम मुद्दे को ही पूरी तरह नकार दिया. ऐसा लगता है कि हमारे असंख्य धर्मनिरपेक्ष संरक्षकों को अपने गुस्से के इज़हार के लिए एक परिचित ख़लनायक की ज़रूरत है. वैसे भी, अनाम हिंसा किसी भी लिहाज से आकर्षक नहीं होती है.

गांधी ने हमेशा ही हिंसात्मक तथ्यों की जगह राजनीति के संघर्षों को अधिक तरजीह दी और आज जो भी लोभ-लालच की ढोंग भरी ज़िंदगी जी रहे हैं, उन सभी को गांधी के सामने खड़ा होने में भी असहजता महसूस होती है. साथ ही आधुनिक भारत के नायक उन्हें समझ भी नहीं पाएंगे. सेंसेक्स में उछाल की ख़ुशी और हर पांचवी शाम निवेश पोर्टफोलियो के प्रतीक रूप में गांधी को स्थापित करने का कोई उपाय ही नहीं है. इसलिए हर कोई अपनी समझ से उनके पोट्रेट को सरकारी कार्यालयों की दीवार पर टांग देता है.

इसके बिल्कुल उलट जिन्ना की समस्या रही है कि वह निहित स्वार्थों की श्रेणी में उपयुक्त या अनुपयुक्त बने रहे. हर किसी ने जिन्ना को अपने खांचे में बांधना चाहा, ताकि उनका स्वार्थ पूरा हो सके. पाकिस्तान के राजनीतिक बुद्धिजीवी भी उनकी धर्मतंत्र की संस्कृति से समझौता करने पर मजबूर हो गए. वह लंदन में 200 सूट के मालिक से एक दुबले-पतले, सौम्य सलवार-कुर्ते वाले शख्स में बदल गए. क्लीन शेव की जगह यदि उन्होंने फैशनेबुल हल्की दाढ़ी भी रखनी शुरू कर दी होती तो उनको आधिकारिक पोट्रेट में छह इंच लंबी दाढ़ी में दिखाया गया होता. आज अधिकांश पाकिस्तानी यह जानकर बेहद आश्चर्यचकित है कि जिन्ना उर्दू नहीं जानते थे, रमजान के दौरान उन्होंने कभी रोजा नहीं रखा, साथ ही धार्मिक रीति-रिवाजों में उनकी बहुत ही कम दिलचस्पी थी और उनकी आध्यात्मिक निर्वाह की अवधारणा वाक़ई में सांसारिक थी. जिन्ना ने नए देश के निर्माण के दिन यानी 14 अगस्त 1947 को माउंटबेटन के स्वागत सम्मान में औपचारिक भोज का निमंत्रण दिया. उनमें से किसी को यह अहसास हुआ कि कम से कम रमजान के दौरान तो भोज की व्यवस्था रद्द होनी चाहिए. हालांकि जिन्ना इस बात से पूरी तरह बेख़बर थे कि मुसलमान तीन सप्ताह तक रोजा रखते हैं.

भारतीय राजनीतिज्ञों ने जिन्ना को और भी सूक्ष्मता से प्रतिबंधित किया. तत्कालीन कांग्रेसियों को एक कार्ड बोर्ड जिन्ना की ज़रूरत थी, ताकि वे विभाजन के गुनहगार के तौर पर किसी ख़लनायक की तलाश कर सकें. भारतीय विद्यालयों के इतिहास की किताबों में उन्हें एक सांप्रदायिक, जिद्दी और घृणा के पात्र के तौर पर दिखाया गया. यह तब के हालात से और भी अधिक घातक था. जब जिन्ना की उपयोगिता पाकिस्तान के क़ायदे आजम के रूप में कम होने लगी, तब उन्हें भारतीय मुसलमानों के गुनहगार के प्रतीक रूप में बदल दिया गया और वे भारतीय राष्ट्रवाद के अपराधी के रूप में हर लिहाज से चर्चित हो गए. भारतीय जनसंघ (आज की भारतीय जनता पार्टी) ने जबसे अलगाव और सांप्रदायिकता की राजनीति शुरू की तो उसने बड़े उत्साह से इसे अपना भावी लक्ष्य बनाया. इस संदर्भ में भारतीय मुसलमान अनुवांशिक तौर पर ग़ैर-देशभक्त ठहरे और उन्होंने इस दोयम दर्ज़े की नागरिकता की आलोचना की. जब जसवंत सिंह ने अकादमिक लेखागार की मदद से इस एकतरफ़ा धारणा को चुनौती दी और सार्वजनिक तौर पर इसका मुक़ाबला किया तो बदले में उन्हें पार्टी से ही निकाल दिया गया. हिंदू और साथ ही वे लोग जो इस अधूरी सच्चाई से परेशान थे, उन्होंने इस अपराध को दूसरों तक फ़ैलाया.

धर्मनिरपेक्ष पार्टियां, जिनके महारथी वोट बैंक को आकर्षित करने में अव्वल हैं, उन्होंने यह बहुत जल्द ही समझ लिया कि भारतीय मुसलमानों का वोट हासिल करने का सबसे आसान ज़रिया है उन्हें भयभीत करना. अतीत और विभाजन का ही नतीजा है भविष्य का भय. मुसलमानों के पास सिर्फ़ दो ही विकल्प थे, सांप्रदायिक पिंजरा और धर्मनिरपेक्षता का जाल. इनमें से एक में उन्हें खाने के लिए दलिया मिलता है तो दूसरे में पनीर. छह दशक बाद भारतीय मुसलमान पिंजरे और जाल दोनों के ही दरवाज़ों में बंद होने जा रहे हैं.

महात्मा गांधी यह फरियाद ज़रूर सुन रहे होंगे.

feedback@chauthiduniya.com

जब तोप मुक़ाबिल हो

संतोष भारतीय

तालिबान को जनता का समर्थन नहीं

पाकिस्तान के लोग समझदार हैं, इसलिए बातें ज़्यादा बताने वाली नहीं हैं लेकिन वहां की सरकार क्यों समझदार नहीं है, इस पर आश्चर्य है. राज्य की सत्ता के कुछ प्रतीक होते हैं, जिन पर आंच आने का मतलब राजसत्ता पर आंच आना माना जाता है. कोषागार, जेल, सेना मुख्यालय और राजभवन ऐसी ही जगहें हैं जिन पर हमला होने का मतलब इन्हें चुनौती देना होता है. पाकिस्तान में सेना पर छुटपुट हमले होते रहे हैं, स्वात और वज़ीरिस्तान में सेना का मुक़ाबला भी होता रहा है पर सेना मुख्यालय पर हमलों की शुरुआत ख़तरनाक संकेत मानना चाहिए. लाहौर में ट्रेनिंग सेंटर पर हमला हुआ था जिसे लेकर पाकिस्तान के नागरिक बहुत चिंतित हुए थे, और अब यह नई शुरुआत.

पाकिस्तान एक अजीब कशमकश में दिखाई दे रहा है. एक ओर इतनी ग़रीबी है कि वहां आटा और रोटियां बांटनी पड़ रही हैं, जिसमें बंटवारे के दौरान हादसे होते हैं और लोग मारे जाते हैं. आतंकवाद इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि लगभग हर रोज़ कहीं न कहीं धमाका होता है और दस से बीस जानें जाती हैं. लाहौर में हर कालोनी में प्राइवेट गार्ड बड़ी संख्या में सोफेस्टीकेटेड हथियारों के साथ दिखाई पड़ जाते हैं. पंजाब को अब वहां की ख़ुफ़िया एजेंसी स्वात की तरह देखने लगी है. बेरोज़गारी ने आतंकवाद को फैशन और अराजकता और लूटपाट को ज़िंदा रहने का तरीक़ा बना दिया है. कराची अराजकता का सबसे अच्छा उदाहरण है. अगर कोई पाकिस्तान के देहातों में जाना चाहे तो उससे कहा जाता है कि सिक्यूरिटी लेकर ही उसे जाना चाहिए.

तीसरी ओर पाकिस्तान सरकार अपनी कमज़ोरी से पैदा होने वाली समस्याओं का ज़िम्मेदार बाहरी देश को बता देती है. पाकिस्तान की शब्दावली में बाहरी देश का मतलब भारत से है. सेना मुख्यालय पर हमला हुआ, तहरीके तालिबान ने ज़िम्मेदारी भी ले ली पर पाकिस्तान सरकार के गृहमंत्री ने कह दिया कि आतंकवादी घटना के पीछे बाहरी देश का हाथ है. पाकिस्तान सरकार आतंकवाद के ख़तरे का सामना ज़रूर कर रही है, लेकिन वह उसे समाप्त करने की जगह बनाए रखना चाहती है. उसकी कोई लड़ाई आतंकवाद को ख़त्म करने की ओर नहीं जाती. वज़ीरिस्तान में अलक़ायदा है जिसकी मदद से तालिबान स्वात, मनेर और अब पंजाब की ओर तेज़ी से बढ़ रहे हैं. कहते हैं कि कराची और लाहौर तालिबान के बड़े नेताओं की शरणस्थली तो है ही, उनका समर्थन भी तेज़ी से बढ़ रहा है. एक ओर पाकिस्तान की सेना, हथियार बंद तालिबानियों से जगह-जगह लड़ती नज़र आती है पर दूसरी ओर पाकिस्तानी सरकार उन राजनैतिक नेताओं को खुला छोड़े हुए है जो तालिबानी विचारधारा पर आधारित संगठनों के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं. यह अंतर्विरोध है जिसे आज पाकिस्तान की सरकार अनदेखा कर रही है और अपने लिए स्वयं ख़तरा पैदा कर रही है.

> पाकिस्तान की जनता की हिम्मत की दाद देनी चाहिए, जो इस माहौल के ख़िलाफ़ खड़ी हो रही है. तालिबानी संस्कृति के ख़िलाफ़ पाकिस्तानी औरतें प्रदर्शन कर रही हैं और जुलूस निकाल रही हैं. लड़कियां तालिबानी धमकियों को अनदेखा कर रही हैं और शालीन आधुनिक कपड़े पहनने की हिम्मत कर रही हैं. वहां के लेखक, डॉक्टर, वकील और आम लोग इस जाल से निकलना चाहते हैं.

पाकिस्तान की जनता की हिम्मत की दाद देनी चाहिए, जो इस माहौल के ख़िलाफ़ खड़ी हो रही है. तालिबानी संस्कृति के ख़िलाफ़ पाकिस्तानी औरतें प्रदर्शन कर रही हैं और जुलूस निकाल रही हैं. लड़कियां तालिबानी धमकियों को अनदेखा कर रही हैं और शालीन आधुनिक कपड़े पहनने की हिम्मत कर रही हैं. वहां के लेखक, डॉक्टर, वकील और आम लोग इस जाल से निकलना चाहते हैं. वहां के नौजवानों में इमरान ख़ान को लेकर ख़ासा उत्साह है, हालांकि इमरान ख़ान को राजनैतिक तौर पर कभी सफलता नहीं मिली. वहां के नौजवानों का कहना है कि उनकी चुनाव प्रणाली इतनी भ्रष्ट और ख़र्चीली है कि उसमें कोई सही राजनैतिक ताक़त पनप ही नहीं सकती.

हमारी जानकारी बताती है कि पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी अब खुल कर पिछड़ेपन, जहालत और तालिबानी दिमाग़ के ख़िलाफ़ खड़ी हो रही है. वे मौलाना या मौलवी जो सही बात कह रहे हैं, उनकी हत्याएं पाकिस्तान में तालिबानियों द्वारा की जा रही हैं, लेकिन इसके बाद भी ऐसी संख्या मौलवियों की बढ़ रही है जो कुरान शरीफ का सही मतलब लोगों को बता रहे हैं.

पाकिस्तान में मज़हब की व्याख्या भी दो तरह की हो रही है. एक वह जो कट्टरता और अंधेरेपन की ओर ले जाती है, दूसरी वह जो हज़रत मोहम्मद पैगम्बर साहब की व्याख्या को उसके अर्थ के साथ आम आदमी को रोशनी देती है. दोनों ही बातें मौलवी ही कहते हैं, पर जो मौलवी हज़रत साहब की बातें कहते हैं उनकी हत्याएं बताती हैं कि उनकी बातों से उन्हें ख़तरा पैदा हो जाता है जो मज़हब की, कुरान शरीफ की मनमानी व्याख्या करते हैं.

पाकिस्तान की सरकार नागरिक ताक़त के साथ खड़ी दिखाई नहीं देती. वह विकास के, रोज़गार बढ़ाने के काम कम कर रही है, अपने लिए समस्याएं बढ़ाने का काम ज़्यादा कर रही है. उसे चाहिए कि वह अपने नागरिकों को ग़लत जानकारी न दे, क्योंकि आज संचार और सूचनाओं की दुनिया इतनी खुली हुई है कि सही ग़लत का पता बहुत जल्दी चल जाता है.

मज़े की बात है कि पाकिस्तान सरकार की तरह ही भारत की सरकार भी समस्याओं की अनदेखी करती नज़र आ रही है. किसी भी देश की सरकार को केवल पांच साल के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि अगले बीस सालों को ध्यान में रख योजनाएं बनानी चाहिए. और यही नहीं हो रहा. हम देखते हैं कि सड़क बनी, अगले साल चौड़ी की जा रही है. पुल बना, पर वाहनों का बोझ नहीं उठा पा रहा. फ़सल पैदा हुई, भाव नहीं मिला. रोज़गार के अवसर कम से कम होते जा रहे हैं. ग़रीब और दलित अशांत हो रहे हैं. वहीं अल्पसंख्यक आदमी अपने को दूसरे दर्जे का नागरिक मान रहे हैं. किसका दोष है यह? यह नागरिकों का नहीं, सरकार का कसूर है. हम आशा करते हैं कि सरकार अपनी ख़ामियों को दूर करेगी, वरना जनता का असंतोष और बढ़ेगा.

संपादक
editor.chauthiduniya.com

रवि किशोर

डॉक्टर की हर चूक को आपराधिक नहीं माना जाना चाहिए

डॉक्टरों द्वारा मरीजों के प्रति लापरवाही के आरोप की वजह से उनके ख़िलाफ़ क़ानूनी मामलों में पहले की अपेक्षा वृद्धि हुई है. क्या यह सिर्फ़ निर्दोष डॉक्टरों के विरुद्ध शिकायतें हैं या फिर वाक़ई चिकित्सा का स्तर गिरता जा रहा है? पिछले कुछ दशकों में जहां चिकित्सा क्षेत्र में तकनीकी विकास की वजह से जीवन स्तर में सुधार हुआ है, वहीं नैतिक स्तर में गिरावट आई है.

यह बेहद दुर्भाग्य की बात है कि ज्यादातर चिकित्सकीय संस्थानों में स्वास्थ्य शिक्षा, मरीज प्रबंधन और इसमें निवेश से संबंधित सुविधाओं का ख्याल नहीं रखा जाता है. अस्पतालों और चिकित्सा से जुड़े लोग जैसे-जैसे व्यवसायीकरण और कॉरपोरेट संस्कृति अपना रहे हैं, उसी अनुपात में मरीज और डॉक्टरों के बीच संबंधों में दूरियां बढ़ती जा रही हैं.

सुप्रीमकोर्ट के मुताबिक़, एक डॉक्टर किसी मरीज की मौत का ज़िम्मेदार तब तक नहीं माना जा सकता, जब तक उसकी लापरवाही साबित नहीं हो जाती. साथ ही उसका रवैया मरीजों के जीवन और सुरक्षा के लिहाज से राज्य के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में भी आता हो. लेकिन, यदि कोई मरीज अपने इलाज और सर्जिकल ऑपरेशन के लिए राजी है तो ऐसे में डॉक्टरों की हर लापरवाही अपराध की श्रेणी में नहीं आएगी. इसे अपराध तभी माना जा सकता है कि जब डॉक्टरों की घोर लापरवाही की वजह से किसी मरीज़ की ज़िंदगी काफी नाजुक हो जाए या उनकी लापरवाही मरीजों की मौत की वजह बन जाए.

यदि किसी मरीज की मौत दुर्घटनावश होती है तो इसे अपराध से जोड़ कर नहीं देखना चाहिए. इस तरह के मामले सुरक्षा या नागरिक दायित्व में तो आ सकते हैं, लेकिन इन्हें अपराध की संज्ञा नहीं दी जा सकती. कोई मामला अपराध की श्रेणी में तभी माना जाएगा, जब अभियुक्त नैतिक तौर उस अपराध के लिए ज़िम्मेदार हो. यदि लापरवाही का स्तर अधिक हो जाए तो सामान्य नियमों के अनुसार यह निश्चित तौर पर अपराध माना जाएगा.

चिकित्सीय लापरवाही के संदर्भ में आम भारतीयों की जागरूकता बढ़ रही है. साथ ही अस्पताल प्रबंधन को तमाम सुविधाएं, पेशेवराना रवैया और चिकित्सकीय जांच प्रणालियों को लेकर शिकायतों का भी सामना करना पड़ रहा है. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत कुछ मरीजों ने डॉक्टरों के विरुद्ध क़ानूनी मामले भी दर्ज़ कराए और प्रबंधन की लापरवाही को साबित किया. साथ ही उन्होंने मुआवजा भी लिया. नतीजतन, लापरवाही से जुड़े कई मामलों पर क़ानूनी फ़ैसले दिए गए.

हालांकि इस तरह के क़ानूनी मामलों ने डॉक्टरों के उत्साह को कम भी किया है, क्योंकि इलाज के दौरान हमेशा उनके दिमाग़ में यह आशंका बनी रहती है कि भले ही उनका प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहे, लेकिन किसी कारणवश यदि मरीज की मौत हो जाती है तो बेवजह उन्हें क़ानूनी पचड़ों में फंसना पड़ सकता है. यदि किसी मरीज की मौत चिकित्सकीय त्रुटि की वजह से होती है तो इसका क़सूरवार डॉक्टरों को नहीं माना जा सकता है.

हालांकि पहले सुप्रीमकोर्ट की राय इन मामलों में बिल्कुल अलग थी, लेकिन हाल में मार्टिन एफ डिसूजा बनाम मो. इश्फाक़ के मामले ने सारा माज़रा ही बदल दिया. इस संदर्भ में फ़ैसला माननीय न्यायाधीश मारकंडे काटजू और न्यायाधीश आर एम लोढ़ा की सम्मिलित पीठ ने दिया.

सुप्रीमकोर्ट के मुताबिक़, डॉक्टरों के ख़िलाफ़ फौजदारी, दीवानी और उपभोक्ता मंच में मामले दर्ज़ किए जाते हैं, वह उनकी लापरवाही का ही नतीजा होता है. इसलिए डॉक्टरों को अपनी ज़िम्मेदारी बख़ूबी समझनी चाहिए. इस संदर्भ में सारा मामला उच्चतम न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ द्वारा जैकब मैथ्यू बनाम पंजाब और एएनआर के मामले में दिए गए फ़ैसले से स्पष्ट हो जाता है.

हालांकि समस्या तब खड़ी होती है, जब इन मामलों की व्याख्या करने का सवाल सामने आता है. चिकित्सकों को अपने काम में कुशलता और जानकारी का बख़ूबी इस्तेमाल करना चाहिए और साथ ही सावधानी भी बरतनी चाहिए. नियमों के लिहाज से प्रतिद्वंद्विता और सावधानी में किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए.

जैकब मैथ्यू के मामले में कहा गया कि साधारण लापरवाही के लिए केवल दीवानी, जबकि किसी बड़ी लापरवाही के लिए फौजदारी मुक़दमों के तहत मामला दर्ज़ किया जा सकता है. दीवानी अपराधों के तहत डॉक्टरों को हर्जाना देना पड़ सकता है, जबकि फौजदारी मामलों में उन्हें जेल की सजा भी हो सकती है. हालांकि साधारण और बड़ी लापरवाही के मामलों पर विशेषज्ञों में मतभेद हो सकते हैं.

क़ानून भी चिकित्सा विज्ञान की तरह ही एक मुकम्मल विज्ञान नहीं है. कोई भी आदमी इसके बारे में पूर्वानुमान नहीं लगा सकता है. यह मामलों के तथ्य और परिस्थिति विशेष पर निर्भर करता है. साथ ही इस बात पर भी कि मामले की सुनवाई कौन न्यायाधीश कर रहा है. लेकिन, इन सबके बीच चिकित्सकीय लापरवाही से संबद्ध सामान्य बातों को समझने की ज़रूरत है.

उच्चतम न्यायालय ने इन मामलों पर फ़ैसला देने से पहले दो ख़ास पहलुओं पर ध्यान दिया. पहला यह कि न्यायाधीश चिकित्सा विज्ञान के विशेषज्ञ नहीं हैं, अत: वे इन मामलों की सुनवाई एक सामान्य नागरिक की तरह ही करेंगे. नतीजतन, इस तरह की लापरवाही के मामले में उनसे भी चूक हो सकती है. दूसरा यह कि इन मामलों में सामंजस्य बनाने की ज़रूरत है. जिन डॉक्टरों की वजह से मौत होती है, उन्हें इसके लिए दंडित किया जाना चाहिए. लेकिन हमें यह भी सोचने की ज़रूरत है कि यदि उनकी छोटी-मोटी ग़लतियों के लिए हमेशा दंडित किया जाएगा तो वे चिकित्सकीय पेशे को ही छोड़ देंगे. इस तरह की मानवीय भूल हर किसी से हो सकती है. ऐसे में तो कोई भी डॉक्टर धैर्य और सहज भाव से काम नहीं कर पाएगा. समाज की सेवा कर रहे इन डॉक्टरों के विरुद्ध हमेशा इस तरह के निर्णय उचित नहीं हैं. परिस्थिति विशेष में इस तरह के फ़ैसले नहीं लिए जाने चाहिए. उपरोक्त दोनों बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए सुप्रीमकोर्ट को चिकित्सकीय लापरवाही से संबंधित सामान्य सिद्धांतों पर विस्तार से चर्चा करने की ज़रूरत है.

(लेखक सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं)

feedback@chauthiduniya.com

चौकस बनाए रखें नजर

संपादक जी,
चौथी दुनिया का नया अंक मिला. आवरण कथा- जसवंत से घबराए अनंत पढ़ी, अच्छी लगी. विषय का चयन जब भी हो, यह देखना बहुत जरूरी है कि उसमें नयापन हो. इस लिहाज से भी आवरण कथा खरी उतरती है. मिड डे मील के बहाने इस्कॉन के घोटाले का पर्दाफाश करके चौथी दुनिया ने देश में व्याप्त भ्रष्टाचार पर एक करारी चोट की है. उम्मीद है कि आइंदा भी आप अपनी नजर इतनी ही चौकस रखेंगे.

मधुकर पांडेय, *लखनऊ, उत्तर प्रदेश.*

सरकार का ढुलमुल रवैया

महोदय,
5-11 अक्टूबर के अंक में क्या भारत एक कमजोर राष्ट्र है, शीर्षक से प्रकाशित आलेख में लेखिका ने चीन की ओर से हमारे देश के लिए बढ़ते खतरे की तरफ साफ इशारा किया है. वास्तव में हमारी सरकार ने अभी तक इस मामले में अपनी किसी ठोस नीति-सोच का परिचय नहीं दिया है. उसका यही ढुलमुल रवैया अक्सर हमें नाकामी के दलदल में धकेलता है. जब आफत आ जाए तो बचाव का भला क्या अर्थ? बात तो तब है, जबकि हम पहले से ही मुसीबत का मुकाबला पूरे जोर शोर से करने के लिए तैयार रहें.

जयवीर सिंह चौहान, *भोपाल, मध्य प्रदेश.*

कभी होता था ऐसा

संतोष जी,
हमेशा की तरह इस बार भी तोप मुकाबिल पर नजर थी. कांग्रेस और भाजपा में कुछ तो फर्क हो के अंतर्गत आपने कहा कि विपक्ष का नेता शेर होता है, वह जनता की आवाज बनता है, उसके दुखदर्द की खबर सरकार के कानों तक पहुंचाता है. आप सही कहते हैं, लेकिन यह तो बीते जमाने की बात है, कभी होता था ऐसा. आज के नेता प्रतिपक्ष से आप ऐसी उम्मीद क्यों लगा बैठे? कौन विपक्ष का नेता है और कौन सत्तापक्ष का, आज जब यह फर्क ही मिट चुका है तो उनकी सोच भला भिन्न कैसे हो सकती है?

बृजभूषण थपलियाल, *देहरादून, उत्तराखंड.*

ज्ञानवर्द्धक जानकारी

क्या आपका बच्चा भुलक्कड़ है शीर्षक से प्रकाशित लेख में बच्चों में भूलने की बीमारी के विषय में विस्तार से बताया गया. आमतौर पर ऐसी बातों और इससे जुड़ी सावधानियों के बारे में सहज मालूम नहीं पड़ता. लेख हम सबके लिए उपयोगी है और पेज की सार्थकता का प्रमाण भी.

रंजना सिंह, *द्वारका, नई दिल्ली.*

बिहार-झारखंड परिशिष्ट

चौथी दुनिया ने बिहार और झारखंड को चार पेज अतिरिक्त देकर बहुत अच्छा किया, क्योंकि इन राज्यों की बहुत सी खबरों को समाचारपत्रों में अपेक्षित स्थान नहीं मिल पाता. कभी कभी भोजपुरी सिनेमा की भी सुधि ले लिया करें.

सदानंद झा, *हाजीपुर, बिहार.*

पाठक अपने विचार और सुझाव हमें इस पते पर भेज सकते हैं-
संपादक, चौथी दुनिया, एफ-2, सेक्टर - 11
नोएडा (उत्तर प्रदेश) पिन-201301
ई-मेल पता : feedback@chauthiduniya.com

सौमित्र मोहन

क्या हम भारतीय नस्लवादी हैं?

हम सभी एक राष्ट्र के तौर पर नस्लवाद के प्रति हमेशा से संवेदनशील रहे हैं और रहेंगे भी. हाल में नस्ल और नस्लवाद से संबंधित ऐसे कई मामले सामने आएं, जिन्होंने मीडिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया. पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों पर हुए हमलों ने इस देश में नस्लवाद को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है. यह हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ही थे, जिन्होंने दक्षिण अफ़्रीका में नस्लवादी नीतियों के ख़िलाफ़ मुहिम छेड़ी थी. पहली बार दक्षिण अफ़्रीका के पीटर मरित्ज़बर्ग रेलवे स्टेशन पर नस्लवादी भेदभाव से दो-चार होने के बाद उन्होंने इसकी मुख़ालफ़त शुरू की, जो 19 वीं सदी के अंत में पूरी दुनिया में उपनिवेशवाद के ख़िलाफ़ जंग की प्रतीक बनी. जब भारत आज़ाद हुआ तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में नस्ल के आधार पर समानता को भी शामिल किया गया. बाद में भारत ने नस्लीय भेदभाव के ख़िलाफ़ अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सहित कई वैश्विक समझौतों पर हस्ताक्षर किए. लेकिन, ऐसे में यह बेहद ही आश्चर्य करने वाला है, जब किसी भारतीय को ही नस्लवाद और नस्लवादी व्यवहार का दोषी पाया जाता है.

क्रिकेट विश्वकप के दौरान इएसपीएन के विज्ञापन, इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) क्रिकेट मैच में सांवले रंगों वाली चीयर लीडर्स की जगह साफ़ और गोरे रंगों वाली चीयर्स लीडर्स, सोनी इंडियन आइडल के प्रतिभागी प्रशांत तमांग पर रेडियो जॉकी की कथित टिप्पणी या एंड्रयू साइमंड्स विवाद जिसमें हरभजन सिंह पर साइमंड्स को मंकी (बंदर) कहने का आरोप लगा था, आदि प्रमुख उदाहरण हमारे सामने हैं. इस तरह नस्लवाद हमारी बुद्धिजीवी चेतना का अंग बन चुका है. अभी हाल ही में उत्तर-पूर्व के एक वरिष्ठ और सम्माननीय नेता ने आरोप लगाया कि वह भी इस देश में नस्लवादी टिप्पणियों का शिकार होते रहे हैं. क्या हम वाक़ई एक राष्ट्र के तौर पर नस्लवादी हैं? क्या पुरातन जाति व्यवस्था या इससे जुड़ी ग़ैर-ज़रूरी अस्पृश्यता (अब इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के मुताबिक़ प्रतिबंधित कर दिया गया है) भी इसके लिए ज़िम्मेदार है? हालांकि जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता अभी भी इस देश में एक कड़वी सच्चाई है. क्या उपर्युक्त भी एक वजह नहीं है जिससे किसी समुदाय, जाति व मज़हब विशेष को पसंद या नापसंद करने का चलन बन पड़ा हो अथवा क्या यह सिर्फ़ गोरे रंग के प्रति पूर्वाग्रह या भ्रम है? आख़िरकार गोरा रंग इस देश में उच्च जाति के आर्यन से जो जुड़ा हुआ है. हालांकि यह बंधन भी काफी पहले तोड़ा जा चुका है. अंतरजातीय और अंतरनस्लीय वैवाहिक संबंधों की वजह से आज हर जाति और समुदाय में सांवले रंग के लोग हैं. केवल यही नहीं, एक ही परिवार में अलग-अलग रंगों के भी सदस्य हैं.

फिर भी गोरे रंग के प्रति हमारा लगाव हमारे विचारों में आता है. साथ ही अवचेतन और कभी-कभी तो यह विभिन्न रंग के लोगों के साथ व्यवहार भी अलग-अलग करता है. प्राय: भारतीय अवधारणा में सुंदरता का मतलब ही गोरा रंग होता है. क्या हमारे प्राय: सभी देवी-देवता गोरे रंग के और सभी दानव काले रंगों के नहीं हैं? तभी से माना गया कि काले रंग से जुड़ना अपराध है, जबकि गोरे रंग का मतलब सदाचारी, शुद्ध, सुंदर और सर्वगुण संपन्न होना है. भारतीयों में गोरे रंग के प्रति आकर्षण इस देश के बाज़ार में फेयरनेस क्रीम और इसी तरह के दूसरे कई उत्पादों के ज़रिए आया. आप बस वादा करें कि अमुक उत्पाद आपके गोरे रंग को बढ़ाता है तो आप कोई भी घटिया उत्पाद इस देश में बेच सकते हैं. हमारे वैवाहिक विज्ञापनों में भी गोरे रंग वाली दुल्हनों को ही प्राथमिकता मिलती है. इस देश में अधिकांश पुरुष गोरे रंग वाली पत्नियों की ही इच्छा रखते हैं, ताकि कम से कम उनके बच्चे तो गोरे हों. यदि आपका बच्चा गोरे रंग का है तो आप बड़ी ही आसानी से उसके लिए योग्य वर या वधू तलाश सकते हैं. अधिकांशत: यह बात लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के मामले में अधिक लागू होती है.

> कई अफ़्रीकी नागरिक भारतीयों द्वारा नस्लीय भेदभाव का आरोप लगाते रहे हैं. अफ़्रीकियों की अपेक्षा अधिक गोरे रंग का होने की वजह से बहुत से भारतीय ख़ुद को उनसे श्रेष्ठ मानते हैं. एक वक़्त ऐसा भी था, जब यह आरोप लगा कि गोरे रंग के पूर्वाग्रह से ग्रसित लोग गोरे रंग की ही एयर होस्टेस, टीवी न्यूज़ रीडर, अभिनेता और अभिनेत्रियों का चयन करते हैं. अभी भी अधिकांश सफल अभिनेता और अभिनेत्रियां अपने वास्तविक रंगों के बजाय मेकअप में शूटिंग करते हैं.

कई अफ़्रीकी नागरिक भारतीयों द्वारा नस्लीय भेदभाव का आरोप लगाते रहे हैं. अफ़्रीकियों की अपेक्षा अधिक गोरे रंग का होने की वजह से बहुत से भारतीय ख़ुद को उनसे श्रेष्ठ मानते हैं. एक वक़्त ऐसा भी था, जब यह आरोप लगा कि गोरे रंग के पूर्वाग्रह से ग्रसित लोग गोरे रंग की ही एयर होस्टेस, टीवी न्यूज़ रीडर, अभिनेता और अभिनेत्रियों का चयन करते हैं. अभी भी अधिकांश सफल अभिनेता और अभिनेत्रियां अपने वास्तविक रंगों के बजाय मेकअप में शूटिंग करते हैं. बॉलीवुड के सबसे सफल अभिनेता और अभिनेत्रियां भले ही वे गोरे रंग के नहीं हैं, लेकिन उनके चित्र हमेशा गोरे रंगों में ही होते हैं. कम से कम हम में से अधिकांश उन्हें ऐसे ही जानते हैं. दैनिक जीवन में ऐसे कई शब्द हैं, जो नस्लीय हैं और साथ ही वे हमारी बोलचाल का हिस्सा भी हैं. मल्लू, चिंकी, सरदारजी, गुज्जू, पुंजू और बिहारी जैसे शब्द हमारी शब्दावली का हिस्सा बनते जा रहे हैं. इस तरह व्यवहार और बोलचाल के अंदाज़ पर कई तरह की कहानियां व चुटकुले भी बन जाते हैं. हम सब बिहारी, सरदारजी, मुल्लू और गुज्जू पर बने चुटकुलों को बड़े चाव से सुनते-सुनाते हैं. लेकिन क्या इससे यह साबित होता है कि हम नस्लवादी हैं?

इस तरह के पूर्वाग्रह सिर्फ़ भारत और भारतीयों में ही नहीं हैं, बल्कि पूरी दुनिया की यही हक़ीक़त है. नस्ल, लिंग और क्षेत्रीयता से संबंधित कुछ दंतकथाएं या इतिहास भी प्रचलन में चले आ रहे होते हैं. इस तरह उक्त सभी हमारी चेतना में जाति और समुदाय विशेष के प्रति एक पूर्वाग्रह बन जाते हैं. धीरे-धीरे इसे हम स्वाभाविक तौर पर लेने लगते हैं और फिर धीरे-धीरे इसे प्राकृतिक रूप में स्वीकार भी करने लगते हैं. कम से कम अधिकांश लोग तो ऐसा ही करते हैं.

यही वजह है कि गुज्जू और मारवाड़ी धन से अपने अधिक लगाव के लिए अथवा मल्लू या बिहारी काम की तलाश में कहीं भी जाने के लिए जाना जाता है. मल्लू भाषा के लिहाज से ख़ास तरह की उच्चारण शैली होने की वजह से उपहास का पात्र बनते हैं. यही हाल बिहारियों और जाटों का है. सरदारजी और इंडियन (पढ़ें रेड इंडियन) पर इतने चुटकुले बन चुके हैं कि उनका मज़ाक चुटकुलों के ज़रिए ही उड़ाया जाता है. कुछ लोग मानते हैं कि यह सब एक स्वस्थ व्यवहार के तौर पर तभी तक स्वीकृत है, जब तक कि सामने वाला उसे उसी मज़ाकिया अंदाज़ में स्वीकार करता है और आपसी सौहार्द के साथ हंसी-मज़ाक का लुत्फ उठाता है. इस तरह सामाजिकता का भी विकास होता है. दरअसल यह हमारा बेपरवाह और अशोभनीय बर्ताव ही है, जो सारे विवादों को जन्म देता है. निश्चित तौर पर यह घृणित नस्लीयता और गुलामी जैसी विकृत मानसिकताओं की श्रेणी में नहीं आता है. साथ ही यह तब तक नस्लीय भेदभाव नहीं है, जब तक कि ऐसा किसी को अपमानित करने के इरादे से न कहा गया हो.

जब कोई किसी सरदार या मुल्लू का मज़ाक उड़ाता है तो निश्चित तौर पर उसमें किसी को अपमानित करने की मंशा नहीं होती है, क्योंकि दोनों ही भारतीय समाज एक सफल हिस्से हैं. लेकिन, समस्या वहां शुरू होती है, जब दोनों पक्ष इन अवसरों का इस्तेमाल पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर एक दूसरे के सामाजिक हितों को नुक़सान पहुंचाने के लिए करते हैं. इस तरह के पूर्वाग्रहों से उपजी हिंसा इतना गंभीर रूप धारण कर लेती है, जिससे एक राष्ट्र बिखर सकता है. 1970 के दशक में पाकिस्तान का बंटवारा इसकी सबसे बड़ी मिसाल है. गनीमत है कि भारतीय संदर्भ में ऐसा कभी नहीं हुआ.

पंजाब में यदि अलगाव सफल नहीं हो सका तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दो समुदायों के बीच रोटी-बेटी (जीवनयापन और वैवाहिक संबंध) का संबंध था. ठीक इसी तरह यदि हम साथ-साथ रहते हैं, समाज में अंतरजातीय, अंतरधर्मीय, अंतर्समुदायी व अंतर-क्षेत्रीय विवाह का चलन बढ़ता है तो ऐसा हर लक्षण और पूर्वाग्रह अपना ज़हर धीरे-धीरे खोता जाएगा. और तब यदि कोई इस तरह के मज़ाक व टिप्पणियां करता है तो भी उनसे कोई ऐसी प्रतिक्रिया पैदा नहीं होगी, जिससे समस्याएं सामने आएं. भारतीय समाज पारंपरिक तौर पर हमेशा से ही इतना खुला रहा है कि यहां सभी लोग आसानी से रह सकते हैं. यही वजह है कि आज यह सलाद के कटोरे जैसा है, जिसमें सब कुछ घुला मिला रहता है. एक विविध जातीय और नस्लीय समाज होने की वजह से अक्सर ऐसा व्यवहार सामने आ जाता है, लेकिन यह तब तक असामान्य बात नहीं है जब तक कि इसे दूसरों को बग़ैर ठेस पहुंचाए नेक इरादे से कहा गया हो. जिस दिन हमारा समाज समझदार और शिक्षित हो जाएगा, उस दिन हर किसी को यह अहसास होगा. इस तरह की बातें समय के मुताबिक़ बदलनी होंगी और बतौर समाज हमें और अधिक परिपक्व होना पड़ेगा. ऐसा तभी हो सकता है, जबकि हम हर मामले में सभ्य और सुशिक्षित होंगे.

(लेखक प. बंगाल में आईएएस अधिकारी हैं. आलेख में व्यक्त विचार उनके अपने हैं और इनका सरकार के विचारों से कोई संबंध नहीं है.)

feedback@chauthiduniya.com

ओबामा ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान इस तरह के वायदे किए थे. उन्होंने कहा था कि समलैंगिकों को भी सेना में भर्ती होने की इजाज़त मिलेगी.

ख़ुफ़िया एजेंसियों के सीक्रेट

मोसाद का ख़ौफ़नाक क़हर

इज़रायल का ख़ुफ़िया आतंक

पिछले अंक में आपने पढ़ा कि किस तरह ब्लैक सेप्टेंबर के आतंकी म्यूनिख ओलंपिक में इज़रायली खिलाड़ियों पर क़हर बन कर टूटे. यहां तक कि उन्होंने इज़रायलियों को संभलने का मौक़ा तक नहीं दिया, साथ ही एक और बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया. जी हां, म्यूनिख ओलंपिक के दौरान पकड़े गए अपने तीन साथियों को छुड़ाने के लिए ब्लैक सेप्टेंबर के आतंकियों ने एक जेट एयरवेज का अपहरण कर लिया, ताकि वे इज़रायली सरकार को अपनी मांगें मनवाने के लिए मजबूर कर सकें. लेकिन, इस बार मिशन की कमान जर्मन अधिकारियों के हाथ में नहीं थी. इन दहशतगर्दों से निपटने की ज़िम्मेदारी दुनिया की तेज़तर्रार ख़ुफ़िया एजेंसी मोसाद को सौंपी गई, जिसका मक़सद हमेशा से यही रहा है...आंख के बदले आंख और जान के बदले जान. इस तरह मोसाद का मंसूबा बिल्कुल साफ़ था. अपने मुल्क को ख़ून के आंसू रुलाने वालों को मौत की नींद सुलाना. हालांकि, यह मिशन कतई आसान नहीं था. यानी मोसाद सरेआम उन आतंकियों को नहीं मार सकता था. इसकी सबसे बड़ी वजह थी कई देशों का उस पर दबाव. उन्हें पकड़ कर सज़ा तो दी जा सकती थी, लेकिन उनका काम तमाम करने पर आमादा मोसाद की मदद के लिए कोई नहीं राजी था. वजह, इस पूरी वारदात में प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर कई देश शामिल थे. मसलन सीरिया, लीबिया, मिस्र और सऊदी अरब आदि. मोसाद के इस मिशन की संजीदगी का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता था कि कई देश म्यूनिख के गुनहगार ब्लैक सेप्टेंबर के आतंकियों को हर लिहाज़ से मदद करते थे. इसका सबसे बड़ा सबूत है कि जर्मन शार्प शूटर्स की गोलियों के शिकार बने आतंकियों के शव जब लीबिया पहुंचे तो उन्हें किसी शहीद के शव की तरह राजकीय सम्मान के साथ दफ़नाया गया. इन देशों का यह क़दम इज़रायल के लिए जले पर नमक छिड़कने से कहीं अधिक दर्द देने वाला था. बस, अब तो मोसाद का एकमात्र मिशन था कि दुनिया के किसी भी कोने से इन आतंकियों को तलाश कर उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाना. एक बार मिशन म्यूनिख के आतंकियों के ख़ात्मे का ज़िम्मा सौंपे जाने के बाद मोसाद ने अपने मिशन का आग़ाज़ किया. तारीख़ थी 9 अप्रैल 1973 और मिशन था रॉथ ऑफ गॉड. इसके लिए मोसाद का सबसे पहला काम था दुनिया के किसी भी कोने में छिपे आतंकियों को खोज निकालना. यह ज़िम्मा मोसाद के यूरोपियन एजेंट्स को सौंपा गया. बहुत ही जल्द मोसाद यह पता लगाने में कामयाब हो गया कि ब्लैक सेप्टेंबर का सरगना मोहम्मद युसूफ़ अल-नज़र उर्फ़ अबू युसूफ़ है, जो इज़रायल में आतंकी वारदातों को अंजाम देता था. उसके एक और सहयोगी अली हसन सालमेह की तलाश करते हुए मोसाद की टीम मोरक्को पहुंच गई, जहां उसने 21 जुलाई 1973 को एक आतंकी को मार गिराया. लेकिन यह मोसाद की कामयाबी नहीं, बल्कि उसकी एक नाकामयाबी ही साबित हुई. दरअसल मारा गया शख़्स ब्लैक सेप्टेंबर का आतंकी नहीं, बल्कि मोरक्को होटल का एक वेटर था, जो बेवजह मोसाद की ग़लतफहमी का शिकार हो गया. म्यूनिख के गुनहगार अभी भी मोसाद के शिकंजे से काफी दूर थे. पूरी दुनिया के चप्पे-चप्पे में मौजूद मोसाद को इसके लिए भी ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा. आख़िरकार, उसके शातिर और क़ाबिल ख़ुफ़िया एजेंटों ने उनका पता लगा ही लिया. जिसकी तलाश में मोसाद मोरक्को भटक रहा था, ब्लैक सेप्टेंबर का वह ख़तरनाक सदस्य अली हसन सालमेह बेरूत में मौजूद था. एक बार फिर मोसाद ने उसे घेरने का पूरा प्लान तैयार कर लिया और साथ में मौक़े पर ही उसे ख़त्म करने का पूरा साज़ो-सामान भी. अपने इस गुप्त मिशन को मोसाद ने कुछ इस तरह अंजाम दिया कि ख़ुद अली हसन को भी पता नहीं चल पाया कि जिस गाड़ी में वह सवार है, वह गाड़ी नहीं बल्कि चलता-फिरता मौत का सामान है. जी हां, मोसाद ने उसकी गाड़ी को रिमोट कंट्रोल्ड कार बम में तब्दील कर दिया था. इस तरह मोसाद के मिशन का पहला निशाना बना ब्लैक सेप्टेंबर का शातिर सरगना अली हसन सालमेह. इस तरह एक-एक कर मोसाद ने ब्लैक सेप्टेंबर के सदस्यों को ख़त्म करना शुरू कर दिया. अभी तक मोसाद ब्लैक सेप्टेंबर के दो ख़ास सदस्यों को मौत के घाट उतार चुका था.

सूत्रों की मानें तो इज़रायल का यह मिशन 20 से भी अधिक वर्षों तक चला. मोसाद का यह मिशन कितना ख़ौफ़नाक था, इसकी सबसे बड़ी दास्तां यह है कि जिस किसी पर भी मोसाद को शक़ हुआ, वह इसकी नज़रों से बच नहीं पाया. यही वजह है कि मोसाद के इस मिशन के दौरान कई बेगुनाहों को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा. लेकिन इससे एक बात तो साफ़ हो गई कि मोसाद जिस किसी के भी पीछे पड़ता है, उसका समूल नाश करके ही दम लेता है. चाहे इसके लिए उसे किसी भी हद तक क्यों न गुज़रना पड़े. इसकी जीती जागती मिसाल है 1992 में पेरिस में फिलिस्तीनी संगठन फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गनाइज़ेशन (पीएलओ) के ख़ुफ़िया प्रमुख की हत्या. मोसाद का मानना था कि इसके तार भी म्यूनिख की साज़िश से जुड़े थे. इसी तरह मोसाद ने न जाने कितने फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतार दिया.

लेकिन, मोसाद की ख़ुफ़िया गतिविधियों पर पैनी नज़र रखने वाले एक लेखक की मानें तो म्यूनिख त्रासदी के पीछे जिस मास्टर माइंड का हाथ था, वह तो कभी भी मोसाद की पकड़ में नहीं आ सका. मोसाद सिर्फ़ इस मास्टर माइंड के मोहरों को ही अपना शिकार बना सका. इन दो मास्टर माइंड में से एक की मौत 1970 में दिल का दौरा पड़ने से हुई, जबकि दूसरा क़ातिल अभी भी ज़िंदा है. जी हां, हम बात कर रहे हैं पर्दे के पीछे से इस सारे खेल को अंजाम देने वाले खिलाड़ी मोहम्मद सफ़दी और अदनान अल-गाशी की. मोहम्मद सफ़दी की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई, न कि मोसाद के बहुचर्चित मिशन रॉथ ऑफ़ गॉड में और कई लोगों का मानना है कि म्यूनिख ओलंपिक के बाद जेट एयरवेज़ के अपहरणकर्ताओं में से एक अभी भी सही सलामत ज़िंदा है. जमाल अल-गाशी, जी हां यही नाम है उस शख़्स का, जो अभी भी मोसाद के डर से अंडरग्राउंड ज़िंदगी जीने को मजबूर है. इस तरह मोसाद का ख़ौफ़ आज भी पूरी दुनिया में बरक़रार है. जिस किसी ने भी इज़रायल की तरफ़ आंख उठाकर देखने की जुर्रत की, उसका हश्र कुछ यूं हुआ कि या तो उसे मोसाद के हाथों अपनी जान बड़ी बेरहमी से गंवानी पड़ी या फिर ज़िंदगी भर वह मोसाद के ख़ौफ़ के साए में जीने को मजबूर हो गया.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

ज़रा हट के

सौ वर्ष के बाद मनाया जन्मदिन

जन्मदिन तो लोग हर साल मनाते हैं, लेकिन अगर कोई एक सौ दस वर्ष की उम्र में पहली बार जन्मदिन मनाए तो उसमें ज़रूर कोई ख़ास बात होगी. ख़ैर, हम इनके जन्मदिन में शामिल तो नहीं हो सकते, लेकिन शुभकामना ज़रूर दे सकते हैं. इसलिए दीजिए ढेर सारी शुभकामनाएं कोयंबटूर शहर के ओल्ड एज होम में रहने वाली पी कुपाथल को, जिन्होंने हाल ही में अपना 110वां जन्मदिन मनाया.

एक सौ दस साल की उम्र में भी वह काफी ऊर्जावान हैं. फुर्ती ऐसी कि जिसे देखकर आप भी यह सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि इनकी सेहत का राज़ क्या है? कुपाथल आज भी बिना किसी सहायता के घूम-फिर सकती हैं. उन्होंने बताया कि वह रोज सुबह शाम को सैर करती हैं और अपने जीवन में कभी बीमार नहीं पड़ीं. 1899 में जन्मी कुपाथल को देखने और सुनने में भी कोई परेशानी नहीं होती. उनकी शादी 10 साल की उम्र में हो गई थी. लगभग चार-पांच साल बाद ही वह विधवा भी हो गईं. उन्होंने अपने बच्चों को ख़ूब पढ़ाया-लिखाया, लेकिन आज उनकी देखभाल करने के लिए कोई भी साथ नहीं है. बावजूद इसके उन्होंने हिम्मत नहीं हारी. उनका मानना है कि यही तो जीवन की सच्चाई है.

अब सेना में भी समलैंगिक

समलैंगिक भी अब दुश्मन पर प्रहार करेंगे. वे सेना की वर्दी और आधुनिक हथियारों से लैस नज़र आएंगे. वे दुश्मन को ललकारेंगे. लेकिन, ऐसा अपने देश में नहीं, बल्कि सात समंदर पार अमेरिका में होने वाला है. अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान इस तरह के वायदे किए थे. उन्होंने कहा था कि समलैंगिकों को भी सेना में भर्ती होने की इजाज़त मिलेगी.

एक समाचार एजेंसी के मुताबिक़, राष्ट्रपति ओबामा ने समलैंगिकों की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 1993 में सेना में समलैंगिकों की भर्ती पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन मैं इस प्रक्रिया को फिर से शुरू करूंगा. हालांकि यह अधिकार उन्हें कब दिया जाएगा, इसकी चर्चा ओबामा ने नहीं की. आप चौंक क्यों गए? इसमें चौंकने जैसी कोई बात नहीं है. आख़िर समलैंगिक भी इंसान हैं. उन्हें भी यह अधिकार मिलना चाहिए, ताकि वे भी अपनी इच्छा अनुसार नौकरी कर सकें. ख़ैर, हम तो यही कामना करेंगे कि उन्हें सेना में नौकरी की मंजूरी जल्द से जल्द मिले.

ई-मेल का उपयोग कैसे करते आइंस्टीन?

आप पत्र व्यवहार के मामले में कम से कम आइंस्टीन और चार्ल्स डार्विन से अलग नहीं हो सकते. नॉर्थवेस्ट यूनिवर्सिटी द्वारा ह्यूमेन बिहेवियर पर आधारित एक स्टडी के मुताबिक़, वह चिट्ठी लिखने के लिए जिस कलम, कागज़ और भाषा का प्रयोग करते थे (इलैक्ट्रॉनिक मेल के अस्तित्व में आने से बहुत पहले), बिल्कुल उसी पैटर्न का उपयोग आज लोग ई-मेल पर करते हैं.

यह अध्ययन (जनरल साइंस मैगज़िन में प्रकाशित) उनकी गतिविधियों की समानता को दर्शाता है. शोधकर्त्ताओं ने 16 प्रसिद्ध लेखकों, कलाकारों, राजनीतिज्ञों और वैज्ञानिकों की चिट्ठियों को गहनता से जांचा, जिसमें आइंस्टीन, डार्विन, सिग्मांड फ्रेड, कार्ल मार्क्स और इर्नेस्ट हेमिंगवे आदि प्रमुख रूप से शामिल थे. शोधकर्त्ताओं ने पाया कि किसी ख़ास समय अंतराल पर वे एक दूसरे को चिट्ठी लिखते थे.

पहले भी ई-मेल व्यवहार को बताने के लिए नॉर्थ वेस्टर्न टीम ने कुछ इसी तरह की गणितीय पद्धति का उपयोग किया था. अब पत्र लिखने वाले लेखकों पर भी इसी पद्धति को लागू किया गया है. सभी में एक बात समान थी कि वे सब लगभग एक जैसी ही चिट्ठी लिखते थे. लुईस अमराल, जो मैक क्रोमिक स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड एप्लाइड साइंस में केमिकल और बाइलोजिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं, ने कहा कि मानव व्यवहार के पैटर्न को पहचानने और समझने के लिए हम काफी उत्साहित हैं. शोध टीम के मुखिया अमराल ने कहा कि कुछ पैटर्न ऐसे हैं कि हमने कैसे दिन बिताए? लोग किसी काम को निश्चित समय पर निबटाने के लिए कैसे समय का निर्धारण करते हैं? क्या इसे किसी अन्य क्षेत्र में भी लागू किया जा सकता है?

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

फायरिंग का यह सिलसिला चालीस मिनटों तक चलता रहता है. सेना के हेलीकॉप्टर इलाक़े की छानबीन में जुट गए और कमांडो दस्ते ने आतंकवादियों की लाशें अपने क़ब्ज़े में ले लीं और घटनास्थल से हटा भी दीं.

पाकिस्तान में कौन सुरक्षित है?

फोटो– पीटीआई

अक़दस वहीद

पिछले दिनों किसी ने मुझे एक एसएमएस भेजा, जो कि वतनपरस्ती के बारे में था. आइए आपको भी इस एसएमएस के बारे में बताते हैं. इसका शीर्षक था, वतनपरस्ती की एक कहानी. एक लड़का था, जो पाकिस्तान को पसंद नहीं करता था और उसकी यह नापसंदगी देश के मौजूदा हालात के चलते थी. लिहाज़ा, वह हमेशा पाकिस्तान को कोसता था और वहां से कहीं दूर किसी दूसरे मुल्क में जाने की फ़िराक़ में रहता था. एक दिन उस पर बिजली का तार गिरा और वह मौत की गिरफ़्त में आने से बाल-बाल बच गया. वह भी इसलिए कि ठीक उसी वक़्त शहर में बिजली चली गई और वह उस तार की चपेट से बाहर आ गया. बिजली के करंट ने उसकी यादाश्त पर असर डाला और उसके जेहन से पाकिस्तान के लिए मौजूद नफ़रत ग़ायब हो गई. उसके मुंह से आवाज़ निकली, पाकिस्तान ज़िंदाबाद. यह एक वतनपरस्त लड़के की कहानी थी. या फिर आप कह सकते हैं कि हम इन संदेशों की मदद से अपनी ग़लतियों को जायज़ ठहराने की कोशिश कर रहे हैं. अब मुझे एक और एसएमएस का इंतजार है जिसमें जीएचक्यू पर हुए आतंकी हमले को जायज़ ठहराया गया हो, जो इस्लामाबाद की सबसे सुरक्षित समझी जाने वाली जगह की सुरक्षा व्यवस्था की कलई खुलने को जायज़ ठहरा सके, जो अमेरिका के कैरी लॉगर बिल को जायज़ करार दे या फिर स्वात और पेशावर के हालात को सही बयान करने के साथ-साथ बलूचिस्तान के हालात और वहां मौजूद नफ़रत को भी जायज़ करार दे.

इस ख़बर के मुताबिक़, सेना की वर्दी में छह आतंकवादी शनिवार की सुबह जीएचक्यू के गेट नंबर एक से घुसने की कोशिश करते हैं. गेट पर तैनात अधिकारियों ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो वे गेट नंबर एक के चेक पोस्ट पर पहुंच जाते हैं और वहां मोर्चाबंदी कर सुरक्षाकर्मियों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं. जवाबी फायरिंग में चार आतंकवादी मारे जाते हैं और दो आतंकवादी फायरिंग के दौरान ही भाग निकलने में कामयाब हो जाते हैं. ख़ासा सुरक्षित माने जाने वाले इस इलाक़े में आतंकवादियों का हमला ऐसे वक़्त में हुआ, जबकि पाकिस्तान की सेना अफगानिस्तान से लगी उत्तर-पूर्वी सीमा पर आतंकवादियों के ख़िलाफ़ एक अहम मोर्चाबंदी करने की तैयारी कर रही थी. हथियारों से लैस आतंकवादी पाकिस्तानी सेना की नंबर प्लेट लगी एक सफेद वैन में हेडक्वार्टर के गेट तक पहुंचने में कामयाब होते हैं, फायरिंग के लिए मोर्चाबंदी करते हैं और जब सुरक्षाकर्मी जवाबी फायरिंग करते हैं तो वे हैंडग्रेनेड का इस्तेमाल भी कर डालते हैं. फायरिंग का यह सिलसिला चालीस मिनटों तक चलता रहता है. सेना के राइफल से लैस हेलीकॉप्टर इलाक़े की छानबीन में जुट गए और कमांडो दस्ते ने आतंकवादियों की लाशें अपने क़ब्ज़े में ले ली और घटनास्थल से हटा भी दी. इस हमले में बचकर भाग निकलने में कामयाब हुए चार आतंकवादियों ने तीन सुरक्षाकर्मियों को बंधक बना लिया. सेना की तरफ़ से अगले ही दिन बयान आया कि बाइस घंटों तक चले एक अभियान में सेना ने तीन आतंकवादियों को मार गिराया और एक को घायल हालत में ज़िंदा गिरफ़्तार कर लिया है. इस ऑपरेशन में बंधक बनाए गए तीन सुरक्षाकर्मियों की ज़िंदगी नहीं बचाई जा सकी.

आतंकवादियों ने जिस घर में सुरक्षाकर्मियों को बंधक बनाया था, उसके मकान मालिक को गिरफ़्त में लिया गया है. बताया जा रहा है कि आतंकवादियों ने हमले के लिए हेडक्वार्टर के बगल में ही एक कमरा किराए पर लिया था. यह मकान मॉडल टाउन हूमक के ढोक अवान इलाक़े में है जो कि सिंहाल पुलिस के क्षेत्र में आता है. पुलिस मान रही है कि आतंकवादी इसी मकान को बेस के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे और हमले के लिए इसी मकान से गाड़ी में सवार होकर हेडक्वार्टर पहुंचे थे. इस मकान पर छापा मारने वाले अधिकारियों को मकान खुला मिला और वहां से सेना अधिकारियों की कई जोड़ी वर्दियां बरामद की गई. इसके अलावा इस मकान से कई संवेदनशील इलाक़ों के नक़्शे, डेटोनेटर, बारूद, पहचान पत्र जैसी चीज़ें बरामद हुई हैं. इस घर में दो जोड़े जींस की पैंट, दस जोड़े सलवार कमीज़ और चप्पलें बरामद हुईं. पुलिस के हाथ किराएदारी की रसीद भी मिली जिसके बिनाह पर प्रॉपर्टी डीलर को भी हिरासत में ले लिया गया है. इस मकान को दस हज़ार रुपये प्रति माह के दर पर किराए पर लिया गया था. इस रसीद से यह भी साफ़ होता है कि हमलावर इस मकान में पिछले बीस-पच्चीस दिनों से रह रहे थे. यह भी अंदाज़ा लगया जा रहा है कि इस मकान में रहने वालों की संख्या दस से बारह के बीच थी. चश्मदीदों के मुताबिक़, इस मकान में रहने वालों में किसी की दाढ़ी नहीं थी और कुछ लोगों ने मूंछ रखी हुई थी. हमले से एक रात पहले इस मकान में काफी गहमागहमी थी और कई लोग स्पोर्टस गाड़ियों में यहां आते-जाते देखे गए थे.

अभी तक किसी आतंकवादी गुट ने इस हमले की ज़िम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन सेना मान रही है कि इस हमले के पीछे तालिबान का हाथ है. एक हफ़्ता पहले तालिबान का नया मुखिया हकीमुल्लाह मेहसूद दक्षिणी वज़ीरिस्तान में एक प्रेस कांफ्रेस के ज़रिए कह चुका था कि पाकिस्तानी तालिबान अगले कुछ दिनों में सेना, सरकार और अन्य निशानों पर कई हमले करेगा. हकीमुल्लाह की इस धमकी के बाद पाकिस्तान के आंतरिक सुरक्षा मंत्री रहमान मलिक ने कहा था कि अब तालिबानी गढ़ दक्षिणी वज़ीरिस्तान पर हमला ज़रूर किया जाएगा. पाकिस्तान सरकार ने यह साफ़ कर दिया है कि दक्षिणी वज़ीरिस्तान में आतंकवाद के ख़िलाफ़ चलाए जाने वाले अभियान को इस तरह के हमले नहीं रोक सकते. सरकार आतंकवादियों के ख़िलाफ़ और भी सख्त कार्रवाई के लिए संकल्प कर चुकी है. अमेरिका और उत्तरी गठबंधन के अन्य देश भी लगातार पाकिस्तान से उन गुटों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं जो अफ़ग़ानिस्तान में अमेरिकी सेना के लिए ज़िम्मेदार है. सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल अतहर अब्बास ने कहा कि आतंकवादियों ने लगभग बीस लोगों का बंधक बना लिया था. आतंकवादियों ने बुलेटप्रूफ जैकेट भी पहन रखी थीं, लेकिन इससे पहले कि वे ख़ुद को बारूद से उड़ाते, सेना के जवानों ने उन्हें गोली से मार गिराया. अतहर अब्बास का कहना है कि जिन लोगों को रिहा कराया गया उसमें सेना के जवानों के अलावा कुछ नागरिक भी शामिल थे. इस अभियान में तीन बंधकों के साथ चार आतंकवादी भी मारे गए.

आंतरिक सुरक्षा मंत्री रहमान मलिक ने कहा कि इस हमले से पाकिस्तान सेना दक्षिणी वज़ीरिस्तान में प्रस्तावित ऑपरेशन को बंद नहीं करेगी. दरअसल, पेशावर दक्षिणी वज़ीरिस्तान का एक प्रमुख शहर है और पिछले कुछ दिनों से आतंकवादी हमलों का निशाना बनता रहा है. इन हमलों को अलक़ायदा और तालिबान के नेटवर्क के ज़रिए अंजाम दिया जाता रहा. इस हमले से तालिबान महज़ पाकिस्तान सेना को जल्द से जल्द अभियान शुरू करने के लिए मजबूर कर रहा है. पिछले चार महीनों में यह छठा आतंकी हमला है जिसमें कुल 77 लोगों की मौत हो चुकी है. यह साफ़ ज़ाहिर हो रहा है कि तालिबान ने पाकिस्तानी ठिकानों पर हमलों को बैतुल्लाह मेहसूद की मौत का बदला लेने के लिए तेज़ कर दिया है.

प्रधानमंत्री गिलानी ने हमले की निंदा करते हुए कहा है कि पाकिस्तान सरकार आतंकवादियों के ख़िलाफ़ चलाए जा रहे अभियान के लिए कटिबद्ध है. सेना अब स्वात घाटी में अपने अभियान के आख़िरी चरण पर है.

इससे पहले तालिबान ने 5 अक्टूबर को इस्लामाबाद में संयुक्त राष्ट्र के एक कार्यालय पर हमला किया था, जिसमें पांच कर्मचारी मारे गए थे. जिस तरह से तालिबानी हमले बढ़ रहे हैं, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि तालिबान अपने पूर्व मुखिया बैतुल्लाह मेहसूद की मौत के बाद भी कमज़ोर नहीं हुआ.

सेना मुख्यालय पर तालिबान के इस हमले के दो मक़सद हैं. पहला तो यह कि जो पाकिस्तान से आतंकवाद का सफ़ाया चाहते हैं वे ख़ुद को कमज़ोर समझें और दूसरा यह कि पाकिस्तान आतंकवाद के ख़िलाफ़ अपने युद्ध को बंद कर दे. लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर पाकिस्तान सेना का मुख्यालय ही आतंकी हमलों का शिकार बन रहा है, तो भला पाकिस्तान की इस सरज़मीं पर सुरक्षित कौन है? इसके साथ ही सेना मुख्यालय पर किए गए इस हमले में वह सभी तथ्य मौजूद हैं जिससे साफ़ होता है कि एक सोची समझी रणनीति के तहत तालिबान ने इस हमले को अंजाम दिया है.

लेखिका पाकिस्तान की युवा पत्रकार हैं।

feedback@chauthiduniya.com

ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों पर हमले की हक़ीक़त

फोटो– पीटीआई

31 मई को मेलबोर्न में हुए भारतीय छात्रों पर हमले के विरोध में प्रदर्शन.

राहुल मिश्र

ऑस्ट्रेलिया जाकर पढ़ाई करने की सोचने वाले भारतीय छात्र ऑस्ट्रेलियाई शहरों में भारतीय छात्रों पर हो रहे हमलों से विचलित हैं. उनको लगता है कि वहां भारतीय मूल के छात्रों पर रंगभेद के चलते हमले हो रहे हैं. एक छात्र जिसे हाल ही में उच्च शिक्षा के लिए आस्ट्रेलिया जाना था, उसकी भी यही राय थी. भारतीय मूल के शोधकर्ता डॉक्टर आशुतोष मिश्र, जिन्हें अभी कुछ ही दिनों पहले ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता मिली है, इस बात की पुष्टि करते हैं. शोध के लिए ऑस्ट्रेलिया गया छात्र छह महीनों के प्रवास के बाद वापस आकर इसकी हक़ीक़त बताई. उसकी बातें बिल्कुल अलग थीं.

ऑस्ट्रेलिया की ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी में शोध कर रहे छात्र स्टीफन इलिज और भारतीय मूल के प्रोफेसर डॉक्टर आशुतोष मिश्र भारतीयों पर हमले की असलियत की तह तक जाने की कोशिश करते हैं. ग़ौरतलब है कि स्टीफन इलिज वहां हो रहे हमलों की जांच से भी जुड़े हैं. इलिज शोध अध्ययन से पहले पंद्रह वर्षों तक ऑस्ट्रेलिया पुलिस में भी काम कर चुके हैं. उनका कहना है कि भारत सरकार ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय छात्रों की ज़रा भी परवाह नहीं कर रही है. अगर ऑस्ट्रेलिया में रंगभेद है तो सरकार भारतीय छात्रों को पढ़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया क्यों जाने दे रही है? अगर ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों की पढ़ाई-लिखाई अंतरराष्ट्रीय स्तर की है और भारतीय छात्र वहां से पढ़ाई के बाद नौकरी-बाज़ार में सशक्त दावेदारी पेश करते हैं, तो क्या भारत सरकार की यह ज़िम्मेदारी नहीं बनती है कि वह बाहर जाने वाले छात्रों का समुचित आंकड़ा अपने पास रखे. क्या भारतीय छात्र उसी विश्वविद्यालय में दाख़िला लेते हैं, जिसमें दाख़िले के लिए वह भारत से चले थे? क्या वह अपने द्वारा बताई हुई जगह पर ही रह रहे होते हैं या फिर उसे किसी तरह की धोखाधड़ी का सामना करना पड़ता है? आशुतोष के मुताबिक़, ऑस्ट्रेलिया में तीन तरह के भारतीय रह रहे हैं. पहले तो वे हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में बतौर नागरिक अपना गुज़र-बसर कर रहे हैं. उनके पास बढ़िया नौकरी होती है, रहने के लिए अच्छा घर होता है और उनके रहन-सहन का तरीक़ा काफी कुछ ऑस्ट्रेलियाई लोगों से मिलता-जुलता होता है. इन लोगों को ऑस्ट्रेलिया के नियम और क़ानून को मानने में कोई परेशानी नहीं होती. दूसरे तरह के भारतीय वे हैं, जो हाल-फ़िलहाल शिक्षाग्रहण करने ऑस्ट्रेलिया गए होते हैं. उन्हें वहां एक अच्छे विश्वविद्यालय में दाख़िला मिला होता है. वे शहर की किसी अच्छी बस्तियों या फिर विश्वविद्यालय परिसर में ही रहते हुए पढ़ाई लिखाई कर रहे होते हैं. यह वैसे भारतीय नागरिकों का तबका है, जिसे देर-सबेर ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता मिल जाने की उम्मीद होती है. पढ़ाई पूरी होने के बाद अच्छी नौकरी मिलना भी लगभग तय होता है. इस तबके के छात्र वहां के नियम और क़ानून को बख़ूबी निभा रहे होते हैं.

ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी के स्टीफन इलिज और डॉ आशुतोष मिश्र.

वहां रह रहे इन दोनों तबकों के उलट, ऑस्ट्रेलिया में एक और भारतीय तबका है. आशुतोष के मुताबिक़, इंटरनेट के इस दौर और विश्वविद्यालयों के व्यवसायीकरण के बाद भारतीय छात्रों में ऑस्ट्रेलिया जाकर पढ़ना एक क्रेज बन चुका है. यह तीसरा तबका इसी क्रेज की देन है. इस श्रेणी के छात्र ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों में दाख़िला कराने वाले दलालों की मदद से ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाते हैं. देश के कई बड़े शहरों में ऐसे दलालों की कई दुकानें एजुकेशन काउंसलिंग के नाम पर चलती हैं. अख़बारों में ऐसे दलालों के बड़े-बड़े विज्ञापन स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया की तर्ज़ पर छपते हैं. ज़ाहिर है, ऐसे विज्ञापनों में देश भर के छात्रों को आकर्षित करने की शक्ति होती है. शिक्षा के इन दलालों के पास पहुंचते ही इन छात्रों को यह बता दिया जाता है कि अगर उनकी जेब में पैसे हैं तो ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय में दाख़िला आसानी से हो सकता है. हक़ीक़त भी कुछ ऐसी ही है- पैसा फेंको, तमाशा देखो. स्टीफन इलिज ने पूर्व में हुए सभी हमलों के शिकार और हमलावरों के पक्ष से बातचीत की. वह इन हमलों में किसी तरह के रंगभेद की झलक नहीं देखते. उनका मानना है कि जिन छात्रों पर हमला हुआ है, कहीं न कहीं उन छात्रों की भी ग़लती रही है. इलिज कहते हैं कि शिकार हुए सभी छात्र डॉक्टर आशुतोष के अनुसार, तीसरे वर्ग के भारतीय हैं. इन लोगों को भारत में ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय में दाख़िले का सपना दिखाकर ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया पहुंचने पर इनको न तो कहीं दाख़िला मिला और न ही इनमें अपनी शिकायत दर्ज़ कराने का हौसला आया. ज़्यादातर छात्र काफी जमा पूंजी लगाकर ऑस्ट्रेलिया पहुंचते हैं, लेकिन अपने ठगे जाने के अहसास के बाद इस डर से परेशान हो जाते हैं कि उन्हें वापस भारत भेज दिया जाएगा. इसी डर की वजह से ऐसे छात्र ऑस्ट्रेलियाई पुलिस के सामने शिकायत दर्ज़ नहीं कराते और ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं. नियम क़ानून इनके लिए मायने नहीं रखता. बाज़ारों में इनके मनचले रवैए से लोग परेशान रहते हैं और यह परेशानी एक आक्रोश का रूप ले लेती है. इस आक्रोश में ऑस्ट्रेलियाई लोगों के पास संवाद का कोई विकल्प नहीं बचता और वे मारपीट कर फ़ैसला करना ही मुनासिब समझते हैं. ऐसे में भारत सरकार के सामने सवाल उठाया जा सकता है कि रंगभेद के आरोपों की आड़ में वह दाख़िले की दलाली कर रहे लोगों को नज़रअंदाज़ क्यों कर रही है? क्या सरकार ऑस्ट्रेलिया जाने वाले छात्रों को ऐसी धोखाधड़ी से बचाने के लिए कोई प्रयास कर रही है या फिर पैसा फेंक-तमाशा देख वाले खेल में वह भी महज़ एक तमाशबीन है?

rahul@chauthiduniya.com

सर्दियों की शुरुआत से ही कुछ लोगों को परेशानी का अहसास होने लगता है. अधिक ठंड बच्चे, बुज़ुर्ग या जवान सभी के लिए किसी न किसी रूप में नुक़सानदायक है.

सर्दी में सुखद स्वास्थ्य

रीतिका सोनाली

सर्दियों की शुरुआत से ही कुछ लोगों को परेशानी का अहसास होने लगता है. अधिक ठंड बच्चे, बुज़ुर्ग या जवान सभी के लिए किसी न किसी रूप में नुक़सानदायक है. इन दिनों जोड़ों के दर्द, नजला, कफ, साइनस साइटिस, इंफ्लुएंजा, वायरल, दमा, हार्ट अटैक, हायपोथलमिस जैसी सर्दियों से प्रभावित होने वाली बीमारियां ज़्यादा परेशान करती हैं. इसके अलावा त्वचा संबंधी रोगों से परेशान और पहले से बीमार चल रहे लोगों की दिक़्क़तें बढ़ जाती हैं. इन तमाम परेशानियों से बचने के लिए ज़रूरी है कि इस मौसम में आप ख़ुद को स्वस्थ रखें. दिल्ली स्थित महाराजा अग्रसेन अस्पताल की एएमएस डॉ. ममता जैन के अनुसार, कुछ बीमारियां ऐसी हैं, जिनका हमला सबसे ज़्यादा सर्दियों के मौसम में होता है. ऐसे में बचाव ही इनसे होने वाली परेशानियों का उपाय है.

हायपोथाइलमस

सामान्य तौर पर शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, लेकिन यदि ठंड की वजह से तापमान धीरे-धीरे कम होने लगे तो इसे हायपोथाइलमस कहते हैं. यह तब और भी ख़तरनाक हो जाता है जब शरीर की रोग प्रतिरोधी क्षमता कम हो जाती है और व्यक्ति इस बीमारी के चपेट में आ जाए. अगर व्यक्ति के शरीर का तापमान 36 डिग्री से कम हो, तब उसे सांस लेने में परेशानी होती है और तापमान 35 डिग्री से कम हो जाए, तब यह रोग जानलेवा हो जाता है. चूंकि यह बीमारी तापमान घटने की वजह से होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा ठंड से बचकर रहें. ठंडी चीज़े जैसे आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक आदि का सेवन न करें. गर्म कपड़े पहनें और खानपान का विशेष ध्यान रखें.

दमा

इसमें आमतौर पर सांस लेने में तकलीफ़ होती है. ठंड की वजह से यह तकलीफ़ और भी ज़्यादा बढ़ जाती है. ऐसे में मरीज ठंड से बचें, धुंध छंटने पर ही बाहर निकलें, वक्त पर दवाएं और इन्हेलर लें. सिर, हाथ और पैर को ढक कर रखें तथा गुनगुने पानी से नहाएं. सांस फूलने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाएं.

अर्थराइटिस

ठंड बढ़ने के साथ ही घुटने और जोड़ों का दर्द बढ़ने लगता है. यह ख़ासकर बुज़ुर्गों में देखा जाता है. शरीर के जोड़ों में साइकोवियल फ्लुइड मौजूद रहता है जो हड्डियों के बीच ग्रीस का काम करता है. लेकिन बढ़ती उम्र के साथ इसका बनना कम हो जाता है और जोड़ों में दर्द होता है. दर्द और भी ज़्यादा तब बढ़ जाता है, जब जोड़ों में सख्ती ज़्यादा होती है. अर्थराइटिस की बीमारी वायरल, इंफेक्शन और हृदय संबंधी समस्याओं के कारण होती है जिसे आस्टियो अर्थराइटिस कहते हैं.

ऐसा जहां युवाओं में बदलती जीवनशैली के कारण हो रहा है, वहीं बुज़ुर्गों में इसका असर उम्र के साथ-साथ बढ़ रहा है. इससे बचाव के लिए हमेशा गर्म कपड़े पहनें, घर का तापमान 70-75 डिग्री फारेनहाइट के बीच रखें, सूर्योदय के बाद ही घर से निकलें, ख़ूब व्यायाम करें और देर तक बैठे न रहें. यही नहीं, प्रोटीनयुक्त भोजन ज़्यादा लें, दर्द कम करने का मरहम व दवा नियमित लें, शराब व सिगरेट से बचें और वक़्त पर मसाज लें.

हृदय संबंधी रोग

ठंड के मौसम में हार्ट अटैक की आशंका 30 फ़ीसदी बढ़ जाती है. सर्दी का असर बढ़ने पर हार्ट के पंप की गति कम हो जाती है, जिससे अचानक हार्ट अटैक हो सकता है. ठंड से बचाव के साथ ही हृदय की धड़कन व रक्तचाप दोनों का बढ़ना ज़रूरी है और इस दौरान ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा होती है. सर्दी शुरू होने से पहले अपना ब्लड चेकअप ज़रूर कराएं, रक्तचाप में बदलाव आते ही डॉक्टरी परामर्श से जीवनशैली में बदलाव ज़रूर लाएं. व्यायाम करें और ज़्यादा ठंड से बचें.

त्वचा संबंधी रोग

इस मौसम में तेज़ और ठंडी हवाओं के असर से त्वचा रुखी हो जाती है, मुंह लाल हो जाता है, ऐड़ियां फट जाती हैं और पैर में छाले पड़ जाते हैं. इसे फ्राफसबाइट कहते हैं. इससे बचाव के लिए मुंह को ढक कर रखें और घर से बाहर निकलने पर शरीर को पूरी तह से ढक लें. हाथ-पैर व चेहरे पर मॉयस्चराइजर युक्त क्रीम लगाएं, नमी के लिए सबसे बेहतर है एलोवो युक्त क्रीम लगाना.

ओस्टियोपीनिया

तीस की उम्र आते-आते महिलाओं में ओस्टियोपीनिया यानी हल्की ओस्टियोपोरोसीस का असर देखा जाता है. इस बीमारी में हड्डी में मौजूद खनिज लवण की मात्रा कम हो जाती है जिससे आगे चलकर ओस्टियोपोरोसीस हो जाता है. इसकी वजह है खानपान का बदलता शौक़, जिससे शरीर में ओमेगा-थ्री फैटी एसिड और कैल्शियम की कमी हो जाती है. इसके अलावा शराब व सिगरेट का सेवन और व्यायाम न करना भी ख़ास कारण हैं. हाइपोथायरॉडिज्म और दूसरे मेटाबोलिक बीमारियों, जैसे डायबिटीज़ के रोगियों को भी ओस्टियोपोरोसीस होने की आशंका बढ़ जाती है. इस मौसम में ठंड ज़्यादा होने की वजह से हवा का दबाव बढ़ता है और परिणामस्वरूप हड्डियों पर इसका असर होता है जिससे दर्द बढ़ने लगता है. इससे बचने के लिए व्यायाम करें, संतुलित आहार लें और शराब व सिगरेट का सेवन न करें. ख़ासकर वैसे व्यायाम करें, जिससे हड्डियां मज़बूत बनें.

साइनस साइटिस

डॉ. अक्शिमा मारवाह के अनुसार चुपचाप चले आने वाले इस रोग से आज लगभग हर आठवां व्यक्ति परेशान है. यह लंबे वक़्त तक मरीज का साथ पकड़े रखता है. साइनस चेहरे और नाक के अंदर पाई जाती है. साइनस बाहर के प्रदूषण को रोकने और शरीर व बाहर के तापमान का संतुलन बनाने का काम करता है. जब किसी एलर्जी या सर्दी की वजह से इनमें सूजन आ जाती है, तब उसे साइनस साइटिस कहते हैं. सूजन आने पर शरीर में हरारत रहती है और सिरदर्द महसूस होने लगता है. नाक से पतला द्रव निकलने लगता है, छींके शुरू हो जाती हैं, बढ़ जाने पर नाक से पीला और हरा द्रव निकलने लगता है और आंख में कीचड़ आने लगता है. इसके साथ ही सूंघने की शक्ति भी कम हो जाती है और नाक के दोनों छेद बंद हो जाते हैं. इस स्थिति का मुख्य कारण है वायरल व बैक्टीरियल इंफेक्शन और शरीर की प्रतिरोधी क्षमता में कमी होना. इससे बचाव का सबसे उपयुक्त उपाय है कि प्रतिदिन रात को सोते वक़्त गर्म पानी की भाप लेना. बेहतर यह होगा कि उसमें विक्स वैपोरब की कुछ मात्रा डाल ली जाए. सुबह हरी घास पर टहलना और ख़ुश रहना भी बहुत ज़रूरी है. तनाव लेने पर भी यह रोग बढ़ जाता है. सर्दियों में यह ज़्यादा परेशान करता है, इसलिए नजला से बचने की कोशिश करें. सर्दी न लगने पाए. इसलिए बाहर निकलने से पहले शरीर के सभी हिस्सों को गर्म कपड़ों से ढंक लें और ठंडी हवा से बचें. साइनस साइटिस हो जाने पर डॉक्टरी परामर्श से एंटी एलर्जिक लें.

कमर दर्द-पीठ दर्द

यह परेशानी आराम की कमी, काम करने का दबाव और ग़लत बैठने-सोने की वजह से होती है. कई बार यह किडनी या किसी अन्य अंग में परेशानी की वजह से भी होती है. इससे बचने का सबसे बेहतर तरीक़ा यह है कि नियमित व्यायाम ज़रूर करें. ठंड में हवा के दबाव की वजह से यह रोग बढ़ जाता है, इसलिए इस मौसम में ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत है. ठंड से बचें, ज़्यादा भारी चीज़ न उठाएं, फिटनेस एक्सपर्ट की राय लेकर व्यायाम करें. कैल्शियम-पोटाशियमयुक्त भोजन लें.

वायरल-इंफेक्शन

जाड़े के मौसम में वायरल बुख़ार और इंफेक्शन भी हो सकता है. दिल्ली स्थित संजीवनी अस्पताल के डॉ. पी के अग्रवाल के मुताबिक़, फेफड़ों की तकलीफ़, खांसी, सर्दी, बुख़ार, नाक बहना और निमोनिया आदि भी परेशान करते हैं. सर्दी में अगर नाक बहने लगे तो दो-चार दिनों तक उसे बहने दें. इससे ज़्यादा हो और स्वत: नियंत्रित न हो, तब डॉक्टरी उपचार कराएं. छोटे बच्चों में नाक बहने की प्रक्रिया ज़्यादा देखी जाती है, इसलिए उनका ख़ास ख्याल रखें. कुछ भी ठंडा खिलाने से परहेज़ करें, क्योंकि ज़्यादा नाक बहने पर बैक्टीरियल इंफेक्शन हो सकता है जो बहुत ज़्यादा परेशान करता है.

ritika@chauthiduniya.com

सहारा आयुर्वेद का

आयुर्वेद को सदियों से जीवनरक्षक के रूप में देखा गया है और हमेशा इसे किसी भी प्रकार की बीमारी के इलाज के काम में लिया जाता रहा है. डाबर रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर के आयुर्वेद रिसर्च हेड डॉक्टर चंद्रकांत कत्याल के अनुसार, प्राकृतिक औषधि, आहार और विहार से हर प्रकार के रोग दूर रहते हैं. वायरस और बैक्टीरियल इंफेक्शन की वजह से बुखार, गले में दर्द, नाक बहना, बदन दर्द, सिरदर्द, कंपकपी और थकान आदि की शिकायतें होती हैं. इससे बचने के लिए आयुर्वेद में कई जड़ी-बूटियां हैं जैसे उड़ीसी, आंवला और अश्वगंधा आदि. यह सारी दिक्कतें शरीर की रोग प्रतिरोधी क्षमता कम होने की वजह से होती हैं. इससे बचने के लिए 20-25 ताजे तुलसी के पत्तों को पीसकर ख़ाली पेट दिन में दो बार लें. चाय में अदरक और काली मिर्च मिलाकर लेने से भी फ़ायदा होता है. इसके अलावा च्यवनप्राश का सेवन सुबह शाम पंद्रह-पंद्रह ग्राम करें. रात को दही कभी न लें. ख़ूब पानी पिएं. इंफेक्शन से बचने के लिए यह ध्यान रखें कि कफ में वृद्धि न हो, वरना वायरस और बैक्टीरिया का हमला आसानी से होता है. साथ ही नाक बंद न हो, इसके लिए सोते वक़्त नाक में दो बूंद सरसों का तेल डालें. कभी भी नाक बंद होने की स्थिति आए तो बिना वक़्त गंवाए गर्म पानी की भाप लेनी चाहिए.

कसरत से सर्दी हो स्वास्थ्यकारी

इन दिनों ख़ुद को स्वस्थ रखने के लिए सबसे आसान तरीक़ा है, कसरत. व्यायाम करने से शरीर में इंडोफिन नामक हार्मोन निकलता है, जिससे हमें ख़ुशी का अहसास होता है. इसके अलावा ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा हो जाता है, इंफेक्शन की आशंका कम हो जाती है, शरीर का प्रतिरोधी तंत्र मज़बूत होता है. गर्मियों की तुलना में सर्दियों का मौसम ज़्यादा फलदायी होता है. इन दिनों भुना-तला-छना भी छककर खा सकते हैं. वह भी बिना किसी ख़ास परेशानी के, लेकिन तब जबकि आप नियमित कसरत करें. योग भी कसरत का ही एक रूप है.

राशिफल

(19 से 25 अक्टूबर तक)

मेष (21 मार्च से 20 अप्रैल)
प्रियजनों का पूरा सहयोग मिलेगा. लेन-देन के मामलों पर चल रहे प्रयास सफल होंगे. यदि आप व्यावसायिक प्रशिक्षण की तैयारी कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी. निकट के संबंध मधुर होंगे.

वृष (21 अप्रैल से 20 मई)
धन, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा की दिशा में चल रहे प्रयास सफल होंगे. आप अकारण ही खिन्नता का अनुभव करेंगे. आलस्य एवं प्रमाद की स्थिति बनी रहेगी. रुपये पैसे की लेनदेन में सावधानी बरतने की आवश्यकता है.

मिथुन (21 मई से 20 जून)
संबंधों में मधुरता आएगी. कुछ ऐसा होगा जिसका आपको लाभ मिलेगा. व्यक्ति विशेष से संबंध मधुर होंगे. पारिवारिक जनों का भरपूर सहयोग मिलेगा. संतान के दायित्व की पूर्ति होगी.

कर्क (21 जून से 20 जुलाई)
किसी मूल्यवान वस्तु को पाने की आपकी अभिलाषा पूरी होगी. उपहार व सम्मान का लाभ होगा. देवदर्शन के योग हैं. सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी. व्यस्तता के बावजूद सुखद मनोरंजन का अवसर मिलेगा.

सिंह (21 जुलाई से 20 अगस्त)
कार्यक्षेत्र में किए जा रहे प्रयास सफल होंगे. विवादित मामलों पर चल रहे प्रयास सफल होंगे. ऐसा कुछ भी न करें जिससे आपको व्यर्थ की परेशानी का सामना करना पड़ जाए.

कन्या (21 अगस्त से 20 सितंबर)
आय को नए अवसर सामने आएंगे. अत्यधिक विश्वास आपको कष्ट दे सकता है. पारिवारिक जनों से आर्थिक सहयोग लेने में सफलता प्राप्त करेंगे. मेलजोल की स्थिति बनी रहेगी.

तुला (21 सितंबर से 20 अक्टूबर)
विरोधी सक्रिय रहेंगे, इसलिए यथासाध्य किसी प्रकार का ख़तरा मोल न लें. संतान के दायित्व की पूर्ति होगी. आर्थिक मामलों में वांछित सफलता मिलेगी. उन्नति का नए रास्ते खुलेंगे.

वृश्चिक (21 अक्टूबर से 20 नवंबर)
संबंधित अधिकारी से कार्य निकालने में आप सफल होंगे. पत्राचार करते समय सावधानी बरतना ठीक रहेगा. आपको व्यर्थ की भागदौड़ करनी पड़ सकती है. आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी. कार्य का बदलाव आपको लाभ देगा.

धनु (21 नवंबर से 20 दिसंबर)
आमोद-प्रमोद के अवसरों का लाभ उठाएंगे. ससुराल पक्ष से कोई अप्रिय समाचार मिल सकता है. परिवार के अन्य सदस्यों का भरपूर सहयोग मिलेगा. यात्रा करनी पड़ सकती है.

मकर (21 दिसंबर से 20 जनवरी)
जारी प्रयास सफल होगा. शिक्षा के क्षेत्र में पिता व अध्यापक का भरपूर सहयोग मिलेगा. दूसरों के मामले में हाथ न डालें. रहन-सहन के स्तर में सुधार आएगा. पद और प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

कुंभ (21 जनवरी से 20 फरवरी)
व्यवसायिक मामलों पर चल रहा प्रयास सफल होगा. कोई सोच पीड़ा देगी. संतान के व्यवहार के प्रति चिंतित हो सकते हैं. परिवर्तन के लिए अभी प्रयास व्यवधान दे सकता है. प्रणय संबंध मधुर होंगे.

मीन (21 फरवरी से 20 मार्च)
पारिवारिक जीवन सुखमय होगा. उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा. आपका डूबा हुआ रुपया वापस मिलेगा, इसलिए प्रयास जारी रखें. आर्थिक स्थिति मज़बूत होगी. सामाजिक कार्यों की तरफ़ आपका रुझान बढ़ेगा.

ज्योतिषाचार्य पं. सुदर्शन

परमपिता परमात्मा की लीला अपरंपार है. कैसे? यही जानने के लिए पिछले दिनों रामलीला मैदान और सीरीफोर्ट ऑडिटोरियम में हज़ारों लोग जुटे. नीचे पेश है एक रिपोर्ट.

बंद हो किताबों की सरकारी ख़रीद

अनंत विजय

इस वर्ष के साहित्य के नोबेल पुरस्कार का ऐलान हुआ और रोमानिया में पैदा हुई जर्मन लेखिका हेर्ता म्यूलर को यह सम्मान मिला तो उनके लेखन के बारे में जानने की इच्छा हुई. काम से वक़्त निकालकर दिल्ली और आसपास की पुस्तकों की दुकानों की ख़ाक छानी, लेकिन हेर्ता म्यूलर की कोई किताब कहीं नहीं मिल पाई. तक़रीबन हर जगह पुस्तक विक्रेताओं ने कहा कि कुछ दिनों में पुस्तक उपलब्ध हो पाएगी. निराश होकर वापस लौट आया, लेकिन कुछ सवाल बेहद परेशान करने वाले रहे और लगातार मुंह बाए मेरे सामने खड़े हैं. पहला तो यह कि हमारे समाज में किताबों को लेकर उपेक्षा भाव क्यों है? उपेक्षा भाव मैं इसलिए कह रहा हूं कि राजधानी दिल्ली, जिसे दूरदराज के साहित्य प्रेमी और लेखक साहित्य की भी राजधानी कहते हैं, में भी किताबों की दुकान ढूंढने में आपको श्रम करना पड़ेगा. ढूंढे से किताब नहीं मिल पाएगी. कोई भी ऐसी दुकान नहीं, जहां आप इस विश्वास के साथ जा सकें कि आपकी मनपसंद किताब आपको मिल जाएगी. अगर हम पुस्तकों की उपलब्धता की बात करें तो दिल्ली और आसपास के शहरों के हालात बेहद निराशाजनक हैं. पूरी दिल्ली में किताबों की दुकानें उंगलियों पर गिनी जा सकती हैं और आपको उन तक पहुंचने के लिए कई किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी. अगर आप तमाम संघर्षों के बाद किताबों की दुकान तक पहुंच भी जाते हैं तो आपको अंग्रेजी की किताबें तो मिल जाएंगी, लेकिन हिंदी की किताबें नहीं मिल पाएंगी. हिंदी की किताबों के लिए आपको प्रकाशकों से संपर्क करना पड़ेगा या फिर दिल्ली के दरियागंज इलाक़े की ख़ाक छाननी होगी. दरियागंज का आलम यह है कि आप अगर वहां अपनी कार से चले गए तो कार अक्षत वापस नहीं आ सकती, उस पर खरोंच लगना तय है. साथ ही गाड़ी पार्क करने में आपको इतनी मशक़्क़त करनी पड़ेगी कि किताब पढ़ने का भूत आपके सिर से उतर जाएगा. यह हाल सिर्फ़ पुस्तकों को लेकर ही नहीं है, पत्र- पत्रिकाएं भी सहज सुलभ उपलब्ध नहीं हैं.

सवाल यह उठता है कि इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? क्या पूरा हिंदी समाज इसके लिए ज़िम्मेदार है या फिर प्रकाशकों को पाठकों की फ़िक्र ही नहीं है. दरअसल मुझे लगता है कि इसके लिए प्रकाशकों के साथ-साथ वामपंथी विचारधारा के लेखकों और प्रकाशकों पर उनका प्रभाव ज़िम्मेदार है. न तो लेखक और न ही प्रकाशक किताबों को प्रोडक्ट की तरह समझकर व्यवहार करते हैं. प्रोडक्ट नाम सुनते ही वामपंथी लेखक ऐसे भड़कते हैं जैसे लगता है कि किसी सांड को लाल कपड़ा दिखा दिया गया हो. प्रोडक्ट शब्द से उनको बाज़ारवाद और पूंजीवाद की बू आने लगती है और वह इसके ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं. उन्हें लगता है कि अगर पुस्तकों को प्रोडक्ट की श्रेणी में रख दिया जाएगा तो उनका श्रम व्यर्थ चला जाएगा, उनकी मेहनत पर पूंजीवाद और बाज़ारवाद पानी फेर देगा, लेकिन प्रोडक्ट वही तो होता है जिस पर मेहनत की जाती है, जिसके उत्पादन पर पैसा ख़र्च किया जाता है और उससे कुछ लाभ की अपेक्षा की जाए. लेखक भी कई महीनों तक किसी कृति पर मेहनत करते हैं. फिर प्रकाशक उसे किताब की शक्ल देने में उस पर पैसा

ख़र्च करता है और लाभ की अपेक्षा लेखक व प्रकाशक दोनों को होती है. जब यहां मानव श्रम, पैसा और लाभ की आकांक्षा तीनों ही चीज़ें मौजूद हैं तो फिर प्रोडक्ट मानने में हर्ज़ क्या है? अगर प्रोडक्ट को बाज़ार नहीं मिलेगा तो न केवल मानव श्रम व्यर्थ जाएगा, बल्कि जिस लक्ष्य और उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी ख़ास विषय पर लिखा गया है वह भी चला जाएगा. लेखकों की रचनाओं से यह अपेक्षा होती है कि वह समाज में बदलाव लाएंगी, लेकिन अगर रचनाएं टार्गेट ग्रुप तक पहुंच ही नहीं पाएंगी तो न समाज में बदलाव आ पाएगा और न ही किसी विचार का प्रसार हो पाएगा.

दूसरी बात यह है कि अगर हम पुस्तकों को एक उत्पाद मानने लगेंगे तो प्रकाशकों के साथ-साथ लेखकों का भी भला होगा. अभी हालात यह हैं कि रॉयल्टी को लेकर हर लेखक के मन में मलाल होता है. हिंदी के लेखकों के इस मलाल से यह तो साबित हो ही जाता है कि उनको अपनी किताब से लाभ की अपेक्षा है. आपने श्रम किया, आपको लाभ की आकांक्षा है और प्रकाशक का पैसा लगा तो फिर किताब को उत्पाद मानने में दिक़्क़त क्या है?

दूसरी अहम बात यह है कि प्रकाशकों की रुचि भी सरकारी थोक ख़रीद में ज़्यादा होती है और पुस्तकों को पाठकों तक पहुंचाने में होने वाली मेहनत और ख़र्चे से वे बचना चाहते हैं. प्रकाशकों के लिए प्रकाशन व्यवसाय किसी भी दूसरे अन्य कारोबार की तरह ही है, जहां उनका उद्देश्य कम ख़र्चे में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना होता है और अपने इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वे प्रयास भी करते रहते हैं, करना भी चाहिए. प्रकाशकों को लगता है कि सरकारी ख़रीद में अफ़सरों को रिश्वत देकर अगर अपनी किताबें बेच दी तो बल्ले बल्ले. हर्रे लगे न फिटकरी रंग चोखा होए. कई प्रकाशक मेरे मित्र हैं, उनसे जब भी बात होती है तो उनकी चिंता सिर्फ़ सरकारी थोक ख़रीद को लेकर रहती है. फुटकर बिक्री में उनकी रुचि बेहद कम होती है. जब भी उनसे बात करो तो पाठकों की कमी का रोना रोकर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हैं. लेकिन, यह बात बार-बार उठती रही है और हर बार ग़लत भी साबित होती रही है कि हिंदी में पाठक नहीं हैं. आज हिंदी के पाठकों का एक बड़ा बाज़ार है, जिस पर क़ब्ज़े की होड़ दिखाई दे रही है, लेकिन हिंदी के प्रकाशक इसको या तो समझ नहीं पा रहे हैं या फिर जानबूझ कर समझना नहीं चाहते.

तीसरी अहम बात यह है कि लेखक भी प्रकाशक पर यह दबाव बना पाने की स्थिति में नहीं हैं कि उनकी किताबों के प्रचार-प्रसार के लिए काम किया जाए. यह किसी व्यक्तिगत प्रयास से संभव नहीं है, क्योंकि आज हिंदी के लेखक इस हैसियत में नहीं हैं कि वे प्रकाशकों पर दबाव बना सकें. जो दो तीन लेखक इस हैसियत में हैं उन पर प्रकाशक इतने मेहरबान होते हैं कि वे अपने साथी लेखकों के हितों के लिए उठने वाली आवाज़ का समर्थन नहीं कर सकते. उल्टे प्रयासपूर्वक मामले को सुलझाने के नाम पर प्रकाशकों की तरफ़दारी करने लग जाते हैं. लेखक संगठन लगभग मृतप्राय हैं जिनकी भूमिका कुछ रह नहीं गई है. लेखकों की शोकसभा और एकाध रचना पाठ आयोजित करने के अलावा संगठन कुछ कर नहीं पाते हैं.

तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि हम जैसे पाठकों का क्या होगा? क्या किसी ख़ास किताब को पढ़ने की हमारी लालसा मन में दबी रह जाएगी या फिर इस समस्या का हल भी सरकार को ही करना पड़ेगा? मुझे तो लगता है कि पुस्तकों की सरकारी थोक ख़रीद बंद कर देनी चाहिए. प्रकाशकों और लेखकों को पाठकों के रहमोकरम पर छोड़ देना चाहिए, तभी प्रकाशक पाठकों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और हिंदी समाज में पुस्तक संस्कृति बन पाएगी.

(लेखक आईबीएन7 से जुड़े हैं.)

feedback@chauthiduniya.com

ब्रह्म साकार है और निराकार भी

देवेन्द्र झा

ब्रह्म निराकार है, यह कहना उतना ही सच है जितना यह कहना कि ब्रह्म साकार भी है. ब्रह्म अगर साकार नहीं है तो ब्रह्म की सर्वव्यापकता और सर्वत्रव्यापकता की बात मिथ्या हो जाती है, अत: निराकार के साथ-साथ ब्रह्म साकार भी है, सृष्टि के इस नियम को मानते रहने के सबल प्रयास के अंतर्गत पत्थर अथवा धातु से निर्मित मूर्ति की पूजा की परंपरा का उद्रेक हुआ, तब से सृष्टि का यह नियम है कि संपूर्ण मूर्त-जगत में ब्रह्म का अंश आत्म तत्व है, इस परंपरा में परिलक्षित होकर जीता चला आ रहा है.

इसी परंपरा के अंतर्गत दो कलाधारी जीवों की पूजा की जाने लगी और वटवृक्ष, पीपल, तुलसी आदि पेड़ पौधों की पूजा- अर्चना होने लगी, इन्हें प्रभु समान आदर देकर प्रभु की सर्वव्यापकता के गुण की मान्यता को सबलता दी गई और ऐसा करना व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन शैली में समाहित हो गया. इसी तरह तीन कलाधारी जीवों की पूजा के क्रम में गाय, बैल आदि पशुओं की पूजा करने की परंपरा ने जन्म लिया, सृष्टि के नियम इस तरह परंपरा बनकर जन-जीवन में उतरते चले आ रहे हैं.

कलाओं की क्रिया के केंद्र-बिंदु

एक से चार तक की कलाओं की क्रिया का केंद्र बिंदु होता है शरीर. इसीलिए पशु और मानव उन्हीं क्रियाओं में तन्मय रहते हैं जिनसे उनकी देह-रक्षा हो तथा देह-जनित आनंद प्राप्त हो सके , देह-तुष्टि के अतिरिक्त इनकी क्रियाओं का कोई अन्य ध्येय नहीं होता. देह से जुड़े सगे-संबंधियों के हितार्थ किए गए कार्य भी व्यक्ति के शरीर को आनंद प्रदान करते हैं, अत: इन क्रियाओं का भी केंद्र-बिंदु शरीर ही होता है, चार कलाधारी जीवों तक देह-भाव प्रदान होता है और इसी कारण स्वार्थपरकता का वर्चस्व रहता है, जब मानव अपनी मेधा-शक्ति का सम्यक विकास कर लेता है तो वह पांच कलाधारी जीव की श्रेणी में आ जाता है, तब दिमाग़ इसकी क्रिया का केंद्र बिंदु बन जाता है. इस अवस्था में इसे दिमाग़ी कार्य अथवा विषय आनंदकारी लगने लगता है. पांच कलाधारी जीव के उदाहरण में समस्त बुद्धिजीवी वर्ग आते हैं. लेकिन जो व्यक्ति पांच कलाधारी होते हुए भी चार कलाओं का स्वभाव नहीं त्याग पाते, वे बुद्धि-सुख के साथ साथ शरीर-सुख भी पाने में तल्लीन रहते हैं. कुछ व्यक्ति शरीर सुख से इतने बंधे होते हैं कि अपनी समस्त विद्वता, पांडित्य और चातुर्य पांचवी कला के गुण का प्रयोग अधिकाधिक शरीर सुख पाने के लिए करते हैं. ऐसे व्यक्ति पांच कलाधारी होते हुए भी वस्तुत: चार कलाधारी जीव की श्रेणी में ही रहते हैं. लेकिन वे व्यक्ति जिन्होंने चार कला के भाव-जगत का पूर्णत: त्याग कर पांच कलाधारी जीव के क्रिया जगत को अपना लिया है, वे शरीर-सुख से बेख़बर बौद्धिक सुख के संसार में विचरण करते हुए देखे जाते हैं, इस श्रेणी में कुछ अन्वेषक, वैज्ञानिक, दार्शनिक आदि आते हैं जिन्हें अपने भोजन, वेशभूषा, शरीर सुख आदि की चिंता ही नहीं रहती.

व्यक्ति पंच कला से ऊपर उठकर छह कलाधारी जीव तब बन जाता है जब उसे यह ज्ञात हो जाता है कि दिमाग़ी सुख पाकर भी उसका हृदय-जगत भूखा रह गया है और दिमाग के कहने पर चलकर उसे वह आनंद प्राप्त नहीं हो पाया जिससे हृदय-पिपासा मिट

सके और जीवन आनंदमय हो जाए. ये मानने लगते हैं कि दिमाग की जगह दिल के कहने पर चलने से ही हृदय-पिपासा मिटती है और जीवन आनंदमय हो जाता है. इस तरह छह कलाधारी जीव के लिए हृदय इनकी क्रिया का केंद्र बिंदु बन जाता है. ये भाव जगत में गोते लगाते नहीं थकते और इन्हें शरीर अथवा विद्वता-पांडित्य का भान ही नहीं रहता, इसके उदाहरण में आते हैं चंद विलक्षण भक्त, कवि, समाजसेवी जो अपने हृदय को आह्लादित करने के क्रम में शेष सभी चीज़ों का त्याग कर देते हैं पर अधिकतर छह कलाधारी व्यक्ति ऐसे होते हैं जो चतुर्थ और पंचम कला के बंधन में बंधे रह जाते हैं और भाव-जगत से वह पाने का यत्न करते रहते हैं जिससे तन और मन की प्यास बुझती रहे. इस श्रेणी में प्रवचन से धन कमाने वाले, आध्यात्मिक क्षेत्र की प्रवीणता से तन-धन सुख पाने वाले, व्यवसाय के तौर पर काव्य-रचना करने वाले आदि आते हैं.

(लेखक प्रसिद्ध इंजीनियर हैं.)

feedback@chauthiduniya.com

ज्ञान, गुण और शक्तियों के भंडार हैं परमपिता

परमपिता परमात्मा अनंत शक्तियों और वरदानों के भण्डार हैं. परमात्मा की अपार शक्तियों एवं वरदानों की अनुभूति के लिए ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से भारत के 16 विभिन्न राज्यों में भव्य विश्व उत्सव का आयोजन किया गया.

राजधानी दिल्ली में यह उत्सव बीती तीन अक्टूबर को रामलीला मैदान और अगले दिन सीरीफोर्ट ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ. इन दोनों कार्यक्रमों में संस्था की अतिरिक्त प्रशासिका राजयोगिनी दादी हृदयमोहिनी ने प्रभु प्रेम व शक्तियों के प्रकंपनों एवं दिव्य प्रकाश का अनुभव कराया. उत्सव के पहले दिन की शुरुआत शुभ स्वागतम शत् स्वागतम गीत पर बी के मीनाक्षी द्वारा शास्त्रीय नृत्य से हुई. उसके बाद हस्तसाल केंद्र के बच्चों द्वारा समूह गीत का प्रदर्शन हुआ. आगे की मनमोहक नृत्य प्रस्तुति बच्चों के ही नाम रही. दिल्ली स्थित सरिता विहार केंद्र के बच्चों द्वारा दिल से निकाल के एक ही स्वर गीत के रिए प्रेम का संदेश दिया गया. सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच-बीच में ब्रह्माकुमारी वरिष्ठ बहनों द्वारा ज्ञान वर्षा भी होती रही. गीत चलो चलें परिवर्तन पथ पर के बोलों पर बच्चों के नृत्य ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया.

बी के सूदन एवं समूह द्वारा गाया गीत *बेचैन हो के* और *मेघा अधलखा* एवं समूह द्वारा गाया गीत ऐसा वरदान दे *दो बाबा* ने वातावरण को झंकृत कर दिया. मि. वाइज के साथ एक मुलाक़ात नामक छोटे से नाटक के ज़रिए परमात्मा से मिलन और स्वार्थ,

ईर्ष्या व अहं जैसे दुर्गुणों को अपने अंदर से ख़त्म करने का संदेश दिया गया. इसके बाद माउंट आबू के मधुरवाणी समूह द्वारा आज की शाम गीत से वातावरण को पवित्र बनाया गया.

इसके बाद राजयोगिनी ब्रह्माकुमारी हृदयमोहिनी द्वारा कहे गए सुवचन, परमात्मा से संपर्क जोड़ने के अनुभव और उसके फ़ायदे पर प्रकाश डाला गया. इस कार्यक्रम को आयोजित करने के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए आज के मनुष्य जीवन की तनावपूर्ण स्थिति पर भी विचार किया गया. वक्ताओं ने कहा कि सभी प्रकार के मानवीय प्रयासों के बावजूद विश्व की समस्याएं दिनोंदिन बढ़ती जा रही हैं. मनुष्य की बुद्धि क्रोध, लोभ और अहंकार रूपी विकारों से ग्रसित है. ऐसे में सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा शिव ही एकमात्र स्रोत हैं जो अपनी शक्तियों और वरदानों से संपूर्ण संसार को सुख व शांति प्रदान कर सकते हैं. वास्तव में परमात्मा शब्द में ही परमपिता का सत्य परिचय समाया हुआ है. परम का अर्थ है सर्वोच्च. संसार में अनेक आत्माएं हैं जैसे देवात्मा, महात्मा, धर्मात्मा और साधारण आत्मा आदि. परमात्मा इन सभी से ऊंचे हैं. करोड़ों आत्माओं में जो मुख्य है, प्रधान है, वही परमात्मा है. जैसे आत्मा ज्योतिबिंदु स्वरूप है, परमपिता भी रूप में वैसे ही हैं, किंतु वह गुणों में सिंधु हैं. उनके बड़े होने का अर्थ है कि वह सर्वात्माओं के माता-पिता, बंधु-सखा, शिक्षक-सतगुरु हैं. वह पुनर्जन्म-मरण के चक्कर से सदा मुक्त हैं. वह ज्ञान, गुणों और शक्तियों के सागर हैं.

परमात्मा शिव नई दैवीय सतयुगी सृष्टि के रचयिता हैं. धर्मग्लानि के समय सृष्टि पर अवतरित होकर पतित आत्माओं को पावन बनाने का दिव्य कर्तव्य करते हैं. जब आत्माएं पावन बन जाती हैं तो सृष्टि पर स्वर्ग की स्थापना हो जाती है और परमपिता अपने कर्तव्य की पूर्ति के बाद पुन: अपने परमधाम को लौट जाते हैं. सदियों से भक्तजन भगवान से शक्ति मांगते हैं. मांगने मात्र अथवा केवल प्रार्थनाएं करने से शक्तियां नहीं मिलतीं. इसी कारण आज मानवीय दुर्बलताएं सर्वत्र व्याप्त हैं. इन्हीं दुर्बलताओं का ही परिणाम है बैर, चिंता, हिंसा, भय, अपराध, उग्रवाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार और असहिष्णुता. अत: मानवीय समाज को दुर्बलताओं से मुक्त कर शक्ति संपन्न, निर्विघ्न, सदाचारी, सुखी और समृद्ध बनाने के लिए ईश्वरीय शक्तियों को प्राप्त करने की विधि जानना अति अनिवार्य है. कई लोग ऐसा समझकर भगवान से डरते हैं कि न जाने वह सर्वसमर्थ कब क्या कर दे? किसी को मार दे, प्रलय ला दे, श्राप दे दें. परंतु परमात्मा शिव सर्वसमर्थ होते हुए भी सदा कल्याणकारी और मंगलकारी हैं. परमात्मा से शक्ति लेने के लिए मन और बुद्धि का सही जुड़ाव चाहिए. बुद्धि द्वारा परमधाम निवासी परमात्मा शिव के बिंदुरूप-ज्योति स्वरूप को स्मृति में लाते हुए मन द्वारा यही संकल्प लेना चाहिए कि हे परमप्रिय परमपिता, आप सर्वशक्तियों के भंडार हैं, दाता हैं. इस प्रकार मनन करने से आत्मा को असीम आत्मबल और ईश्वरीय बल की अनुभूति होती है. इस अनुभूति के बल से उसके साकार कर्मों में असंभव को भी संभव करने जैसी चमत्कारी शक्ति आ जाती है. वह अपनी किरणों के माध्यम से शक्तियों और वरदानों का अनुभव आत्मा रूपी बच्चों को कराते हैं.

> परमात्मा शिव नई दैवीय सतयुगी सृष्टि के रचयिता हैं. धर्मग्लानि के समय सृष्टि पर अवतरित होकर पतित आत्माओं को पावन बनाने का दिव्य कर्तव्य करते हैं. जब आत्माएं पावन बन जाती हैं तो सृष्टि पर स्वर्ग की स्थापना हो जाती है और परमपिता अपने कर्तव्य की पूर्ति के बाद पुन: अपने परमधाम को लौट जाते हैं.

शिविर के अगले दिन कार्यक्रम की शुरुआत ब्रह्माकुमारी आरती बहन के गीत से हुई, जिसके बोल थे *शिव की प्रीत ने सिखलाया है सबसे प्रीत निभाना.* यह परमात्मा की याद में और विश्व उत्सव के अवसर पर स्वरचित गीत है. इसके बाद वरिष्ठ भ्राता ब्रह्माकुमार ब्रजमोहन ने वहां मौजूद लोगों को विश्व उत्सव के उद्देश्यों और सफलताओं के बारे में बताया. राजयोग का सुखद अनुभव मुखवचनों द्वारा ब्रह्माकुमारी आशा जी ने कराया. कार्यक्रम के दौरान भारत में यूनेस्को के डायरेक्टर परशुराम ने ब्रह्माकुमारीज को अपनी शुभकामनाएं और संदेश दिया. उसके बाद नन्ही कलाकार कुमारी एकता नंदा ने तीन मिनट का भाषण दिया कि सच्चे अर्थों में रावण को जलाना क्या होता है. दरअसल एक रावण हमारे अंदर छिपा होता है, जिससे हमारे स्वभाव में ईर्ष्या, बैर और स्वार्थ का संचार होता है.

दिल्ली के मुख्य सचिव राकेश मेहता ने इस मौके पर अपना संदेश देकर अन्य अतिथियों के साथ विश्व उत्सव के इलैक्ट्रॉनिक चिह्न का उदघाटन किया. व्यक्ति का साक्षात्कार परमपिता से होता है. अमेरिका में राजयोग केंद्र की निर्देशिका एंड्रिका ने राजयोग की महत्ता पर अपने अनुभव सुनाए. उन्होंने बताया कि हम परमात्मा से शक्तियां और वरदान किस प्रकार पा सकते हैं. उनके बाद फ्रांस से आए ब्रह्माकुमार मार्क ने अपने जीवन का अनुभव सुनाया, जिसमें वह 29 वर्ष पहले अपने जीवन के दुखों से परेशान होकर आत्महत्या करने वाले थे, पर परमात्मा से परिचय के बाद वह सुखद जीवन जीने में कामयाब हैं. कार्यक्रम में पंडित बिरजू महाराज के शिष्य पंडित पुलकित मिश्रा ने मधुर रागिनी गीत पर शास्त्रीय नृत्य पेश किया. देश भर में चल रहे विश्व उत्सव के सिलसिले का समापन समारोह संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में 22 नवंबर को आयोजित किया गया है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

टेक्नोलॉजी और गैजेट्स की बात हो और जापान की चर्चा न हो, ऐसा हो नहीं सकता. इस बात को पूरी दुनिया जानती है.

दिल्ली, 19-25 अक्टूबर 2009
चौथी दुनिया

सैमसंग का नया पिक्सन 12

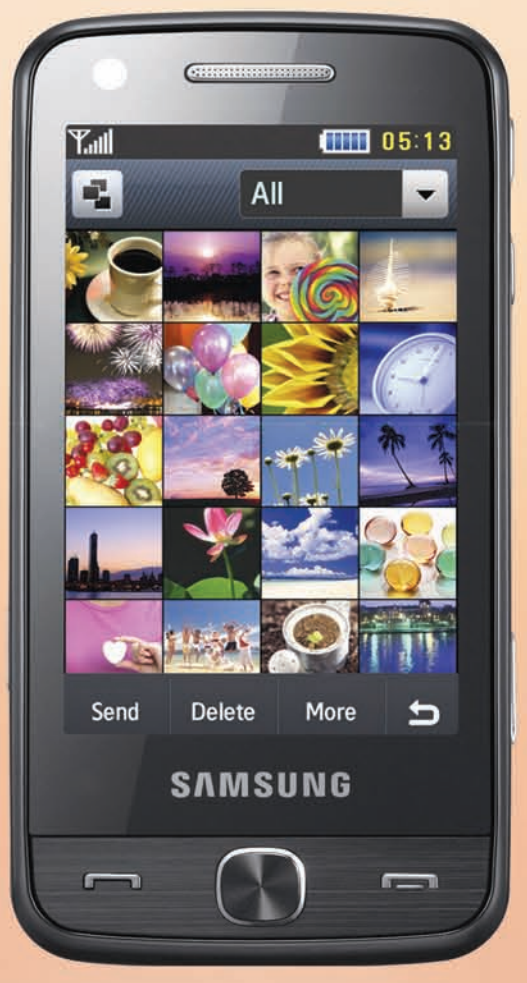

बाज़ार में विभिन्न सेलफोन निर्माता कंपनियों के बीच बेहतरीन कैमरा फोन लांच करने की होड़-सी मची है. बात चाहे डिजीटल कैमरे की हो या फिर अन्य लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की, हर कंपनी इस होड़ में एक-दूसरे से आगे निकलना चाहती है. वैसे हाल ही में सोनी एरिक्सन ने 12 मेगापिक्सल वाला स्मार्ट कैमरा फोन सैशियो लांच कर बाज़ार में धूम मचा दी थी. पर इस बार धूम मचाने की बारी है सैमसंग की.

सैमसंग ने भी भारतीय बाज़ार में 12 मेगा पिक्सल का फोन पिक्सन 12 एम 8910 लांच कर एरिक्सन को ज़ोरदार टक्कर देने की कोशिश की है. फीचर्स के मामले में यह दूसरे किसी भी फोन से कम नहीं है. इस सेलफोन में ठीक वैसी ही सुविधा दी गई है, जिसे अमूमन यूजर्स अपने सेलफोन में देखना चाहते हैं.

इसमें 3.1 इंच का एमोलेड टच स्क्रीन लगा है. इसके ज़रिए आप किसी ऑब्जेक्ट को स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं. इतना ही नहीं इसमें जीपीएस, ब्ल्यूटूथ, आरडीएस के साथ ही एफएम रेडियो भी है. जहां तक मेमोरी क्षमता का सवाल है तो पिक्सन 12 में 150 एमबी की इनबिल्ट मेमोरी है. इसके साथ ही 16 जीबी एक्सपेंडेबल मेमोरी की सुविधा है जो कि किसी भी फोन के लिहाज़ से काफी है. इसमें एसडी मेमोरी कार्ड का भी उपयोग कर सकते हैं.

एप्पल आईफोन ने टच स्क्रीन फोन लांच कर बाज़ार में क्रांति ला दी है. अब हर फोन कंपनी टच स्क्रीन वाले फोन बाज़ार में उतार रही हैं. जिससे कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा भी बने रहे और सेलफोन प्रेमी नई-नई टेक्नोलॉजी से रू-ब-रू हो सकें. हालांकि ये बात अलग है कि लोग किस फोन को अपनी पहली पसंद बनाते हैं.

गुड़िया जापान की...

टेक्नोलॉजी और गैजेट्स की बात हो और जापान की चर्चा न हो, ऐसा हो नहीं सकता. इस बात को पूरी दुनिया जानती है. हम भी इस बार इस बात की ही चर्चा कर रहे हैं. एशिया के सबसे बड़े क्यूबा ट्रेड फेयर में जापान की एक कंपनी की रोबोटनुमा गुड़िया ने सबको हैरत में डाल दिया. जापानी गुड़िया बहुत पहले से हमारे देश में धाक जमा चुकी है, लेकिन जिस गुड़िया (रोबोट) की हम बात कर रहे हैं, उसे यहां आने में अभी वक्त लगेगा. लेकिन हाल ही में एशिया के सबसे बड़े क्यूबा ट्रेड फेयर में इसका प्रदर्शन किया गया है.

जापान के इलैक्ट्रॉनिक पार्ट्स बनाने वाली कंपनी मुराता इलैक्ट्रॉनिक्स ने इस रोबोटनुमा गुड़िया को एशिया ट्रेड फेयर में प्रदर्शनी के लिए लगाया था. कंपनी ने इस रोबोट का नाम मुराता-सिको-चेन रखा है. इसका आकार-प्रकार दूसरे रोबोट की तरह ही है, लेकिन इसका लुक औरों की तुलना में ज्यादा अट्रैक्टिव है. इसकी लंबाई 50 सेंटीमीटर और भार छह किलोग्राम है.

वैसे देखने में तो यह काफी छोटा लगता है, लेकिन सुविधा ऐसी कि जिसे देखते ही आप दांतों तले अंगुलियां दबा लें. मतलब यह कि आप कुछ देर सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि इसमें इतने सारे फीचर्स हैं.

इस रोबोट को कंट्रोल करने के लिए इसमें एक सेंसर लगा हुआ है. रिमोट के ज़रिए आप इसे आगे-पीछे भी कर सकते हैं. लेकिन सिर्फ़ आकार में छोटा होने के कारण इसे कम आंकने की भूल न करें.

यह आकार में छोटा भले है लेकिन जब आप इसकी सुविधाओं के बारे में जानेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे. इसमें वीडियो कैमरा और ब्ल्यू टूथ लगा है जिसके द्वारा आप वीडियो शूट तो कर ही सकते हैं साथ ही इसे कहीं ट्रांसफर भी कर सकते हैं. इसके अलावा बिना तार के आप अपने पीसी पर इसे ट्रांसमिट भी कर सकते हैं. है न बड़ी बात! तभी तो आप भी सोच में पड़ गए कि इस जापानी गुड़िया में कुछ ख़ास बात है.

निकॉन कूल कैमरे की मची धूम!

कैमरा प्रेमियों के लिए निकॉन ने एक नया कैमरा बाज़ार में उतारा है. वैसे तो यह कैमरा बिल्कुल आम कैमरों जैसा ही है, लेकिन इसके फीचर्स दूसरों से जुदा है. कूलपिक्स एस1000पीजे की एक ख़ासियत यह है कि इससे वीजीए क्वालिटी की मूवी भी प्रोजेक्ट की जा सकती है. कैमरा निर्माता कंपनियों में निकॉन की अलग पहचान है.

सबसे बड़ी बात तो यह है कि कूलपिक्स एस1000पीजे कैमरा लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लायक है. और जहां तक कंपनी की विश्वसनीयता की बात है तो निकॉन दूसरी कंपनियों से इस लिहाज़ से भी आगे है. निकॉन का प्रोडक्ट ख़रीदते वक्त लोगों के मन में तनिक भी इसके बारे में संदेह उत्पन्न नहीं होता है. मतलब यह कि लोग बेहिचक इसके प्रोडेक्ट को ख़रीदते हैं. निकॉन द्वारा मार्केट में लांच किया गया यह विश्व का ऐसा पहला कैमरा है, जिसमें इंटीग्रेटेड प्रोजेक्टर लगा हुआ है. इतना ही नहीं इसमें कई दूसरी सुविधाओं की भी भरमार है, जो लोगों को निश्चित तौर पर अपनी ओर आकर्षित करेगा.

कूल पिक्स एस 1000 पीजे वीजीए क्वालिटी की मूवी को प्रोजेक्ट कर सकता है. इसके अलावा अच्छी क्वालिटी की फोटो भी ले सकता है. न सिर्फ अच्छी क्वालिटी के फोटो, बल्कि यह 40 इंच की इमेज भी ले सकता है. इस कैमरे के साथ एक प्रोजेक्टर स्टैंड और एक रिमोट कंट्रोल का सेट दिया जाता है ताकि प्रोजेक्ट करने और फोटो लेने में आपको लाइव रूम का अहसास हो. इस 12.1 मेगापिक्सल कैमरे में वाइड-एंगल 5 एक्स जूम निकॉन लेंस और एक 2.7 इंच का टीएफटी एलसीडी लगा हुआ है. जिसके ज़रिए आप इमेज को देख भी सकते हैं.

इमेज स्टैबिलाइजेशन और स्मार्ट पॉर्ट्रेट फीचर्स की मदद से आप इमेज में आने वाले काले धब्बे को दूर भी कर सकते हैं. इतना ही नहीं इससे आप ब्लर फ्री इमेज भी ले सकते हैं.

एस1000 पीजे एसडी और एसडीएचसी कार्ड्स भी एक्सेप्ट करता है. इसमें रिचार्जेबल लिथियम बैटरी लगी हुआ है. इस बैटरी को एक बार चार्ज करने पर आप इस कैमरे से 220 शॉट ले सकते हैं. इसकी क़ीमत कुछ ख़ास नहीं है. इसके लिए आपको सिर्फ़ 28,950 रुपये चुकाने पड़ेंगे.

अब आएगा मज़ा बाथरूम में बरसात का

बरसात का नाम सुनते ही हर किसी का मन मचल उठता है कि काश अभी बारिश हो जाए और ख़ूब जम कर नहाने का मज़ा ले सकें. वैसे बारिश में भीगना किसे अच्छा नहीं लगता है. हर कोई इसका जमकर लुत्फ उठाते हैं, लेकिन ज़रा सोचिए कुछ इसी तरह का अहसास आपको अपने वाथरूम में मिले और वह भी मौसम का इंतजार किए बगैर तो कितना मज़ा आए. सच पूछिए तो इस बारे में सोच कर ही दिल बाग-बाग हो जाता है. आपको बता दें कि ये बातें आपको भले ही सपनों जैसा लगे, लेकिन सपना अब हक़ीक़त में तब्दील होने ही वाला है. इसलिए आप बारिश में भीगने के लिए तैयार हो जाइए. क्योंकि पीटीएमटी सिमेट बाथ एसेट्स का प्रयाग इनोवेशन ने आपके लिए इस तरह की व्यवस्था की है, जिससे आप बाथरूम में भी बारिश का मजा ले सकेंगे.

प्रयाग इनोवेशन उपभोक्ताओं की ज़रूरत के हिसाब से समय-समय पर मॉडर्न बाथ फिटिंग (पीटीएमटी सिमेट बाथ एसेट्स) बाज़ार में उतारते हैं. प्रयाग इनोवेशन आपके लिए भारत में पहली बार स्टील मैट फिनिश लेकर आ रहा है. यह पीतल और स्टील दोनों में उपलब्ध है. आप अपनी पसंद के अनुसार कोई-सा भी ख़रीद सकते हैं. देखने में यह काफी ख़ूबसूरत है और काम ऐसा कि बाथरूम में ही झमाझम बारिश का मज़ा दिला दे. क्यों, अब आपका भी मन कर रहा है बाथरूम में बरसात का मज़ा लेने का? तो फिर देर किस बात की. झट से जाइए बाज़ार और इसे ख़रीदकर अपने बाथरूम में लगवाइए, फिर जमकर लीजिए बारिश का मज़ा.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

क्रिकेटर साल भर अधिक क्रिकेट का रोना रोते हैं, लेकिन चैंपियंस लीग जैसे मुक़ाबलों में खेलने में उन्हें कोई बुराई नज़र नहीं आती. मामला मोटी कमाई से जो जुड़ा है.

उड़न परी की आंखों में आंसू

भारत अपने खिलाड़ियों का कितना सम्मान करता है, हमें एक बार फिर से इसकी मिसाल देखने को मिली. हम सुपर पावर बनने का दंभ भले भरते हों, लेकिन हक़ीक़त यह है कि यही दंभ हमें हर मर्तबा ले डूबता है. जिस देश में खिलाड़ियों की आंखें आंसू से गीली हो जाती हों और खेल अधिकारी बाद में मामले की लीपापोती करने में जुट जाते हों, ऐसे देश में सुपर पावर बनने का सपना तो बस ख्याली पुलाव पकाने के जैसा ही है. इंडियन ट्रैक एंड फील्ड की दुनिया में उड़न परी के नाम से मशहूर खिलाड़ी पी टी ऊषा का जिस तरह राष्ट्रीय खेलों के दौरान अपमान किया गया, उससे साफ़ ज़ाहिर होता है कि भारतीय खेल अधिकारियों के दिल में अपने खेल सितारों और भारत का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों के प्रति सम्मान भाव की हक़ीक़त क्या है.

पी टी ऊषा की आंखों में आंसू यह बताने के लिए काफ़ी है कि खेल के इन हुक्मरानों का बर्ताव अपने पूर्व खिलाड़ियों के प्रति कैसा रहता है. मौजूदा समय में क्रिकेट को छोड़ कर किसी भी खेल में खिलाड़ियों के साथ दोयम दर्ज़े का ही सलूक होता है.

हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया अपनी टीम के खिलाड़ियों को हवाई जहाज के टिकट तक उपलब्ध नहीं करा पाती है. दूसरी ओर क्रिकेट की चकाचौंध दुनिया है जहां पैसों की भरमार देखने को मिलती है, लेकिन इसके बाद भी भारतीय क्रिकेट टीम बड़े मुक़ाबलों में फिसड्डी साबित होती रहती है. वहीं अथक मेहनत के दम पर भारत का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी भी हैं, लेकिन उन्हें तिरस्कार और आंसू के सिवा कुछ नहीं मिलता है. पी टी ऊषा ने जिस हक़ीक़त का सामना किया है, वह खेल में राजनीति का घालमेल बताने के लिए वह काफी है.

बीजिंग ओलंपिक में जितनी संख्या खिलाड़ियों की नहीं थी उससे कहीं ज़्यादा खेल अधिकारियों और उनके नाते-रिश्तेदारों की थी, लेकिन इसे क्या कहेंगे कि राष्ट्रीय खेल में उड़न परी को ही शामिल नहीं होने दिया.

भागमभाग में फंसे खिलाड़ी

चैंपियंस लीग की शुरुआत हो चुकी है. दुधिया रोशनी के चकाचौंध भरे माहौल में इसका आग़ाज़ हुआ. दूसरी ओर इसके साथ बीसीसीआई की चैलेंजर ट्रॉफी भी शुरू हुई, लेकिन चैंपियंस लीग के सामने चैलेंजर ट्रॉफी की चमक फीकी ही नज़र आई. कुछ भारतीय खिलाड़ी लीग में खेलते नज़र आए तो कुछ चैलेंजर ट्रॉफी में, लेकिन इन प्रतियोगिताओं में सबसे अहम मुद्दा कहीं खो गया. जी हां, खिलाड़ियों की व्यस्तता और उनके आराम का.

फोटो – पीटीआई

जब कोई टेस्ट या एकदिवसीय मुक़ाबले होते हैं तो खिलाड़ी व्यस्त कार्यक्रम का रोना रोने लगते हैं. उनकी शिकायत होती है कि अधिक व्यस्त शेड्यूल होने की वजह से उन्हें आराम का मौक़ा नहीं मिलता और लगातार खेलते रहने का असर उनके प्रदर्शन पर पड़ता है. अब क्या हो गया, इन खिलाड़ियों को. ये आराम क्यों नहीं करते, ताकि चंद दिनों बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ शुरू होने वाले मैच में ये अपना सौ फ़ीसदी दे सकें, ख़ुद को चोटिल होने से बचा सकें और अपने देश के लिए अधिक से अधिक खेल सकें. पर, ये खिलाड़ी ऐसा कभी नहीं करेंगे. क्योंकि ऐसा करने से इनकी बेतहासा कमाई पर लगाम जो लग जाएगा. यही वजह है कि कई खिलाड़ी साल भर तो अधिक क्रिकेट का रोना रोते हैं, जब वक़्त आता है आराम का तो चैंपियंस लीग जैसे मुक़ाबलों में खेलने लगते हैं फिर चोटिल हो जाते हैं और जब तक कोई दूसरा कमाई का लीग शुरू नहीं होता, तब तक अनफिट रहते हैं. उदाहरण के तौर पर विरेंद्र सहवाग का नाम आपके सामने है. आईपीएल में चोटिल होकर महीने भर के लिए खेल के मैदान से बाहर हो गए और विज्ञापन की शूटिंग में व्यस्त रहे, बजाय आराम फरमाने के.

अब जबकि चैंपियंस लीग शुरू हो गई है तो अब इसमें खेलने के लिए फिट हो चुके हैं. ग़जब की टाइमिंग है. पैसा कमाना कोई ग़लत बात नहीं है, लेकिन खेल की आड़ में सिर्फ़ पैसे कमाना किस हद तक जायज़ है?

फिक्सिंग पर पाकिस्तान का पलटवार

चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया ने फिर अपनी बादशाहत क़ायम की है. तीन बार की विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने लगाातार दूसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी का ख़िताब अपने नाम कर यह जता दिया कि सारे दिग्गज ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के संन्यास लेने के बावजूद यह टीम अभी भी दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम है.

लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे दिलचस्प वाकया रहा, सेमीफाइनल में हार के बाद पाकिस्तानी खेल मंत्रालय का भारत पर मैच फिक्सिंग का आरोप. पाकिस्तानी खेल मंत्री की मानें तो, सेमीफाइनल का मैच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने फिक्स कर रखा था, ताकि पाकिस्तानी टीम फाइनल में न पहुंच पाए. पाकिस्तान का यह भी आरोप है कि बीसीसीआई ने अंपायरों को प्रभावित किया और अंपायरों ने सारे फ़ैसले पाकिस्तान टीम के ख़िलाफ़ दिए. हालांकि, कुछ फ़ैसले ज़रूर पाक के ख़िलाफ़ गए थे. सेमीफाइनल मुक़ाबले में जिस तरह कप्तान युनूस ख़ान ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाज़ इलियट का कैच टपकाया, उससे पाक कप्तान पर भी सवाल उठने लगे हैं, साथ ही कोच इंतख़ाब आलम भी संदेह के दायरे में हैं. ख़बर तो यह भी है कि कप्तान के पद से युनूस ख़ान की विदाई तय है और संभव है टी-20 की तरह वनडे टीम की बागडोर भी शाहिद अफ़रीदी को ही सौंप दी जाए. इन सबके बीच पाकिस्तान टीम पर फिर से मैच फिक्सिंग का भूत मंडराने लगा है. इसके पहले श्रीलंकाई सरज़मीं पर मेज़बानों के हाथ हार के बाद, पाक टीम इसी तरह मैच फिक्सिंग के घेरे में आई थी, लेकिन इस बार चैंपियंस ट्रॉफी में हार ने पाकिस्तान पर फिक्सिंग के सवाल खड़े तो किए ही, पाकिस्तान का भारत पर बेबुनियाद आरोप ने जाहिर कर दिया कि दोनों देशों के बीच खेल संबंधों में दरार कितनी बढ़ चुकी है.

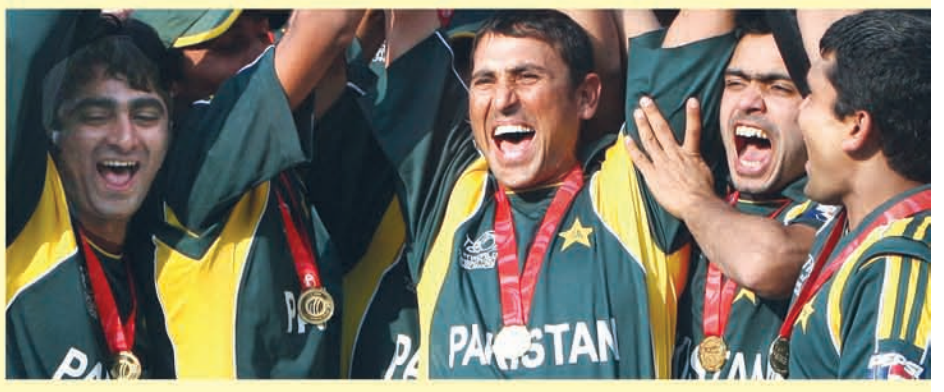

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

ये है यंगिस्तान

भारत एक ऐसा देश जहां प्रतिभाओं की कभी कोई कमी नहीं रही. ख़ास तौर पर देश के छोटे बच्चे. उनकी प्रतिभा देखकर वाक़ई लगता है भारत में महाशक्ति बनने का माद्दा है. फ़िलहाल, हम बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र के दो भाई-बहन, इलिना और भास्कर गुप्ता की. इलिना कक्षा आठ की छात्रा है जबकि भास्कर तीसरी कक्षा का. ये दोनों बच्चे न सिर्फ़ पढ़ाई में अव्वल हैं, बल्कि इतने कम उम्र में ही इन दोनों ने इतनी अधिक उपलब्धियां हासिल कर ली हैं कि ताज्जुब होता है और कई लोग अपनी तमाम ज़िंदगी में उन ऊंचाईयों तक पहुंचने के लिए लालायित रहते हैं. इलिना राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कला स्पर्धाओं में 35 से भी अधिक पदक जीत चुकी है. जबकि महज़ तीसरी क्लास का छात्र भास्कर शतरंज जैसे गंभीर खेल की कई प्रतियोगिताओं में 40 से भी अधिक ट्रॉफियां जीत चुका है. यहां तक कि कॉमनवेल्थ देशों की शतरंज प्रतियोगिता में रजत पदक भी जीत चुका है. और वह अंडर-9 ग्रुप में महाराष्ट्र स्टेट चैंपियन भी है.

इस तरह के कुछ उदाहरणों से उम्मीद बंधता है कि भारत जो खेलों में तरक़्क़ी कर रहा है, वह यूं ही नहीं है. इसके पीछे भारत के यंगिस्तान का हौसला, मज़बूत इरादे हैं, जो पूरी दुनिया में भारत को एक नई बुलंदी तक लेने जाने को आतुर हैं. इलिना और भास्कर जैसे बच्चे इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल हैं.

उंघते नज़र आए राष्ट्रमंडल प्रमुख

राष्ट्रमंडल खेल 2010 में होना है और इसके लिए अब साल भर से भी कम समय रह गया है, लेकिन इसकी तैयारी अभी भी कछुए की सुस्त चाल से चल रही है. शायद इसी वजह से राष्ट्रमंडल प्रमुख तैयारी का जायजा लेने आए और ख़ुद सुस्त हो गए. दरअसल, सारा वाकया राष्ट्रमंडल खेल महासंघ (सीजीएफ) अध्यक्ष माइकल फेनेल स्टेडियम के निरीक्षण के दौरे पर निकले तब हुआ.

अध्यक्ष महोदय के लिए तैयारियों से संबंधित स्लाइड-शो दिखाने का इंतजाम किया गया था. लेकिन, स्लाइड-शो देखने के बजाय फेनेल साहब और उनके प्रतिनिधि मंडल के सदस्य उंघते नज़र आए. शायद, शो उन्हें पसंद नहीं आया या मुमकिन है खेलों की तैयारी उन्हें आकर्षित नहीं कर पाई. और शो की समाप्ति के बाद ही सीजीएफ अध्यक्ष की नींद टूटी. ग़ौरतलब है कि इन खेलों का आरंभ अगले साल 7 अक्टूबर से होना है और इसकी तैयारियों से फेनेल वाक़ई संतुष्ट नहीं दिखे, उनका मानना है कि यदि इसी रफ़्तार से तैयारियां चलती रही तो समय पर इसका पूरा होना नामुमकिन ही है. इन सबके बीच भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के मुताबिक़, तैयारियों का जायजा लेने आए सभी सदस्य हमारे काम से काफी संतुष्ट दिखे, लेकिन हक़ीक़त कुछ और ही बयां कर रही है. इसका सबूत है, राष्ट्रमंडल खेल प्रमुख इन तैयारियों से इतने ख़ुश दिखे कि वह निरीक्षण के दौरान ही झपकी लेते नज़र आए.

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. 45843/86

करीना की इमेज हॉट ग्लैमर गर्ल की है. ज़ाहिर है उनके लिए साधारण लड़की का किरदार निभाना मुश्किलों से भरा ही होगा, लेकिन उनके साथ बहुत जल्द ही ऐसा कुछ होने जा रहा है.

मुक़ाबला कांटे का

करीना की इमेज हॉट ग्लैमर गर्ल की है. ज़ाहिर है उनके लिए साधारण लड़की का किरदार निभाना मुश्किलों से भरा ही होगा, लेकिन उनके साथ बहुत जल्द ही ऐसा कुछ होने जा रहा है. उनकी फिल्म स्टेप मॉम जल्द ही रिलीज़ होने वाली है. इस फिल्म में वह बिल्कुल सीधी सादी दिखेंगी. इससे पहले वह किसी भी फिल्म में साधारण नहीं दिखी हैं. ख़बर है कि करीना को नया लुक देने के लिए उनके डिज़ाइनर मनीष मल्होत्रा भी काफी परेशान हैं. वैसे करीना ख़ुद भी इस लुक के लिए काफी मेहनत कर रही हैं. यहां तक कि वह वर्कशाप भी अटेंड कर रही हैं. आख़िरकार उनका मुक़ाबला काजोल देवगन से जो है. इस फिल्म में वह काजोल की सौतन की भूमिका निभा रही हैं. फिल्म की शूटिंग इसी महीने के अंत तक शुरू हो जाएगी. करीना अभी थ्री इडियट्स की शूटिंग में व्यस्त हैं. उसकी शूटिंग ख़त्म करने के बाद वह स्टेप मॉम के लिए तैयारी करती हैं.

ग़ौरतलब है कि करीना ने अपने करियर में ख़ास तौर पर ग्लैमरस रोल ज़्यादा किए हैं, जबकि काजोल ने हर तरह की भूमिकाएं निभाई हैं. यही नहीं, फिल्म फेयर अवार्ड सहित वह कई अवार्ड भी जीत चुकी हैं. इस लिहाज़ से करीना के सामने काजोल एक बड़ी चुनौती के रूप में मौजूद रहेंगी. एक बात ग़ौर करने योग्य है कि अब करीना उन किरदारों की तरफ़ ज़्यादा ध्यान दे रही हैं, जो उन्होंने अपने फिल्मी करियर में अभी तक नहीं किए हैं. स्टेप मॉम वाला किरदार भी उनमें से एक है. देखते हैं, वह यह नया रोल निभाने में कितनी सफल हो पाती हैं या फिर उन्हें केवल ग्लैमरस रोल ही भाता है. बेबो को वाकई में इस रुप में देखना दिलचस्प तो होगा ही क्योंकि उन्हें आज तक साधारण रुप में नहीं देखा है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

प्रियंका के बाद बिपाशा

प्रियंका तो अपने 12 रोल से दर्शकों का दिल जीतने में सफल साबित नहीं हुई तो इसी के चलते बिपाशा बसु ने इसमें एक और बढ़ाकर अपने रोल 13 कर लिए हैं. अपनी आने वाली फिल्म पंख में वह 13 रोल कर रहीं हैं. प्रियंका के लिए तो 12 राशियां अनलकी रही, लेकिन बिप्स के लिए 13 का अंक कितना लकी साबित होगा, यह तो फिल्म रिलीज़ होने के बाद ही पता चलेगा. बिपाशा को अपनी इस फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार है क्योंकि काफी समय के बाद उनकी फिल्म रिलीज़ होगी. हो सकता है कि बिप्स अपने 13 रोल से दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब हो जाएं.

आइटम गर्ल नहीं बनना चाहतीं मंदिरा

आज भी अधिकतर लोग मंदिरा बेदी को धारावाहिक शांति की शांति के रूप में ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि मंदिरा ने अपनी पहचान वहीं से बनाई थी. दरअसल वह तो अभिनेत्री बनना चाहती थीं, पर बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने में असफल रहीं. हाल ही में उन्होंने ख़तरों के खिलाड़ी-2 में भी हिस्सा लिया था. उनका कहना है कि उन्हें रोमांच बहुत पसंद है. लेकिन, उन्हें यही रोमांच तब महंगा पड़ गया, जब उन्होंने इसके चक्कर में बिकनी में फोटो खिंचवा ली थी और जिसका उन्हें अभी तक अफ़सोस है. सूत्रों से पता चला है कि उनका कहना है कि लोग उन्हें एक्ट्रेस के रूप में न जानकर बतौर शो होस्ट जानते हैं. उनके पास अब तो टीवी सीरियल के ऑफर भी नहीं आते. बल्कि आजकल उनके पास आइटम नंबर के ऑफर आते हैं. यहां तक कि दक्षिण की फिल्मों से भी आइटम नंबर के ऑफर आ रहे हैं. समझ में नहीं आ रहा कि उनके पास ऑफर वहां से क्यों आ रहे हैं ? यह राज़ तो अब मंदिरा ही बेहतर बता सकती हैं.

MURUGAPPA GROUP

BSA MOTORS e-Scooters

BSA मोटार्स आ गया
सबके दिलों पे छा गया।

BSA MOTORS की हर एक इलैक्ट्रीक स्कूटर की खरीद पर पाईये
"एक साल की बैट्री वारंटी" एवम् "Rs. 4000/- का कैश कार्ड मुफ्त"।

4000/- रुपये मूल्य के कैश कार्ड निश्चित रुप से पाओ।
एक साल की बैट्री वारंटी*$
दो सालो में 29,890/- रुपये की बचत करो।*#

Conditions apply##
*Ex. showroom Price starting from Rs.15,450/- for Smile in Delhi after subsidy & cash card.
*$ Battery Warranty of 12 months / 12000 km's whichever is earlier & applicable.
*# Savings Vary from model to model.

SHAHDARA: Binsar Auto Mobiles, 954 - E, Main 100 Ft Road, Babarpur Extn.Shahdara. Phone: 011-22831100 / 22831400/9911994444/9911450121. NAJAFGARH: CNS Retail Pvt Ltd, Plot No. 1, Block – G, Gopal Nagar. Phone: 011 - 28015634 / 28010709/ 09958019000/9212365634. DWARKA-MAIN PALAM DABRI ROAD: CNS Retail Pvt Ltd, D - 70/5, Main Palam Dabri Road, Mahavir Enclave. Phone: 011 – 28011702/ 45017150/09818239724/ 9212275634/ 9212170006. NANGLOI: CNS Retail Pvt Ltd, Plot No 18, Ram Nagar Colony, Main Najafgarh Road, Nangloi. Phone: 9971734599 / 9213899686. KRISHNA NAGAR: Agrawal Motors, A-1/14. Krishna Nagar, Chachi Building Chawk,Near Lal Quarter Market. Phone: 011 – 22452829/09312835117. KAROL BAGH: Imperial Cycles, 53/2, Deshbandhu Gupta Road, Karol Bagh. Phone: 011-65461542/ 28722276/25717886/9811453355. ASHOK NAGAR: New Golden Cycle Store, 36/13, Ground Floor, Ashok Nagar. Phone: 9810807183. NOIDA: Agrawal Motors, B-41 & 42, Sector 16 , Near Mirula's Hotel, Gautam Budh Nagar. Phone: 0120-4249906/ 4232242/9312835117/ 09350906906. ROHINI: Rocky Autolinks, F 18/61, Rohini, Sector 8. Phone: 9811032353 (Opening Shortly)

आने वाली फिल्में

अलादीन

झंकार बीट्स के निर्माता सुजॉय घोष अपनी नई फिल्म लेकर आ रहे हैं, नाम है अलादीन. फिल्म के कलाकार हैं अमिताभ बच्चन, रितेश देशमुख, संजय दत्त और जूही चावला. संगीत विशाल शेखर ने दिया है. फिल्म में शहंशाह एक जिन्न का किरदार निभा रहे हैं. रितेश अलादीन का रोल करेंगे और संजय दत्त बनेंगे बदमाश रिंग मास्टर. अलादीन, उनके चिराग और उससे निकलने वाले जिन्न की कहानी पर तो पहले भी फिल्में बन चुकी हैं. इस नई फिल्म में अलादीन के बॉलीवुड रूपांतरण के साथ-साथ जादू के भी ख़ूब स्पेशल इफेक्ट्स इस्तेमाल किए गए हैं. अब देखना यह है कि फिल्म बच्चों के साथ-साथ बड़ों को कितना प्रभावित कर पाती है.

लंदन ड्रीम्स

लंदन ड्रीम्स के निर्देशक विपुल शाह हैं. मुख्य कलाकार हैं सलमान ख़ान, अजय देवगन और आसिन. संगीत शंकर महादेवन का है. फिल्म की कहानी दो पंजाबी दोस्तों की कामयाबी और उनकी कुर्बानी पर आधारित है, जो बचपन से ही रॉक स्टार बनने की चाहत रखते हैं और अंत में लंदन में शो करते हैं. फिल्म में दोनों संगीत की दुनिया में नाम रोशन करना चाहते हैं. अजय देवगन और सलमान 10 साल बाद यानी हम दिल दे चुके सनम के बाद एक साथ दिखाई देंगे. सलमान दो अलग और दिलचस्प लुक में नज़र आएंगे. फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा कि उन दोनों का लंदन में रॉक स्टार बनने का सपना पूरा होता है या नहीं.

चौथी दुनिया

बिहार झारखंड

www.chauthiduniya.com

दिल्ली, 19-25 अक्टूबर 2009

बाहुबली : कोई पस्त तो कोई मस्त

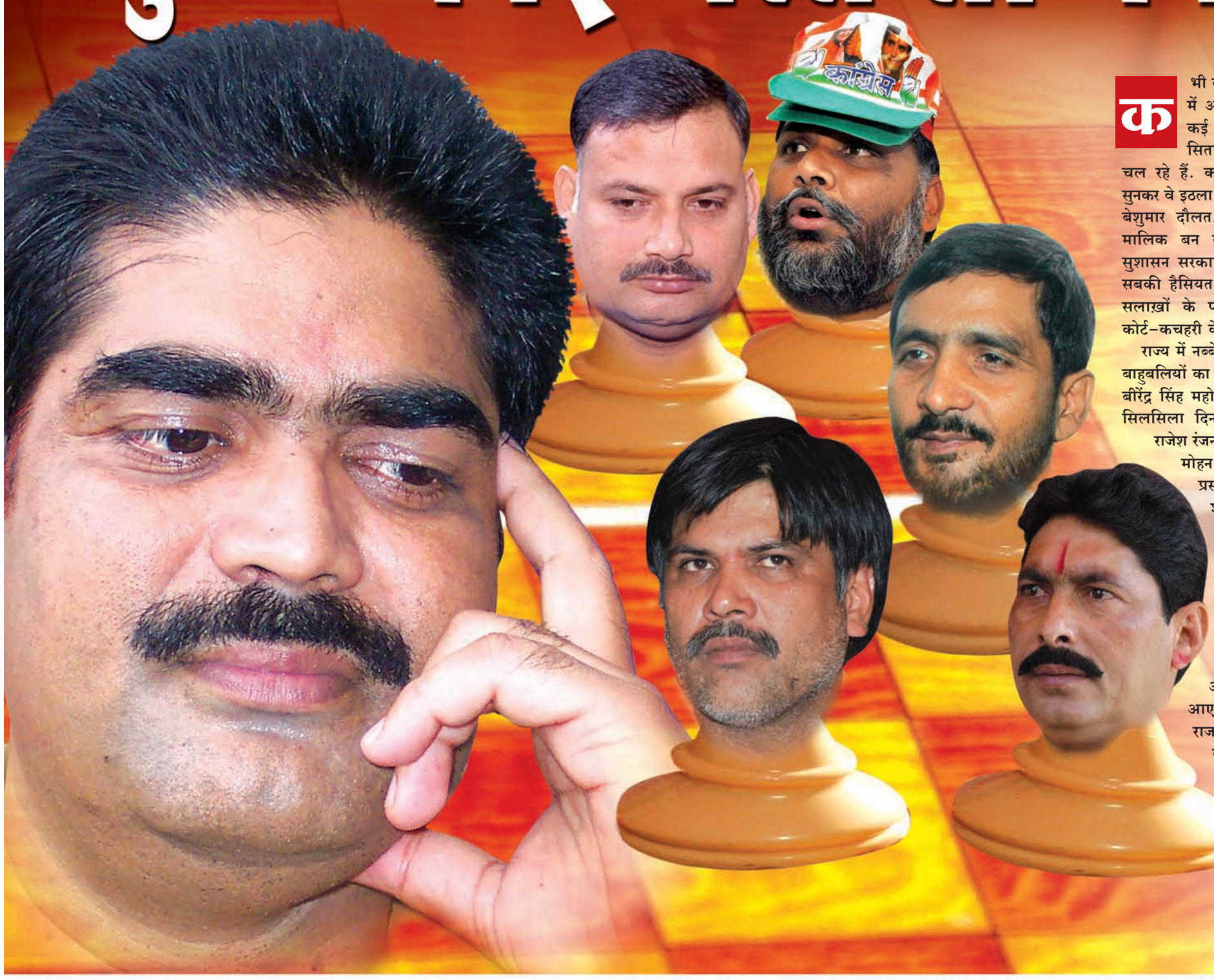

कभी बंदूक़ की ताक़त पर सूबे में अपनी सत्ता चलाने वाले कई बिहारी बाहुबलियों के सितारे इन दिनों गर्दिश में चल रहे हैं. कभी ख़ुद को बाहुबली सुनकर वे इठला उठते थे. देखते ही देखते बेशुमार दौलत, गाड़ी और बंगले के मालिक बन बैठे ये सब. लेकिन, सुशासन सरकार में नज़र लग गई इन सबकी हैसियत को. इनमें से कुछ तो सलाख़ों के पीछे हैं तो कई लोग कोर्ट-कचहरी के चक्कर काट रहे हैं.

राज्य में नब्बे के दशक से शुरू हुआ बाहुबलियों का सफ़र अब ढलान पर है. बीरेंद्र सिंह महोबिया से शुरू हुआ यह सिलसिला दिनोंदिन बढ़ता ही गया. राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, आनंद मोहन, देवेंद्र दूबे, बृजबिहारी प्रसाद, मोहम्मद शहाबुद्दीन और दिलीप सिंह आदि ऐसे नाम हैं जिन्होंने जनता में अपनी ऐसी इमेज बना ली थी कि लोग इनकी तुलना कभी-कभी रॉबिनहुड से कर बैठते थे. पहले अपराध जगत और फिर राजनीति में आए इन बाहुबलियों ने राजनीति की परिभाषा ही बदल कर रख दी. इसके बाद बाहुबलियों में नाम शुमार हुआ सूरजभान सिंह उर्फ सूरज, मुन्ना शुक्ला, राजन तिवारी, सुनील पांडे, रामा सिंह और मनोरंजन सिंह उर्फ धूमल सिंह का. इनमें से कई जेल में रहते हुए ही विधायक बने. लेकिन जनप्रतिनिधि बनने के बाद भी इनकी आदत नहीं बदली. अपहरण, रंगदारी और हत्या के मामलों में इनके नाम आते रहे. लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के शासनकाल में उक्त बाहुबली, चाहे वे किसी भी दल के क्यों न रहे हों

> **सीवान में अपनी हुकूमत चलाने वाले राजद सांसद रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन का उदाहरण लें. सीवान में उनका अपना अलग राज चलता था. अंडरवर्ल्ड से उनके रिश्ते जगज़ाहिर रहे. अपहरण, हत्या और रंगदारी के दो दर्जन से ज़्यादा मामलों के आरोपी शहाबुद्दीन आज क़ानून के फंदे में फंस चुके हैं.**

ख़ूब मज़े में रहे. जेल उनके लिए आरामगाह बनी रही. कोई जेल से निकलकर मुजरा देखने जाता था तो कोई अपने घर. एक बाहुबली विधायक ने तो गजब ही कर दिया. वह पिछले दस साल से जेल में हैं, जमानत तक नहीं मिली, लेकिन जेल में रहते हुए ही उन्होंने अपनी शादी की दावत दे दी और आज दो बच्चों के बाप हैं. पहले विधायक थे, अब पूर्व विधायक हैं.

(शेष पृष्ठ 18 पर)

जगमग बिहार का सपना अंधेरे में

सरोज सिंह

नीतीश सरकार ने सत्ता संभालते ही जगमग बिहार का जो सपना दिखाया था, वह अब तक सपना ही है. राजधानी पटना को अगर छोड़ कर दें तो पूरे बिहार का अधिकांश इलाक़ा अंधेरे में ही डूबा रहता है. बिजली के अभाव में विकास की गाड़ी इस तरह से पटरी से उतरी कि नए कल-कारखाने तो खुलने से रहे किसी तरह चल रही छोटी-मोटी फैक्ट्रियां भी बंदी के कगार पर है. ग्रामीण इलक़ों का तो हाल यह है कि लोग एक-दूसरे से यह नहीं पूछते हैं कि बिजली कब जाती है, बल्कि उनका सवाल होता है कि बिजली कब आती है. इस सवाल का जवाब न तो गांव की बेबस जनता के पास है, न बिजली विभाग और न ही सरकार के पास.

दरअसल शुरू से ही बिजली के मामले में बिहार के साथ पक्षपात होता आया है. कांटी व बरौनी थर्मल पावर स्टेशन के अलावा राज्य के पास उत्पादन इकाई के नाम पर कुछ भी नहीं है. पनबिजली परियोजनाओं की क्षमता इतनी कम है कि उसके भरोसे कुछ नहीं हो सकता. नीतीश सरकार ने कांटी व बरौनी थर्मल इकाइयों को ठीक करने की पहल की, पर परिणाम अच्छा नहीं आया. ये दोनों इकाइयां ज़्यादातर ठप ही रहती हैं. राज्य को लगभग 2100 मेगावाट बिजली की दरकार है, पर इसके खाते में इतनी बिजली नहीं है. केंद्रीय पूल से बिहार के लिए 1630 मेगावाट बिजली आवंटित है. इसकी ज़्यादातर आपूर्ति एनटीपीसी व एनएचपीसी के माध्यम से होती है. इसके अलावा राज्य सरकार 150 मेगावाट अतिरिक्त बिजली पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से ख़रीदती है.

इस तरह मांग के अनुसार बिजली न रहने के कारण हर कोई लाचार दिखता है. केवल पटना के लिए ही 386 मेगावाट बिजली आवंटित रहने के कारण अन्य ज़िलों में बिजली आपूर्ति का हाल और भी बुरा हो जाता है.

लेकिन इस संकट का एक दूसरा पहलू भी है. केवल कम आवंटन का रोना रोकर समस्या को एक आंख से देखना होगा. राज्य में बिजली की वितरण व संचरण प्रणाली इतनी जर्जर है कि बिजली रहते वह लोगों के घरों तक नहीं पहुंच पाती है. ग्रिडों की हालत इतनी ख़राब है कि राज्य 1400 मेगावाट से अधिक बिजली का उपयोग नहीं कर सकता है. इसलिए आवंटन बढ़ा भी दिया जाए तो भी हर घर में रोशनी नहीं हो सकती है. कुछ निजी बिजली उत्पादक कंपनियों ने बिजली की दशा सुधारने के लिए पहल की थी पर लगता है सरकारी प्रोत्साहन न मिलने के कारण उनका उत्साह भी ठंडा रहा है. मौजूदा हालात को देखकर तो यही लगता है कि जगमग बिहार के लिए अभी बिहारवासियों को लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा.

थर्मल से रोशनी तो नहीं, परेशानी ज़रूर मिली

विकास अगर बेतरतीब हो तो वह अपने साथ भारी तबाही भी लेकर आती है. बिहार में जब औद्योगिकीकरण की शुरुआत हुई तो पुराने मुंगेर ज़िले (अब बेगूसराय) में सिमरिया के क़रीब गंगा के किनारे आज से लगभग 49 साल पहले बरौनी थर्मल पावर की नींव रखी गई थी. तब शायद किसी ने सोचा भी न होगा कि इससे लगी सैकड़ों एकड़ सोना उगलने वाली ज़मीन एक दिन किसी काम की नहीं रह जाएगी, अन्न से भरे गोदाम ख़ाली हो जाएंगे और हंसी-ख़ुशी ज़िंदगी गुज़ारने वाले यहां के किसान दाने-दाने को मोहताज़ हो जाएंगे. बरौनी थर्मल प्लांट की जब बुनियाद रखी जा रही थी तो किसानों ने वर्तमान और भविष्य की चिंता किए बग़ैर अपनी ज़मीनें उसके हवाले कर दी थीं. उन्हें उम्मीद थी कि आने वाले दिनों में यह प्लांट उनके घर के अंधियारे को तो दूर करेगा ही, उनकी ज़िंदगी में भी उजाला लाएगा. उन्हें यह यक़ीन हो गया था कि इस प्लांट के बन जाने के बाद उनके बच्चों को रोज़गार की तलाश में दूर परदेस नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन बाद में सब कुछ उम्मीद के विपरीत ही होता चला गया. निर्माण की ग़लतियों व रखरखाव में घोर लापरवाही के कारण बरौनी थर्मल प्लांट से आज बिजली उत्पादन न के बराबर है.

हर दूसरे दिन बिजली उत्पादन ठप हो जाना आम बात हो गई है. बिजली नहीं मिली, इससे तो लोगों ने संतोष कर लिया, लेकिन लगभग 566 एकड़ ज़मीन जो कभी अन्न के रूप में सोना उपजाती थी, आज कोयले की राख से अटी पड़ी है. 86 एकड़ ज़मीन पर बरौनी थर्मल कारखाना और 140 एकड़ ज़मीन पर थर्मल टाउनशिप है. इस समय टाउनशिप और 340 एकड़ ज़मीन पर केवल बरौनी थर्मल कारखाने से निकलने वाली काली राख फैली हुई है, जिसने लोगों को लगभग तबाह करके रख दिया है. सैकड़ों एकड़ भूमि पर खड़ी फसल बुरी तरह प्रभावित हो चुकी है. शेष ज़मीन, जिसके सहारे मल्हीपुर-चकिया के किसानों की ज़िंदगी चलती थी, आज बंजर हो चुकी है. समस्या सिर्फ़ इसकी राख को लेकर नहीं है, थर्मल कारखाने की चिमनियों से निकलने वाले धुएं के कारण यहां के किसान मानसिक व शारीरिक तौर पर पंगु होते जा रहे हैं. ज़्यादातर लोग सांस की बीमारी से ग्रसित हैं. इसके अलावा उनके सामाजिक जीवन को भी राख और धुएं ने कहीं का नहीं छोड़ा है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

लोकसभा चुनाव और उसके बाद बिहार विधानसभा उपचुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विजय रथ को रोकने वाले बांका के सांसद दिग्विजय सिंह अब लोकमोर्चा के बैनर तले नीतीश कुमार की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कमर कस चुके हैं.

बिहार में भारत–नेपाल सीमा पर बसा शहर रक्सौल अपराध और अपराधियों की शरण स्थली माना जाता है. मादक पदार्थों की तस्करी के लिए बदनाम यह शहर नक़ली नोटों के तस्करों का अड्डा बन चुका है. भारत में नक़ली नोटों की खेप इसी सीमा से भारत में प्रवेश कराई जाती है.

लालू की राह पर चल पड़े हैं नीतीश

बिहार में विकास के नाम पर केवल घोषणाएं

लोकसभा चुनाव और उसके बाद बिहार विधानसभा के उपचुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विजय रथ को रोकने वाले बांका के सांसद दिग्विजय सिंह अब लोकमोर्चा के बैनर तले नीतीश कुमार की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कमर कस चुके हैं. स्वच्छ राजनीति एवं ईमानदार सरकार के नारे के साथ उन्होंने गांधी जयंती के अवसर पर गांधी की कर्मभूमि चंपारण से नीतीश सरकार के ख़िलाफ़ आंदोलन का शंखनाद कर दिया. उनका मानना है कि दशकों से बिहार में मूल्य की राजनीति की जगह सिर्फ़ तिकड़म और जातीय समीकरण की राजनीति चल रही है. नीतीश भी इस खेल में शामिल होकर लालू की राह पर चल पड़े हैं. दिग्विजय सिंह नीतीश कुमार से लगभग हर मंच से यह सवाल पूछ रहे हैं कि विकास का कोई एक काम वह जनता को बताएं. उनका आरोप है कि बिहार में विकास नहीं, बल्कि कुछ इलाक़ों में मरम्मत का काम चल रहा है. विकास का काम मुख्यमंत्री नहीं बता पाएं, इसलिए उपचुनाव में जनता ने उन्हें ख़ारिज़ कर दिया. दिग्विजय सिंह का दावा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में भी जनता केवल घोषणा करने वाली इस निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकेगी.

आगामी विधानसभा चुनाव में लालू व नीतीश से किसी भी तरह के तालमेल से पूरी तरह इनकार करते हुए उन्होंने अपनी रणनीति साफ़ करते हुए कहा कि साफ़ व ईमानदार छवि वाले ऐसे लोग जिन्हें सही मायनों में राज्य की विकास की चिंता है उनका खुले दिल से स्वागत है.

राजनीति की इतनी कठिन राह चुनने पर उनका तर्क है कि कीचड़ को कीचड़ से साफ़ नहीं किया जा सकता है. उनका मानना है कि नीतीश कुमार व लालू प्रसाद दोनों विकास विरोधी हैं. इन दोनों नेताओं ने 19 वर्षों में बिहार को रसातल में पहुंचा दिया है. उन्होंने समाज को जातियों में बांटने का काम किया है. नीतीश सरकार तो मेंटेनेंस वाली सरकार है. मुख्यमंत्री मेंटेनेंस को ही विकास बता रहे हैं. सच्चाई यह है कि बिहार में अब तक विकास का एक भी कार्य नहीं हुआ है. अगर विकास हुआ है तो मुख्यमंत्री बताएं कि चार वर्षों में उन्होंने कहां पर कार्य किया है? यहां न तो कोई निवेश हुआ है और न ही कोई बिजली का प्लांट लगा. उद्योग स्थापित न होने तथा रोज़गार के अवसर पैदा न होने से मजदूरों के पलायन का सिलसिला जारी है. काम के बदले रोज़गार योजना भी यहां नाकाम हो रही है. राज्य में मजदूरी नहीं मिलने के कारण पेट भरने के लिए लोग बाहर जा रहे हैं. इसके लिए लालू एवं नीतीश जिम्मेवार हैं. लालू एवं नीतीश के कारण देश की एकता और अखंडता को भी ख़तरा है. दूसरे राज्यों में बिहारियों को मारा जा रहा है. कुछ दिनों के बाद लोग यह कहेंगे कि बिहार बोझ बन गया है. इसलिए बिहार को अलग देश बनाया जाए.

इस दोनों के अलावा अन्य किसी भी दल के साथ तालमेल की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है. उन्होंने इशारों ही इशारों में कहा कि जदयू के कई बड़े नेता उनके संपर्क में हैं. उन्होंने सख्त लहज़े में कहा कि बिहार में अपराधियों एवं बाहुबलियों का प्रभाव निरंतर बढ़ता ही जा रहा है.

राजनीतिक दलों में कार्यकर्ता की जगह पैसे वालों की पकड़ मज़बूत होती जा रही है. लोकमोर्चा में अपराधियों एवं बाहुबलियों के लिए कोई स्थान नहीं है. लालू के कारण पिछले 15 वर्षों में बिहार का विनाश ही हुआ और अब नीतीश कुमार समाज को जातियों में बांट कर तोड़ रहे हैं.

उपचुनाव में लोकमोर्चा प्रत्याशियों की हार पर दिग्विजय का मानना है कि नीतीश की हार तय करना हमारा मक़सद था और इसमें हम सफल रहे. उन्होंने कहा कि जल्द ही न केवल बिहार में, बल्कि पूरे देश में लोकमोर्चा एक मज़बूत राजनीतिक ताक़त बनकर उभरेगा.

दिल्ली की राजनीति में अपना ज़्यादा समय देने के सवाल पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि लोकमोर्चा का गठन राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है. इसलिए देश भर में घूमकर अच्छे लोगों को जोड़ने की ज़िम्मदारी मुझ पर है, लेकिन बिहार व झारखंड में भी पूरी तैयारी के साथ उनका संघर्ष जारी है. उन्हें पूरी उम्मीद है कि इन दोनों राज्यों की जनता ज़रूर अच्छे लोगों को चुनेगी और ये दोनों राज्य विकास के पथ पर तेज़ी से आगे बढ़ेंगे.

सरोज सिंह
feedback@chauthiduniya.com

कसहा दियारा में ख़ूनी खेल की तैयारी

मोकामा से सटे कसहा दियारा में ख़ूनी खेल खेलने की पृष्ठभूमि काफी तेज़ी से तैयार हो रही है. यहां अंदर ही अंदर आग सुलग रही है. लोग गोलबंद हो रहे हैं और ज़मीन पर कब्ज़े और वर्चस्व को लेकर लाशों का गिरना शुरू भी हो गया है. प्रशासन को भी इस बात की जानकारी है कि यहां तनाव बढ़ रहा है, पर मज़बूत इच्छाशक्ति और सशक्त रणनीति के अभाव में प्रशासन हाथ पर हाथ रख कर लाशों का सिर्फ़ पंचनामा भर करा रही है और अपराधी सरेआम बंदूक चमकाकर अपनी ताक़त का अहसास करा रहे हैं.

पटना ज़िला के अंतर्गत पड़ने वाले कसहा दियारा में ज़मीन पर कब्ज़े को लेकर ज़ोर–आज़माइश जातीय तनाव में तब्दील हो चुकी है. मोकामा प्रखंड के मरांची थाना क्षेत्र में पड़ने वाला यह इलाक़ा कभी भी ख़ून खराबे की बड़ी घटना का गवाह बन सकता है. जिस तरह से यहां तीन जातियों के बीच तनाव फैल गया है वह वाकई चिंताजनक है. कसहा दियारा में मूलत: बिंद जाति के लोगों की बहुतायत है. इस पंचायत के बगल के गांव यादव और भूमिहार बहुल है. कसहा दियारा में बहुसंख्यक आबादी भले ही बिंद जाति के लोगों की है, परंतु अधिकांश ज़मीन भूमिहार जाति के लोगों की है और उसके बाद यादव जाति के कब्ज़े में सर्वाधिक ज़मीन है. इन ज़मीनों पर बिंद जाति के लोगों की नज़र गड़ गई है और नतीजतन पांच सौ से अधिक बीघा ज़मीन तीन–चार वर्षों से परती यानी बिना बोआई के रह जा रही है.

दियारा की उर्वर भूमि में बंदूक की खेती तब से ज़्यादा पनपी जब ज़मीन विवाद उलझना शुरू हुआ. प्रशासनिक आंकड़े बताते हैं कि दियारा की कुल 7000 बीघा ज़मीन में से 1735 बीघा ज़मीन विवादित है. विवादित ज़मीनों में थाना नंबर दस के अंतर्गत छत्तीस पाड़ी की कुल 180 बीघा ज़मीन है. इसके अलावा महाजी प्रताप की थाना नं. 19 की कुल 1555 बीघा ज़मीन विवादित है. मराची के किसानों द्वारा इनपर दावेदारी जताई जाती है. इन्हीं ज़मीनों पर रामपुर डुमरा के लोग दावा जताते हैं. सरकारी अमीन द्वारा नापी होने के बाद सीमांकन कर दिया गया. एसडीओ नौशाद युसूफ और तत्कालीन ग्रामीण पुलिस अधीक्षक द्वारा कई बार बैठक कर समस्या का समाधान निकालने का प्रयास किया गया, परंतु नतीजा सिफर है. एसडीओ नौशाद युसूफ भी सीमांकन के बावजूद हल नहीं निकलने को दुखद मानते हैं. किसानों के इस विवाद का फ़ायदा उठाकर स्थानीय अपराधी अब किसानों की ज़मीन पर हक़ जताने लगे हैं. दियारावासियों को पट्टे पर मिलने वाली ज़मीन पर वे प्रति बीघा अलग से रुपये की मांग करते हैं. आजिज दियारावासियों ने खेत पट्टे पर लेना बंद कर दिया और इसके बाद ज़मीन परती रहने लगी. इन बंदूकबाजों का मानना है कि ज़मीन पर दावा उनका है और वे हर हाल में इस पर कब्ज़ा करेंगे. मरांची गांव के किसानों की कई बार पिटाई भी हो चुकी है और कई बार विवाद को लेकर गोलियां भी चली हैं. कसहा दियारा अब तक कई मौतों का गवाह बन चुका है. इन हत्याओं के पीछे एकमात्र कारण है वहां भय स्थापित करना, आतंक पैदा करना ताकि भयवश लोग उधर से आना–जाना छोड़ दें. पिछले एक साल में आधा दर्ज़न लोग मौत के घाट उतारे जा चुके हैं. बेगूसराय के रामदीरी निवासी इंद्रदेव सिंह के भाई की हत्या से शुरू हुआ सिलसिला अभी तक जारी है. तीन माह पूर्व मटिहानी के आकाशपुर निवासी वाले यादव की हत्या हुई. उसके बाद अपराधियों ने सीतापुर के शंभू यादव की हत्या कर दी. पालू यादव पर भी जानलेवा हमला हुआ. इसके बाद शिबालक बिंद की हत्या कर दी गई. बिहट निवासी घीया सिंह की महज़ इसलिए हत्या कर दी गई, क्योंकि वह अपने बकाए पैसे की मांग करने गया था. हत्या की इन घटनाओं के पीछे पुलिस वर्चस्व की होड़ को कारण मानती है, परंतु वर्चस्व किस बात को लेकर है इस बारे में कुछ भी नहीं बता पाती है.

कसहा दियारा के स्थानीय निवासी बताते हैं कि अपराधियों की नज़र किसानों की ज़मीन पर गड़ी हुई है और वे भय और आतंक का ऐसा माहौल स्थापित करना चाहते हैं कि किसान डर से अपनी ज़मीन पर दावा छोड़ दे. दियारा के इलाक़े में रह रहे लोग शांति प्रिय हैं, परंतु विगत बीस वर्षों में आकर बसने वाले लोग आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं. ग्रामीणों का भी मानना है कि यदि समय रहते सख्त कारवाई नहीं हुई तो आने वाले समय में ख़ूनी खेल की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है.

विद्यासागर
feedback@chauthiduniya.com

दीपावली एवं छठ के शुभ अवसर पर समस्त कटिहार जिलावासियों को
हार्दिक शुभकामनाएँ

अशोक अग्रवाल
सदस्य
बिहार विधान पार्षद

दीपावली एवं छठ के शुभ अवसर पर समस्त कटिहार जिलावासियों को
हार्दिक शुभकामनाएँ

विजय अग्रवाल
किरासन तेल थोक विक्रेता
बड़ा बाजार कटिहार

दीपावली एवं छठ के शुभ अवसर पर समस्त
बिहार –बंगाल एवं झारखंड वासियों को
हार्दिक शुभकामनाएँ
SUN - PLANT AGRO LTD.
(An ISO 9001 : 2008 Certified Company)
आज की उम्मीद कल की दिशाएं
Sun - Plant Constructions Ltd.
Sun - Plant Agro Product (P) Ltd.
Sun - Plant Insurance Consultants (P) Ltd.
Sun - Plant Business Ltd.
Sun - Plant Green Society
North East Forging (P) Ltd.

अवधेश कुमार सिंह प्रबन्ध निदेशक
सन प्लान्ट एग्रो लिमिटेड

तस्करी का चारागाह बना रक्सौल

बिहार में भारत–नेपाल की सीमा से सटा यह शहर मानो प्रतिदिन सुर्ख़ियों में रहने को अभिशप्त है. मामला चाहे जाली नोटों की तस्करी का हो अथवा अफ़ीम, स्मैक, गांजा और चरस जैसे मादक पदार्थों या विस्फोटकों को सीमा पार पहुंचाने का, सारा कुछ यहां की रोजमर्रा में शामिल है. कई बार ऐसे मामले जब सामने आते हैं तो अखबारों की सुर्ख़ियां भी बनती हैं, लेकिन पुलिसिया छानबीन बिना किसी अंजाम तक पहुंचे ही ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है. छोटी–मोटी कार्रवाइयों की वजह से अधिकारियों के नाम मीडिया में ज़रूर आते हैं और इसी के बूते महीनों अपनी पीठ भी स्वयं ही थपथपाई जाती है. आइए रूबरू होते हैं तस्करी के इस नेटवर्क से और तस्करी से ही जुड़े कई अन्य पहलुओं से भी.

बिना कोई भूमिका बनाए सीधे शुरुआत करते हैं तस्करी के नेटवर्क से. अधिकारियों के बयान व हिरासत में आए अपराधियों के इकबालिया जुर्म से ज़ाहिर होता है कि कम से कम जाली नोट के तस्करी का सीधा संबंध पाकिस्तान के आईएसआई एजेंटों से है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से तोड़ना चाहते हैं. जाली नोट का ज़ख़ीरा नेपाल की राजधानी काठमांडू से चलकर वीरगंज पहुंचता है जहां जुबैद आलम व असगर अंसारी नामक दो व्यक्तियों के यहां इसे सुरक्षित रखा जाता है. यहां से कुरियर के माध्यम से इसे रक्सौल पहुंचाया जाता है. इन नोटों की कुछ डीलिंग रक्सौल में भी की जाती है. हाल ही में श्याम साह नामक जाली नोट के मुख्य तस्कर की गिरफ़्तारी भी की जा चुकी है. इन तस्करों ने कई राज़ खोले हैं, कुछ बातें सार्वजनिक हो चुकी हैं, लेकिन कई ऐसी जानकारियों को गुप्त रखते हुए कई सुरक्षा एजेंसियां कार्य कर रही हैं. एसएसबी के सहायक कमांडेंट लोकेश कुमार सिंह ने कई जानकारियां दीं और तस्करों के नेटवर्क को तोड़ने का जज़्बा भी दिखलाया.

बकौल लोकेश कुमार, जाली नोटों का जो ज़ख़ीरा रक्सौल पहुंचता है उसे बड़ी आसानी से गोरखपुर, इंदौर, दिल्ली, सूरत व अन्य व्यवसायिक शहरों में पहुंचाया जाता है. यह पूछे जाने पर कि आख़िर किन मामलों में एसएसबी अन्य सुरक्षा एजेंसियों से आगे हैं? सहायक कमांडेंट ने बताया कि तस्करों की पूरी सूची तैयार कर एक डाटा बेस तैयार किया जा रहा है और वह दिन दूर नहीं जब एक एक तस्कर को सलाख़ों के पीछे किया जाएगा और किसी भी हाल में भारतीय अर्थव्यवथा पर आंच नहीं आने दिया जाएगा.

उन्होंने बहुत गर्व के साथ यह कहा कि हमें इस बात पर भी नाज़ है कि यहां के कई स्थानीय लोग देशभक्ति के जज़्बे से हमें सूचनाएं भी पहुंचाते हैं जो हमारे लिए कई बार सार्थक साबित होती हैं. ऐसे लोगों के नाम पते को गुप्त रखा जाता है साथ ही उनके सुरक्षा की ज़िम्मेदारी भी एसएसबी के लोग लेते हैं.

अन्य सुरक्षा एजेंसियों के प्रति उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर सभी का साथ ईमानदारी व लगन से मिले तो इस नेटवर्क को तोड़ना आसान काम है. हालांकि उनके चेहरे पर अन्य सुरक्षा एजेंसियों ढीले ढाले काम को लेकर असंतोष के भाव ज़रूर थे. उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले तक सीमा क्षेत्र से सटे कई घाट,मसलन कलैक्शन सेंटर थे, जहां पर तस्करों से उगाही का काम किया जाता था. आज एक भी घाट नहीं है सभी घाटों को तोड़ दिया गया है व दलालों को पीट पीट कर खदेड़ा गया है.

उन्होंने विवशता जताते हुए यह भी कहा कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता. मसलन नारकोटिक्स से जुड़े असलम नामक व्यक्ति को एसएसबी अगर गिरफ़्तार भी करती है तो वह सलाख़ों के पीछे से ही स्मैक को मिट्टी साबित कर बाहर आ जाता है. कई सफेदपोश का वरदहस्त उसे हासिल है. रक्सौल के कई गणमाण्य लोग उसे तरजीह देते हैं. अन्य सुरक्षा एजेंसियां हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है.

उन्होंने अन्य सुरक्षा एजेंसियों पर इशारा करते हुए बताया कि एसएसबी अन्य सुरक्षा एजेंसियों के दायरे में घुसकर छापेमारी कर तस्करी के करोड़ों के माल के साथ तस्करों को गिरफ़्तार करती है, लेकिन संबधित सुरक्षा ऐजेंसी हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है. ऐसे में हमारे कार्य करने की उर्जा प्रभावित होती है. और तो और छापेमारी को अंजाम देती है एसएसबी और मीडिया में क्रेडिट लेता है कोई और.

चौथी दुनिया ने आम लोगों से भी बातचीत की और कई लोगों ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि कुरियार के कार्य में महिलाओं की भूमिका बढ़ती जा रही है. एसएसबी सहायक कमाडेंट ने बताया कि मोतिहारी स्थित पीपराकोठी मुख्यालय में लगभग 50 महिला बटालियन की टीम तैयार की गई है, जिसका इस्तेमाल रक्सौल एसएसबी भी गाहे बगाहे करती है. उन्होंने आने वाले समय मे महिला कुरियार के नेटवर्क को भी आसानी से तोड़ने की उम्मीद जाहिर की. उन्होंने सामाजिक सरोकारों का ज़िक्र करते हुए स्पष्ट किया कि कई ऐसे लोग भी हैं जो किसी मजबूरी में आकर तस्करी के नेटवर्क से जुड़ गए हैं. हम ऐसे लोगों को बिना नुक़सान पहुंचाए इनके सरगना तक पहुंचना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन का सहारा लिया जा रहा है, ताकि तस्करी के नेटवर्क में जुड़े लोगों की पहले पूरी जानकारी ली जा सके और उसके बाद ही किसी अंजाम तक पहुंचा जा सके.

मनोज कुमार राव
feedback@chauthiduniya.com

बाहुबली : कोई पस्त तो कोई मस्त

पृष्ठ 17 का शेष

नीतीश कुमार की तेरह दिन वाली सरकार में इन बाहुबलियों ने अपने जो तेवर दिखाए थे, वही शायद इन्हें महंगा पड़ गया. जब से नीतीश कुमार की सरकार पूर्ण बहुमत में आई, तभी से इन बाहुबलियों की ग्रह दशा ख़राब हो गई. स्पीडी ट्रायल शुरू हो गया इन बाहुबलियों पर. सीवान में अपनी हुकूमत चलाने वाले राजद सांसद रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन का उदाहरण लें. सीवान में उनका अपना अलग राज चलता था. अंडरवर्ल्ड से उनके रिश्ते जगज़ाहिर रहे. अपहरण, हत्या और रंगदारी के दो दर्ज़न से ज़्यादा मामलों के आरोपी शहाबुद्दीन आज क़ानून के फंदे में फंस चुके हैं. वह जेल में हैं और अब तक आठ मामलों में उन्हें सज़ा भी हो चुकी है. अभी भी कई मामलों में ट्रायल चल रहा है. जेल में रहने के दौरान इनका साम्राज्य तहस–नहस हो गया. सांसदी भी चली गई. पत्नी को भी चुनाव मैदान में उतारा, लेकिन उसे पराजय का मुंह देखना पड़ा. हालत यह है कि आज शहाबुद्दीन को जेल में भी अपनी जान का ख़तरा महसूस हो रहा है.

गोविंदगंज से विधायक रहे राजन तिवारी पर भी क़ानून का शिकंजा कस गया है. पहले अजीत सरकार और अब ब्रजबिहारी प्रसाद हत्याकांड में उन्हें उम्रकैद की सज़ा सुनाई जा चुकी है. जबकि धनबाद के जालान अपहरण कांड में ट्रायल चल रहा है. विधायक बने और अब पूर्व भी हो गए, लेकिन वह जेल से बाहर नहीं आ सके. जब विधायक बने तो करोड़ों की ठेकेदारी के अलावा कई बसों के मालिक बन गए. ख़ूब फैलाया अपना कारोबार, लेकिन धीरे–धीरे सब ख़त्म हो रहा है, क्योंकि कभी उनकी बंदूक़ से डरने वालों के मन में उनका ख़ौफ़ अब पहले जैसा नहीं रहा.

जद यू के विधायक सुनील पांडे अब नहीं सुधरेंगे वाली हालत में हैं. पटना के चर्चित डॉ. रमेश चंद्रा अपहरण कांड में कोर्ट ने उन्हें सज़ा सुना दी है, लेकिन जेल जाना–आना उनके लिए एक सामान्य बात है. अब तो उनके हिस्ट्रीशीटर भाई हुलास पांडे भी विधान परिषद सदस्य बन चुके हैं. हालांकि लोजपा विधायक रामकिशोर सिंह उर्फ रामा सिंह की हालत कुछ बेहतर है. रामविलास पासवान का दामन थामने के बाद रामा सिंह के पास बिजनेस के नाम पर बहुत कुछ है, आदत में भी सुधार हुआ है, हालांकि लोकसभा चुनाव में हार के बाद उनकी साख में थोड़ा सा बट्टा ज़रूर लगा है. कुछ यही हाल जद यू विधायक मुन्ना शुक्ला का भी है. अपने भाइयों की साख पर हुकूमत कर बाहुबली कहलाने वाले मुन्ना शुक्ला शासन के क़रीब रहते हुए भी उसे कोसने से कभी बाज नहीं आए. बृजबिहारी हत्याकांड में उन्हें भी उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है. पप्पू यादव की हालत भी अच्छी नहीं है. वह जेल से बाहर ज़रूर आ गए हैं, पर पत्नी और मां को संसद भेजने में सफल नहीं हो सके. हां, सुशासन सरकार के क़रीब रहने वाले अनंत सिंह ज़रूर मस्त हैं और लगातार अपना कारोबार फैला रहे हैं.

जद यू के विधायक सुनील पांडे अब नहीं सुधरेंगे वाली हालत में हैं. पटना के चर्चित डॉ. रमेश चंद्रा अपहरण कांड में कोर्ट ने उन्हें सज़ा सुना दी है, लेकिन जेल जाना–आना उनके लिए एक सामान्य बात है.

आभा ओझा
feedback@chauthiduniya.com

शुभ दीपावली, छठ एवं माँ काली पूजा के अवसर पर
सभी बड़हरवा प्रखंडवासियों को हार्दिक शुभकामनाएँ
शैलेन्द्र कुमार लाल
प्रखंड विकास पदाधिकारी, बड़हरवा, साहिबगंज

प्रकाश का पर्व दीपावली एवं छठ की देवघरवासियों को
हार्दिक शुभकामनाएँ
प्राचार्य एवं
समस्त महाविद्यालय परिवार
ए एस महाविद्यालय, देवघर

देवघर जिले की जनता को दीपावली एवं छठ की
हार्दिक शुभकामनाएँ
दिलीप कुमार सिंह
अधिवक्ता
जिलाध्यक्ष, बुद्धिजीवी मंच,
झारखंड विकास मोर्चा, देवघर

देवघरवासियों एवं स्कूल के सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों व कर्मचारियों को दीपावली एवं छठ की
ढेर सारी शुभकामनाएँ
युद्धिष्ठिर प्रसाद राय
सचिव
रेड रोज स्कूल, देवघर

स्कूल के सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों, कर्मचारियों एवं शहरवासियों को दीपावली एवं छठ की
मंगलकामनाएँ
प्राचार्य
देवघर सेंट्रल स्कूल, देवघर

झारखंडवासियों, उद्यमियों व व्यावसायियों को दीपावली एवं छठ की
हार्दिक शुभकामनाएँ
वैद्यनाथ पोलिट्यूब प्राइवेट लिमिटेड, देवघर

साहिबगंज जिलेवासियों को दीपावली एवं छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएँ
एस सी डी विद्यालय
वर्ग नर्सरी से कक्षा आठ तक
मिर्जाचौकी, साहिबगंज
कार्यकारी निदेशक
डा राजीव रंजन झा

प्राचार्या
रचना झा

प्रकाश का अंधकार पर विजय का पर्व दीपावली एवं छठ पर्व पर सभी मिर्जाचौकी वासियों को शुभकामनाएँ

महेश्वर प्रसाद रंजन
थाना प्रभारी,
मिर्जाचौकी साहिबगंज

प्रकाश का पर्व दीपावली पर सभी प्रखंडवासियों को
हार्दिक शुभकामनाएँ
अरुण सिंह

प्रखंड सचिव, झामुमो मंडरो, साहिबगंज

माँ काली पूजा, दीपावली एवं छठ पर्व के अवसर पर सभी मिर्जाचौकीवासियों को
हार्दिक शुभकामनाएँ
आयुष इन्टरप्राईजेज
मिर्जाचौकी, साहिबगंज
प्रोपराईटर....बबलू मिश्रा

दीपावली एवं छठ पर्व पर सभी प्रखंडवासियों को
हार्दिक शुभकामनाएँ
मनोज कुमार दुबे
सामाजिक कार्यकर्ता, मिर्जाचौकी, साहिबगंज

चौथी दुनिया
दिल्ली, 19–25 अक्टूबर 2009

उस कृषि अनुसंधान का क्या फ़ायदा जिसका किसानों को लाभ ही न मिले. बिहार के राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में उन्नत बीज और तकनीक के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुसंधान तो किए गए, लेकिन किसानों तक वह पहुंच ही नहीं पाया.

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. 45843/86

बेतिया के महाफ़िज़खाने में कई ऐतिहासिक राज़ छिपे हैं

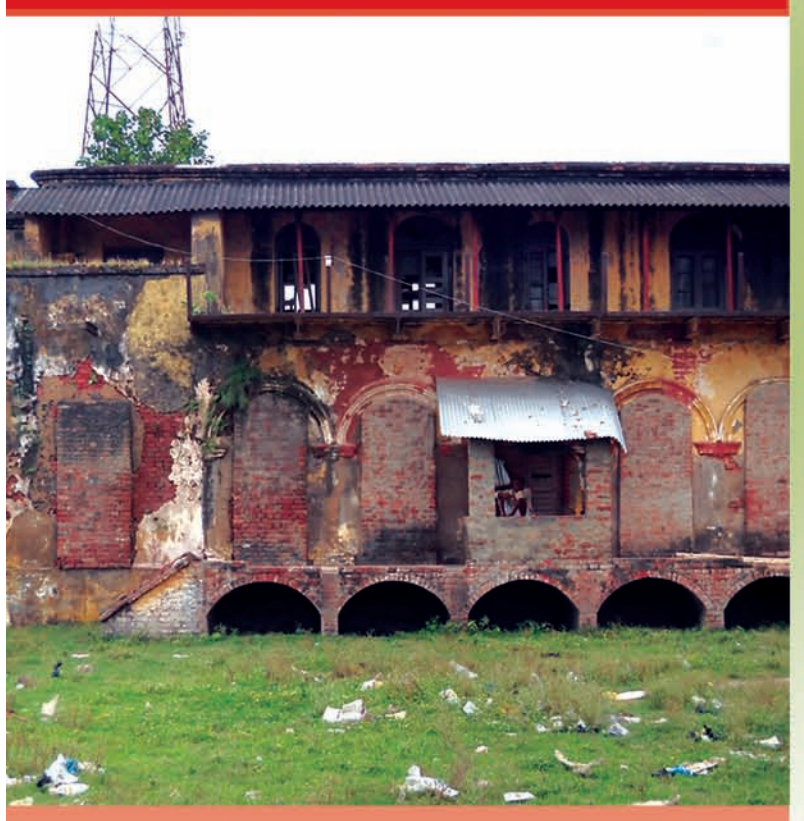

मनोज कुमार राव

बेतिया राजघराना तो अब रहा नहीं, लेकिन उससे जुड़ी यादों के प्रति भी सरकारी तंत्र लापरवाह हो जाए तो ज़ाहिर है कि पूरी दुनिया में हमारे प्राचीन धरोहरों का मज़ाक ही उड़ेगा. बेतिया राज के कुछ ऐसे ही अवशेष आज सरकारी संरक्षण का इंतज़ार कर रहे हैं. पश्चिमी चंपारण के ज़िला मुख्यालय बेतिया स्थित राजड्योढ़ी आज बस एक जर्जर मकान भर है, लेकिन इतिहास के पन्नों में इसका नाम महाफ़िज़खाना दर्ज़ है. इसमें सैकड़ों बस्त सहेजकर रखे गए हैं, जिनमें कई दस्तावेज़ों में समकालीन इतिहास, समाज, विदेशी संबंध, धर्म, अर्थव्यवस्था और नागरिक जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं. अस्सी के दशक में हावर्ड विश्वविद्यालय के एक स्कॉलर एडवर्ड भारत आए थे, जिन्होंने तत्कालीन मंत्री विजय शंकर दूबे से इजाज़त लेकर महाफ़िज़खाना के बंद पड़े दरवाज़ों को खुलवाया था. पूरे भवन में लाल कपड़े से बांधकर रखे गए सैकड़ों बस्तों की दुर्दशा देखकर एडवर्ड तब आश्चर्य में डूब गए थे और उन्होंने शासन–प्रशासन के अधिकरियों को पत्र लिखकर इस दुर्दशा की जानकारी भी दी थी, लेकिन इसके बावजूद कहीं कुछ नहीं हुआ.

जिन प्राचीन धरोहरों की दुर्दशा को लेकर हमारे नेता और प्रशासनिक अधिकारी इतने उदासीन हैं, उसके प्रति विदेशी स्कॉलरों की बेचैनी और जिज्ञासा वाकई एक सबक है.

बेतिया राज स्थित इस महाफ़िज़खाना के सैकड़ों बस्तों को अगर सरकारी पहल करके संजोया जाए अथवा उसके तथ्यों को समझा जाए तो कई राज़ सामने आ सकते हैं. यहां हर बस्त में कई राज़ छिपे हैं. दस्तावेज़ के रूप में इसमें अंग्रेजों के ज़ुल्मोसितम की दास्तां क़ैद है. रैयतवाड़ी व महलवाड़ी मालगुज़ारी व्यवस्था से पीड़ित भारतीय किसानों की सिसकियां भी इसमें सुनी जा सकती हैं. नील की खेती से चरमराती भारतीय आर्थिक व्यवस्था के दर्द को भी इसमें महसूस किया जा सकता है.

दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक में जिस ड्रेन थ्योरी के बारे में प्रकाश डाला है, उससे जुड़े कई तथ्य बस्त के अध्ययन से सार्वजनिक हो सकते हैं. इससे यह भी मालूम हो सकता है कि राजघरानों के पैसे बड़ी आसानी से ब्रिटेन कैसे पहुंच जाते थे और उन पैसों से वायसराय से लेकर दूसरे फिरंगी अधिकारियों तक की मौज हुआ करती थी.

दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक में जिस ड्रेन थ्योरी के बारे में प्रकाश डाला है, उससे जुड़े कई तथ्य बस्त के अध्ययन से सार्वजनिक हो सकते हैं. इससे यह भी मालूम हो सकता है कि राजघरानों के पैसे बड़ी आसानी से ब्रिटेन कैसे पहुंच जाते थे और उन पैसों से वायसराय से लेकर दूसरे फिरंगी अधिकारियों तक की मौज हुआ करती थी. इन दस्तावेज़ों से संभवतः इन ऐतिहासिक तथ्यों की भी जानकारी मिल सकती है कि किन परिस्थितियों में बुद्ध और जैन काल की सामाजिक संरचनाओं में ब्राह्मणों का स्थान राजपूतों ने ले लिया था. क्या वजह थी कि गौतम बुद्ध ने चंपारण में धर्म प्रचार के लिए जगह–जगह पर बौद्ध स्तूप लगवाए और कैसे धर्म महामात्रों की नियुक्ति धर्म प्रचार के लिए की गई.

बस्त के दस्तावेज़ों में बेतिया राज और समकालीन राजघरानों के आपसी संबंध, कूटनीति और युद्ध के ब्योरों की फ़ेहरिस्त क़ैद है. इन बस्तों को सहेजने का काम कई सालों से बंद पड़ा है. न कोई राजनेता इसके प्रति जागरूक है और न कोई ही इसके प्रति फिक्रमंद है. शायद इन्हीं रोचक तथ्यों की जानकारी को सहेजने के लिए आस्ट्रेलिया के हावर्ड विश्वविद्यालय के स्कॉलर बेतिया आए थे. अगर समय रहते इनकी देखभाल न की गई और इन ऐतिहासिक पन्नों को सहेजा न गया तो वह दिन दूर नहीं, जब बस्त में छिपे राज़ हमेशा के लिए राज़ ही रह जाएंगे.

feedback@chauthiduniya.com

खगड़िया: मौत की पटरी पर दौड़ती ट्रेन

फोटो – पीटीआई

अमृतसर से आम्रपाली एक्सप्रेस पर सवार होकर कटिहार जा रहे पूर्णियां के पूरण सिंह को क्या पता था कि जिस ट्रेन से वह सफर पर निकला है वह बीच रास्ते में ही मौत की पटरी पर दौड़ जाएगी और अचानक उसकी जिंदगी की रफ़्तार थम जाएगी. दरअसल सात अक्टूबर की देर रात बरौनी–कटिहार रेलखंड के पसराहा–गौछाड़ी स्टेशन के बीच अमृतसर–कटिहार आम्रपाली एक्सप्रेस जैसे ही धंसान क्षेत्र से होकर गुज़रा कि ज़ोर का धमाका हुआ. इससे पहले कि आम्रपाली में सवार लोग कुछ समझ पाते, इंजन सहित सात डब्बे पटरी से उतर चुके थे. फिर तो लोगों की चीख–पुकार मच गई. 22 वर्षीय पूरण दूसरे यात्रियों की तरह ख़ुशकिस्मत नहीं रहा. उसकी मौत हो गई. इस दुर्घटना में 50 से भी ज़्यादा यात्री ज़ख्मी हो गए. दुर्घटना के वक़्त ट्रेन की रफ़्तार बेहद कम थी वरना हताहतों की संख्या कितनी होती, इसका अंदाज कर पाना भी मुश्किल है. जिस वक़्त ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई, ज़्यादातर मुसाफिर गहरी नींद में थे. यात्रियों को ट्रेन के दुर्घटनाग्रस्त होने का जब अहसास हुआ तब ट्रेन से बाहर निकल पाना भी उनके लिए मुश्किल था. हादसे के बाद रेल अधिकारियों ने रटे–रटाए शब्दों में कह दिया कि लगातार हो रही बारिश के कारण पटरी के नीचे की मिट्टी धंस गई और ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई. वैसे हादसे का मुख्य कारण क्या था यह तो जांच के बाद ही स्पष्ट कहा जा सकता है. जितनी आसानी से रेल अधिकारियों के द्वारा इस तरह की बातें कही गईं, उतनी आसानी से इस तरह की बातें लोगों के गले इसीलिए नहीं उतर पा रही है, क्योंकि यह अकेला ऐसा इलाक़ा नहीं है, जहां सात अक्टूबर को भीषण बारिश हुई थी. बिहार का शायद ही ऐसा कोई इलाक़ा बचा था, जहां सात अक्टूबर को बारिश न हुई हो.

रेल अधिकारियों द्वारा भीषण बारिश को दुर्घटना के कारण बताना अपनी कमज़ोरी और लापरवाही छिपाने के अलावा कुछ नहीं है. ग़ौर करने वाली बात यह है कि सात अक्तूबर को तक़रीबन पूरे बिहार में बारिश हुई थी, न कि सिर्फ़ दुर्घटना वाले इलाक़े में. वैसे भी यह इलाक़ा धंसान क्षेत्र की श्रेणी में रखा गया है, तो फिर यहां रेल पटरियों के समुचित रख–रखाव की व्यवस्था क्यों नहीं की जाती है? पिछले माह भी कई दिनों तक इस स्थल पर मरम्मत का कार्य कराया गया था. कई दिनों तक सभी ट्रेनें स्थगित रही थीं. 30 सितंबर से परिचालन फिर से शुरू किया गया. बावजूद इसके यह हादसा हुआ तो इसके पीछे कहीं न कहीं मुख्य वजह लापरवाही ही कही जा सकती है. जानकारों का तो यहां तक कहना है कि इस घटना की वजह निश्चित तौर पर रेल अधिकारियों की लापरवाही ही रही है. ग़ौरतलब है कि घटनास्थल पर बीते तीन–चार दिनों से रेल पटरी के नीचे दरार देखी गई थी. बावजूद इसके रेलों का परिचालन जारी रखा गया. अगर रेल का परिचालन रोक कर मरम्मत कर दिया गया होता तो शायद यह हादसा होता ही नहीं और तब लोगों को मौत के मुंह में जाने या घायल होने से बचाया भी जा सकता था.

राजेश सिन्हा
feedback@chauthiduniya.com

नक्सलियों के फ़रमान से विकास ठप है

झारखंड में विकास कार्यों पर नक्सलियों का फ़रमान भारी पड़ रहा है. सड़कों के निर्माण में नक्सलियों के दख़ल के कारण कई बड़ी सड़क निर्माण परियोजनाओं का भविष्य अधर में लटक गया है. करोड़ों रुपये की लागत से प्रस्तावित इन सड़कों का निर्माण पूरा होगा कि नहीं और होगा तो कब तक, इसका जवाब न तो विभाग के पास है और न ही सरकार के पास. हां, इसका जवाब उन नक्सलियों के पास अवश्य है, जिन्होंने सड़क निर्माण के एवज में लेवी की मांग की है.

राज्य में क़रीब एक अरब रुपये की लागत से बननेवाली सड़कों, पुल–पुलियों का निर्माण नक्सलियों ने रोक रखा है. पलामू, गढ़वा लातेहार, चतरा और गिरिडीह की कई योजनाओं का काम अरसे से बंद है. नक्सलियों के डर से इंजीनियर और ठेकेदार कार्यस्थल पर जाना नहीं चाह रहे हैं. करोड़ों रुपये की कई योजनाएं तो पांच वर्ष से अधिक समय से इसलिए रूकी हुई हैं, क्योंकि नक्सलियों ने निर्माण के लिए हरी झंडी नहीं दी है. सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के मुताबिक़ करोड़ों रुपये की लागत से बननेवाले 14 पुलों का निर्माण नक्सलियों के डर से रुका हुआ है. चतरा की द्वारी नदी पुल का निर्माण कार्य एक साल पहले रोका गया. पुल का निर्माण वित्तीय वर्ष 2004–05 की योजना के तहत विशेष प्रमंडल द्वारा कराया जा रहा है. क़रीब 80 प्रतिशत काम हो चुका है. लातेहार के मनिका में क़रीब पांच वर्ष पहले 18 करोड़ रुपये की लागत से दो सड़कों का निर्माण शुरू हुआ था. एक बार बंद होने के बाद आज भी इसका निर्माण बंद ही है. राज्य में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बननेवाले 14 पुलों का काम भी नक्सलियों के डर से रूकवा दिया गया है. राज्य में राष्ट्रपति शासन होने के बावजूद पलामू, गुमला, लातेहार, हजारीबाग, चतरा और गिरिडीह ज़िलों के दो दर्ज़न से भी अधिक सड़कों और पुलों का निर्माण नक्सलियों के डर से रूका हुआ है.

दरअसल नक्सलियों के ख़िलाफ़ किसी ठोस नीति के अभाव में पुलिस और प्रशासन भी कुछ करने में अपने को असहाय पाता है. पुलिस बल को आधुनिक बनाने की बात हो या फिर नक्सलियों के ख़िलाफ़ कठोर कार्रवाई करने की बात, इन सब पर किसी का ध्यान नहीं है. किसी बड़ी घटना के बाद हाय–तौबा मचती है पर कुछ दिनों बाद सब पुराने ढर्रे पर लौट आता है.

अनीता
feedback@chauthiduniya.com

बंद पड़ी निर्माण परियोजनाएं	लागत (रुपये में)
चतरा की गिद्धोर–गंगापुर–मारंगी सड़क योजना	एक करोड़
गुमला के चैनपुर में अपर शंख जलाशय का निर्माण	25 करोड़
गढ़वा–चुनिया मार्ग	साढे चार करोड़
पलामू के चैनपुर में कुट्टी मोड़ से रामगढ़ की सड़क	एक करोड़
मनिका का लंका–कोपे मार्ग	नौ करोड़
लातेहार–सरयू–गारू पथ	19 करोड़
तुबद नदी पर पुल निर्माण	एक करोड़
चुरचू में नानो मोड़ से आंगो तक की सड़क परियोजना	दो करोड
लोहरदगा और गुमला को जोड़ने वाली कोयल नदी पर पुल	दो करोड़
चतरा की इटखोरी–पिंडारकोत सड़क	एक करोड़

किसानों को कृषि अनुसंधान का लाभ नहीं मिल पा रहा है

कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा के खाते में उपलब्धियों की कोई कमी नहीं हैं. ऐसे मौके कई बार आए जब न केवल देश, बल्कि विदेशों में भी इस विश्वविद्यालय के नाम का डंका बजा, लेकिन ज़्यादातर मामलों में कमज़ोर सूचना तंत्र के कारण इसकी उपलब्धियों से दुनिया अवगत ही नहीं हो पाती है. और यही वजह है कि किसानों को इसका समुचित लाभ नहीं मिल पाता है. खेती–बाड़ी के लिए विकसित उन्नत बीज व ज़्यादा पैदावार के लिए अपनाई जाने वाली वैज्ञानिक तकनीकों से यहां के किसान परिचित हों, इसके लिए समुचित व्यवस्था यहां है ही नहीं.

हालांकि कुलपति डॉ. मेवालाल चौधरी ने पदभार संभालने के बाद इस कमी को भांपा और सूचना तंत्र को शीघ्र ही चुस्त–दुरुस्त बनाने का वादा भी किया, बावजूद इसके समस्या आज भी जस की तस है. इस कारण सूबे का इकलौता कृषि विश्वविद्यालय किसानों और आम लोगों तक अपनी उपलब्धियों और कृषि की उन्नत तकनीकों को पहुंचाने में नाकाम हो रहा है. राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से इस विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्ज़ा देने का अनुरोध किया है. अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन को भी सूचना उपलब्ध

सूचनाओं, उपलब्धियों एवं नवीनतम कृषि तकनीक के प्रचार प्रसार में विश्वविद्यालय कहीं से भी विफल नहीं है. सभी जानकारियां एवं सूचनाएं हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं. हमारे सूचना अधिकारी स्थानीय समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं के माध्यम से भी लोगों तक महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध करवा रहे हैं.

–मेवा लाल चौधरी
कुलपति
राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा

कराने वाले तंत्र को सुदृढ़ करने की ओर ध्यान देना चाहिए. लोगों, ख़ासकर ग्रामीण जनता से व्यापक पैमाने पर जुड़े बिना यह विश्वविद्यालय किस तरह केंद्रीय विश्वविद्यालय का स्वरूप लेगा, इस बारे में ज़्यादा बेहतर तो विश्वविद्यालय प्रशासन एवं सरकार ही बता सकती है. राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा राज्य का इकलौता कृषि विश्वविद्यालय है. उन्नत किस्म के बीज के साथ–साथ विश्वविद्यालय ने कई महत्वपूर्ण तकनीकें विकसित की हैं और अनुसंधानों के सफल परीक्षण भी किए गए हैं. विश्वविद्यालय में आज भी शोध एवं परीक्षण की प्रक्रिया जारी है और इसके नतीजे भी उत्साहवर्द्धक रहे हैं, लेकिन फ़ायदा किसानों को न मिलना दुख की बात है. हालांकि विश्वविद्यालय में सूचना उपलब्ध कराने के लिए सूचना अधिकारी का पद है, लेकिन यह केवल नाम मात्र का है. विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों और सूचना तंत्र के बीच बेहतर तालमेल न होने के कारण सूचना पदाधिकारी के पास सूचनाएं पहुंच नहीं पाती हैं. नतीजतन मीडियाकर्मियों को भी कृषि से संबंधित सूचनाओं के लिए भारी मशक़्क़त करनी पड़ती है. ज़िले के नयानगर ग्राम पंचायत (हसनपुर प्रखंड) के मुखिया व किसानश्री से सम्मानित प्रगतिशील कृषक सुधांशु कुमार एवं रोसड़ा के सुरेंद्र नारायण सिंह लालन रेडियो एवं दूरदर्शन पर कृषि आधारित उपयोगी जानकारियों के नियमित प्रसारण की वकालत करते हैं. ऐसी एक योजना विश्वविद्यालय में लंबित पड़ी है, जिसके तहत कृषि विज्ञान केंद्र, बिरौली में एक आधुनिक रेडियो केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव है. इस केंद्र से नियमित रूप से कृषि आधारित जानकारियों के प्रसारण की योजना है. विश्वविद्यालय सूत्रों के मुताबिक़ योजना से संबंधित राशि उपलब्ध होने के बावजूद यह प्रस्ताव अभी ठंडे बस्ते में पड़ा है.

समग्र रूप से यह कहा जा सकता है कि विश्वविद्यालय जब तक अपने सूचना तंत्र को दुरुस्त नहीं करता है तब तक वह अपने उद्देश्यों में कामयाब नहीं हो सकता. कृषि आधारित अनुसंधानों, तकनीकों आदि को जब तक किसानों की प्रयोगशाला यानी खेत–खलिहान तक नहीं पहुंचाया जाता, तब तक इसका कोई औचित्य नहीं है. नवीनतम अनुसंधानों को केवल विश्वविद्यालय की रिसर्च काउंसिल से पास करा लेना ही काफी नहीं...! इसे किसानों की खेत तक ले जाने की ज़रूरत है.

विभूति कुमार
feedback@chauthiduniya.com